• वर्ष-3
• अंक-111
रायपुर, रविवार
17 दिसंबर 2023
• पृष्ठ-8
• मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› रोहित निर्देशित फिल्म में सिद्धार्थ ...

लोकसभा की सुरक्षा में सेंध
मामले की जांच समिति करेगी

नई दिल्ली। लोकसभा की सुरक्षा में सेंध लगने का मामला लगातार सुर्खियों में हैं। संसद के दोनों सदनों में हंगामा होने के कारण कार्यवाही भी बाधित हुई। विपक्षी दल गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी से संसद में जवाब देने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों को पत्र लिखा है। उन्होंने उच्चस्तरीय समिति के गठन की बात कही है।

सांसदों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया

हंगामे के कारण बाधित हुई दोनों सदनों की कार्यवाही को लेकर लोकसभा स्पीकर ने चिंता जताई। उन्होंने सांसदों से कहा कि सदन को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना अपेक्षित है। ओम बिरला ने कहा कि संसदीय परिसर की सुरक्षा के लिए उन्होंने खुद एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया है। बिरला ने कहा कि यह समिति पूरे संसद कॉम्प्लेक्स की सुरक्षा से जुड़े अलग-अलग पहलुओं की समीक्षा करेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि समिति ऐसे ठोस उपाय और योजना तैयार करेगी जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं दोहराई न जा सकें।

भाजपा सांसद पर कार्रवाई की मांग

बता दें कि बीते 13 दिसंबर को संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी थी। इसी दिन दोपहर करीब एक बजे दो लोग दर्शक दीर्घा से अचानक संसद में कूद पड़े। इस मामले में कर्नाटक से निर्वाचित भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा का नाम भी चर्चा में है। विजिटर पास पर प्रताप सिम्हा का नाम लिखा होने के कारण विपक्षी सांसद उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

आतंकी हमले की 22वीं बरसी के दिन सुरक्षा में सेंध

संसद की कार्यवाही के दौरान सुरक्षा में गंभीर चूक के इस मामले में 13 दिसंबर को भी जोरदार हंगामा हुआ था। अगले दिन विपक्षी दलों ने पीएम मोदी या गृह मंत्री शाह से बयान की मांग को लेकर भी हंगामा किया। अशोभनीय आचरण के आरोप में विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया है। विपक्षी पार्टियां सरकार पर आवाज दबाने और जवाबदेही से भागने के आरोप लगा रही हैं।

विकसित भारत में छोटे शहर की अहम भूमिका: मोदी

विकसित भारत संकल्प यात्रा सरकार का एक बड़ा जनसंपर्क कार्यक्रम

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में सैकड़ों छोटे शहरों की अहम भूमिका है और उनकी सरकार जीवनयापन को आसान बनाने के लिए ऐसे शहरी केंद्रों में बुनियादी सुविधाओं को उन्नत कर रही है। देश में जारी 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' के दौरान केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार उन शहरी परिवारों के लिए पैसा बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिन्हें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा और सभी के लिए आवास जैसी पहलों से लाभ हुआ है। 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' सरकार का एक बड़ा जनसंपर्क कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य केंद्रीय पहलों के दायरे के तहत सभी लाभार्थियों को लाना है। मोदी ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए कहा, ''हमारा एजेंडा पैसे बचाने में लोगों की सहायता करना है।''

यह यात्रा राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में शुरू की गयी, जहां विधानसभा चुनाव के लिए लागू आदर्श आचार संहिता के कारण इसे पिछले महीने शुरू नहीं किया जा सका था। यह यात्रा 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी में शुरू की गई थी और हजारों गांवों और 1,500 शहरों के 2.5 करोड़ लोगों तक पहुंच चुकी है। मोदी ने कहा, ''मुझे यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ गांवों के हर गरीब व्यक्ति और शहरों की झुग्गी-झोपड़ी वाली हर बस्ती तक पहुंचे और उन्हें बिना किसी कठिनाई के लाभ मिले। यही कारण है कि मोदी की गारंटी की वैन चारों ओर घूम रही है। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को हासिल करने में शहरों की बहुत बड़ी भूमिका है और उस समय देश आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा। उन्होंने कहा, ''आजादी के बाद लंबे समय तक जो विकास हुआ, उसका दायरा देश के कुछ बड़े शहरों तक ही सीमित था। लेकिन आज हम टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।''

मोदी ने कहा कि देश के सैकड़ों छोटे शहर विकसित भारत की भव्य इमारत को मजबूत करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 'अमृत मिशन' और 'स्मार्ट सिटी मिशन' जैसी पहल छोटे शहरों में बुनियादी सुविधाओं को उन्नत कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने मुंबई, लखनऊ, शिमला के पास रोहड़ू, कोझिकोड और गुवाहाटी के रहने वाले विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री ने लोगों से सरकार की पेंशन योजनाओं में नामांकन कराने और खुद को सुरक्षित करने का आग्रह किया और लोगों से यात्रा के हिस्से के रूप में देशभर में घूमने वाली 'जनसंपर्क वैन' को समर्थन देने के लिए कहा।

प्रधानमंत्री ने कहा, जब दूसरों से उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तब 'मोदी की गारंटी शुरू' होती है। उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक लोगों ने 'पीएम स्वनिधि योजना' के तहत बैंक सहायता का लाभ उठाया है, इस यात्रा के दौरान 1.25 लाख लोगों ने योजना के लिए आवेदन किया है। मोदी ने कहा कि छह करोड़ लोगों ने अटल पेंशन योजना की सदस्यता ली है जो 60 साल की उम्र के बाद 5,000 रुपये मासिक पेंशन सुनिश्चित करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 'पीएम सुरक्षा बीमा योजना' और 'जीवन ज्योति योजना' के तहत 17,000 करोड़ रुपये के दावों का निपटान किया गया है।

भविष्य का भारत बनाने के लिए युवाओं की बात सुननी होगी: शाह

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि भारत को विकसित बनाने के लिए युवाओं की बात सुननी होगी, उनकी पसंद को समझना होगा, उनकी आकांक्षाएं कार्य योजना में शामिल करनी होंगी और उनकी शक्ति पर विश्वास करना होगा। गुजरात के आणंद में सरदार पटेल विश्वविद्यालय के 66वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस समझ के साथ कई योजनाएं लेकर आए कि केवल युवा ही भविष्य का भारत बना सकते हैं। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल को याद करते हुए, शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 को निरस्त करना उनको एक श्रद्धांजलि थी।

कोविड मामलों में वृद्धि: केरल में मिला सब-वेरिएंट जेएन1 का मामला

नई दिल्ली। तमिलनाडु सरकार पड़ोसी राज्य केरल और सिंगापुर में कोरोना के मामलों में हालिया वृद्धि को देखते हुए नए प्रकोप से निपटने के लिए सभी सावधानियां बरत रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मा सुब्रमण्यम ने शनिवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को वायरस के प्रसार को रोकने के लिए उचित कदम उठाने के लिए कहा गया है। उन्हें किसी भी विशेष क्षेत्र में बुखार के मामलों में वृद्धि होने पर आरटी-पीसीआर परीक्षण करने के लिए सतर्क किया गया है। उनकी यह टिप्पणी पड़ोसी राज्य केरल और सिंगापुर में भी संक्रमण के मामले बढ़ने के बीच आई है।

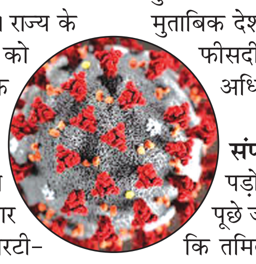

तमिलनाडु और केरल में कोरोना के कितने सक्रिय मामले- केंद्र सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध कोविड आंकड़ों के मुताबिक, 15 सितंबर तक तमिलनाडु में 98.94 फीसदी के डिस्चार्ज अनुपात के साथ 36 सक्रिय मामले हैं। इसके मुताबिक देश के सभी राज्यों में केरल में 98.94 फीसदी के डिस्चार्ज अनुपात के साथ सबसे अधिक 1,144 सक्रिय मामले हैं।

केरल में अपने समकक्षों के संपर्क में तमिलनाडु के अधिकारी- पड़ोसी राज्य में बढ़ते मामलों के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने यहां पत्रकारों से कहा कि तमिलनाडु के स्वास्थ्य अधिकारी केरल में अपने समकक्षों के संपर्क में हैं और वे विकास की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जब मैंने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से संपर्क किया, तो मुझे बताया गया कि यह संक्रमण हल्का है और यह तीन या चार दिनों तक चला। केरल में भी ऐसा ही है।

स्थिति की निगरानी कर रहा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय

वहीं, केंद्र सरकार ने कहा कि आईएनएसएसीओजी द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। केरल में कोविड के एक सब-वेरिएंट जेएन.1 का एक मामला पाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सार्वजनिक स्वास्थ्य और अस्पताल की तैयारियों का आकलन करने के लिए राज्य में सभी स्वास्थ्य सुविधाओं में मॉक ड्रिल कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों के संपर्क में है और स्थिति की निगरानी कर रहा है।

राहुल के बयान पर लोग हंसते हैं..., हरदीप पुरी का कांग्रेस नेता पर पलटवार

नई दिल्ली। संसद की सुरक्षा में चूक के मामले ने सियासी माहौल गरम कर दिया है। विपक्षी दल सरकार से इस मामले में पर बयान की मांग कर रहे हैं। वहीं, सत्तारूढ़ पार्टी के नेता विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। पुरी ने कहा, %राहुल गांधी एक ऐसे युवा नेता हैं जो कई बातें बोलते हैं। उनकी पार्टी की विचारधारा से जुड़े लोग संसद में (विजिटर गैलरी से नीचे) कूद पड़े और वह कहते हैं कि इसका कारण बेरोजगारी है... वह बयान देते हैं और लोग हंसते हैं। दरअसल, संसद की सुरक्षा में सेंध के बारे में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा था, यह क्यों हुआ है?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पांच राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के कोने कोने में पहुंच रही है। यात्रा को शुरू हुए एक महीना हो चुका है। यात्रा हजारों गांवों के साथ डेढ़ हजार शहरों में भी पहुंच चुकी है। इनमें से अधिकतर छोटे-छोटे कस्बे हैं। आज छत्तीसगढ़ से भी यात्रा का शुभारंभ हो गया है। (विस्तृत समाचार पृष्ठ 8 पर)

प्रमुख समाचार

नेता प्रतिपक्ष बनाए गए चरणदास महंत बोले- विपक्ष की सशक्त भूमिका निभाएगी कांग्रेस

रायपुर. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने डॉ. चरणदास महंत को छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए नेता प्रतिपक्ष बनाया है। जिसका पत्र संगठन के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जारी किया है. डॉ. महंत ने नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर कांग्रेस के यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित छग विधानसभा के निर्वाचित कांग्रेस के सदस्यों के प्रति आभार जताया है. साथ ही विपक्ष की सशक्त भूमिका निभाने की बात भी कही है. सक्ती विधायक डॉ. चरणदास महंत को छग विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर प्रदेशभर के कांग्रेसियों सहित कोरबा लोकसभा और सक्ती विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने हर्ष का माहौल है.

मप्र: जीतू पटवारी बने प्रदेश अध्यक्ष, सिंघार नेता-प्रतिपक्ष

भोपाल। पूर्व मंत्री और राहुल गांधी के नजदीकी माने जाने वाले जीतू पटवारी को मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया है। वे कमलनाथ की जगह लेंगे। वहीं सदन में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अब आदिवासी नेता और विधायक उमंग सिंघार संभालेंगे। जीतू पटवारी को आलाकमान और दिग्विजय सिंह के करीब होने का फायदा मिला। बता दें कि मध्यप्रदेश में कांग्रेस की करारी हार के बाद से ही प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव की बात कही जा रही थी। अब कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हुआ है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे कमलनाथ की जगह अब कमान जीतू पटवारी को सौंपी गई है। बता दें, जीतू पटवारी विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। उन्हें राऊ विधानसभा से भाजपा के मधु वर्मा ने हराया था। उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। उनका नाम काफी समय से चर्चा में था। उन्हें जिम्मेदारी देकर कांग्रेस ने आदिवासियों को भी साधा है। वहीं हेमंत कटारे को उप नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। बता दें कि इन नियुक्तियों से पता चलता है कि कांग्रेस का अब भी मालवा निमाड़ पर फोकस है।

22 जनवरी को अयोध्या नहीं आएं: चंपत राय

नई दिल्ली। अगले साल 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने वाला है. भगवान राम की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित होता देखने के लिए लाखों तीर्थयात्रियों के अयोध्या आने की उम्मीद है. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने आज राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि समारोह 22 जनवरी को दोपहर 12 बजे होगा. उन्होंने कहा कि गर्भगृह तैयार है, मूर्ति भी, लेकिन पूरे मंदिर के निर्माण में दो साल और लग सकते हैं. विभिन्न राज्यों के कई लोग इस दौरान अयोध्या जाने की योजना बना रहे हैं. लेकिन राय ने भक्तों को इस दौरान अयोध्या न आने को कहा है. चंपत राय ने लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या आने के बजाय अपने नजदीकी मंदिर में आनंद महोत्सव मनाएं. उन्होंने भक्तों को दिए अपने संदेश में कहा, 22 जनवरी को अयोध्या न आएं. अपने नजदीकी मंदिर में इकट्ठा हों, चाहे वह छोटा हो या बड़ा... जो मंदिर आपके लिए संभव हो, वहां जाएं, भले ही वह आपका हो.. शहर में इस दौरान भीड़भाड़ न हो इसलिए उन्होंने ये आग्रह किया है.

आज 32वें दौरे पर काशी आएंगे पीएम, रहेंगे 25 घंटे

वाराणसी। 32वें दौरे पर रविवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी आएंगे। मोदी रविवार और सोमवार दो दिन अपने संसदीय क्षेत्र में रहेंगे। पहले दिन 17 दिसंबर को काशी यात्रा में पीएम मोदी नदेसर में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। फिर शाम को नमो घाट पर काशी तमिल संगमम का उद्घाटन करेंगे। अगले दिन 18 दिसंबर को पीएम विहंगम योग के सबसे बड़े केंद्र स्वर्वेद महामंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद बरकी में मिशन-2024 का शंखनाद करते हुए जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं काशी संसद खेल प्रतियोगिता 2023 के प्रतिभागियों के कुछ लाइव खेल कार्यक्रमों को देखने के बाद वह कार्यक्रम के विजेताओं के साथ बातचीत करेंगे। तीन राज्यों में भाजपा की जीत के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच रहे पीएम मोदी के एयरपोर्ट से लेकर नदेसर तक 22 किमी रास्ते पर भव्य स्वागत की भी तैयारी की गई है। पीएम मोदी 17 दिसंबर की रात में काशी के विकास को परखने शहर में भ्रमण भी कर सकते हैं। नमो घाट से कन्याकुमारी से वाराणसी की विशेष ट्रेन और बरकी से दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत सहित 5 ट्रेनों का शुभारंभ करेंगे। यहीं से पीएम के हाथों 19150 करोड़ की 37 परियोजनाओं का लोकर्पण और शिलान्यास भी होगा।

चंडीगढ़ की दवा कंपनी के दिल्ली-एनसीआर और पंजाब में करीब दर्जनभर स्थानों पर ईडी की छापेमारी

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मामले में चंडीगढ़ स्थित दवा कंपनी पैराबोलिक ड्रग्स और इसके प्रवर्तकों के खिलाफ धनशोधन जांच के तहत शुक्रवार को दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और पंजाब में लगभग एक दर्जन स्थानों पर छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। इस मामले में कंपनी पैराबोलिक ड्रग्स के खिलाफ अक्टूबर में भी छापे मारे गए थे। उन्होंने बताया कि तलाशी के दौरान एजेंसी के अधिकारियों ने कुछ दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए। केंद्रीय एजेंसी ने पहले पैराबोलिक ड्रग्स के प्रवर्तकों-विनीत गुप्ता (54) और प्रणव गुप्ता (56) तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट सुरजीत कुमार बंसल (74) को धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था। विनीत एवं प्रणव गुप्ता हरियाणा के सोनीपत स्थित अशोक विश्वविद्यालय के सह-संस्थापक भी हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में उन्हें न्यायिक हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा 2021 में 1,626 करोड़ रुपये की बैंक ऋण धोखाधड़ी में कथित संलिप्तता को लेकर उनके और कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

भाजपा ने चार दशक पुराने इंदिरा गांधी के रास्ते का अनुसरण किया

नीलांजन मुखोपाध्याय

भाजपा द्वारा मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति पर 1982 में द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित मशहूर कार्टूनिस्ट आरके लक्ष्मण का एक कार्टून मुझे याद आया। उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हाथ में छाता लिए पारंपरिक राजनीतिक पोशाक पहने कई राजनेताओं के आगे से गुजर रही थीं। जमीन पर पड़े अखबार की हेडलाइन दृश्य को स्पष्ट करती है, जिसमें लिखा है, %आंध्र के सीएम की तलाश जारी है। कार्टून में इंदिरा गांधी को उनमें से किसी एक नेता की ओर उंगली दिखाते और कहते हुए दिखाया गया है कि, %ठीक है, आप...वहां... आप सीएम हैं। आपका नाम क्या है? यह कार्टून तब बनाया गया था, जब इंदिरा गांधी ने आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री के लिए एक खोज अभियान चलाया था।

दरअसल, उस वक्त राजीव गांधी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री टी अंजैया को सार्वजनिक तौर पर इसलिए अपमानित किया था कि उन्होंने हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर कांग्रेस नेता का असाधारण ढंग से स्वागत किया था। उससे राजीव गांधी इतने नाराज हुए कि उन्होंने दिल्ली लौटकर अपनी मां से अंजैया को बर्खास्त करा दिया। उस घटना की वजह से न केवल कांग्रेस ने कम पहचान वाले मुख्यमंत्रियों को नियुक्त करना शुरू किया, बल्कि उससे तेलुगु स्वाभिमान आंदोलन भी शुरू हुआ, जिसमें एनटी रामाराव एक नेता के तौर पर उभरे और आखिरकार 1983 में उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के लिए तेलुगु देशम पार्टी का गठन किया। शीघ्र फैसले लेने के लिए जानी जाने वाली भाजपा ने तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के एलान करने में काफी समय लगाया। आखिरकार जब मुख्यमंत्रियों और उनके दो उप मुख्यमंत्रियों के नाम सामने आए, तो कम ही लोग थे, जिन्होंने कभी मोहन यादव, भजन लाल शर्मा या विष्णु देव साय का नाम सुना था।

टेलीविजन पर यह खबर देखने के बाद गूगल पर इनके नामों की खूब खोज की गई। इनके अलावा, राजेंद्र शुक्ला, जगदीश देवड़ा, दीया कुमारी, प्रेम चंद बैरवा, विजय शर्मा और अरुण साव के नामों के साथ भी यही हुआ, जो सभी इन तीनों राज्यों के अनाम से नेता हैं। हैरत की बात है कि भाजपा ने भी उसी रास्ते का अनुसरण किया है, जो इंदिरा गांधी ने चार दशक पहले चुना था। इतिहास गवाह है कि यह इंदिरा गांधी के सत्तावादी तरीकों की अभिव्यक्ति थी, लेकिन भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने यह कदम उठाकर पार्टी के भीतर कार्यकर्ताओं और आम जनता को क्या संदेश दिया है? इस सवाल का जवाब देने से पहले मुझे एक और घटना याद आती है। बात दरअसल 2014 की है, जब लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी को अपना उम्मीदवार घोषित किया था, जिनकी मेरी लिखी जीवनी उस वक्त काफी चर्चित हुई थी। तब कई पत्रकारों ने इंटरव्यू वगैरह के लिए मुझसे संपर्क भी किया। इनमें से एक पत्रकार ने मुझसे हुई बातचीत के आधार पर अपनी पत्रिका के कवर पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ मेरे नाम के साथ मेरी टिप्पणी प्रकाशित की, कि %मोदी कभी भूलते या माफ नहीं करते।%

नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसी बात कहने वाला मैं अकेला नहीं होऊंगा और दुनिया व भारत में भी ऐसे और भी नेता होंगे, जिनके बारे में यह बात कही जा सकती हो। लेकिन आज जबकि शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे की पारी खत्म हो गई है, मुझे प्रधानमंत्री की यही खूबी याद आ रही है। एक स्तर पर देखें तो यह फैसले बिल्कुल निजी दिखते हैं। यह 2011-12 और 2013 की शुरुआत में भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों की सूची में मोदी को चुनौती देने के चौहान और राजे के फैसले पर मोदी का प्रतिशोध भी हो सकता है। उस वक्त आरएसएस भी असमंजस की स्थिति में था, क्योंकि मोदी के साथ कई शीर्ष नेताओं के व्यक्तिगत मुद्दे सामने आ रहे थे। आखिरकार मोदी प्रधानमंत्री बने और चौहान व राजे 2018 तक अपने राज्यों के मुख्यमंत्री रहे। मार्च, 2020 में चौहान को मुख्यमंत्री के तौर पर वापस लाया गया। वहीं, जब राजस्थान में गहलोत की सरकार गिराने की स्थितियां बन रही थीं, वसुंधरा दूर-दूर ही थीं। हालांकि, मध्य प्रदेश और राजस्थान में करीब दो दशकों तक भाजपा के शीर्ष पर रहे दो नेताओं को दरकिनार करने की वजह केवल निजी मतभेदों को नहीं माना जा सकता।

इसी तरह, रमन सिंह को एक बार फिर छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री नामित न करने का फैसला इसलिए नहीं लिया गया कि वह भाजपा नेतृत्व की पिछली पीढ़ी के चुने गए व्यक्ति थे। उल्लेखनीय है कि इनमें से किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम न घोषित करने का फैसला तब लिया गया, जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा के लिए मुश्किलें और राजस्थान में बराबर की टक्कर बताई जा रही थी। यह दरअसल एक जोखिम था, जो मोदी ने उठाया। इन हालात में मोदी-शाह को तीनों राज्यों में नई पीढ़ी के नेतृत्व को आगे बढ़ाने का अवसर दिखा। तीनों राज्यों में भारी जनादेश मिलने के बावजूद भाजपा नेतृत्व ने अपना फैसला नहीं बदला, तब भी, जब कई नवनिर्वाचित विधायक चौहान और राजे के समर्थन में थे। यह बिल्कुल साफ है कि तीनों राज्यों में मोदी के नेतृत्व को समर्थन देने का जनादेश मिला है। यह भी उल्लेखनीय है कि जिन नेताओं को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री पदों के लिए चुना गया है, उनकी आम जनता या पार्टी के भीतर भी कोई खास पकड़ नहीं है। जाहिर है कि वे मोदी और शाह के आभारी रहेंगे। लेकिन उन्हें चुने जाने के पीछे की वजह सिर्फ उनकी वफादारी नहीं है। इंदिरा गांधी के कार्टून में जैसे नेताओं को चुना गया, वैसे तो हर राजनीतिक दल में होते हैं। इनका चयन उत्तर भारत के जाति संयोजन को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध ढंग से किया गया है और कोशिश यही दिखती है कि ऊंची जातियों समेत ओबीसी, दलित और आदिवासी सभी जाति समूहों और इनके भीतर मौजूद वर्गों को भी खुश किया जाए। तीनों राज्यों में भाजपा के पास बहुमत है। जाहिर है कि सरकार और पार्टी पर नियंत्रण केंद्रीय नेतृत्व का ही होगा। इससे लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार अभियान का बारीकी से प्रबंधन करना मोदी-शाह के लिए सुविधाजनक हो जाएगा। इसके विपरीत कांग्रेस ने पुरानी पीढ़ी को बदलने और नए चेहरों को आगे बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया, जो चुनावी रण में उत्साह से कूद सकें। जबकि मोदी और शाह ने अपनी राजनीतिक चतुराई से नए नेतृत्व को उभरने का अवसर देकर अपने फायदे के लिए बदलाव लाने के अपने संकल्प का भी प्रदर्शन किया।

बीजापुर में सुरक्षाबलों को मिली सफलता, मुठभेड़ के बाद किया नक्सलियों का कैंप ध्वस्त

बीजापुर। छत्तीसगढ़ के माओवादी प्रभावित बस्तर संभाग में नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए चलाए जा रहे अभियान में शनिवार को बीजापुर में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। मिली जानकारी के शनिवार को पुलिस ने पेद्दाकोरमा के जंगल में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ के बाद उनका कैंप नष्ट कर दिया है।

बताया जा रहा है कि नक्सलियों के कैंप से भारी मात्रा में विस्फोटक, दवाईयां, नक्सली वर्दी, प्रतिबंधित नक्सल संगठन के प्रचार प्रसार संबंधी सामग्री, नक्सली साहित्य और अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री मिली है। घटना के संबंध में साझा की गई जानकारी के मुताबिक नक्सली कमांडर और गंगालूर एरिया कमेटी के सचिव दिनेश मोड़ियम, गंगालूर एलओएस कमांडर दुला कारम, गंगालूर एरिया आरपीसी कमलू पूनेम समेत 15 से 20 अन्य सशस्त्र नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर सुरक्षाबल नक्सल विरोधी अभियान के लिए निकले थे।

रोहित को कप्तानी से हटाना मुंबई को पड़ा भारी, रातोंरात इतने लाख फैन्स ने इन्स्टाग्राम पर किया उनफॉलोरोहित को कप्तानी से हटाना मुंबई को पड़ा भारी, रातोंरात इतने लाख फैन्स ने इन्स्टाग्राम पर किया उनफॉलो

इसी दरमियान डीआरजी, बस्तर फाइटर, एसटीएफ और कोबरा 202, 210 के जवानों के साथ पेद्दाकोरमा के जंगलों में नक्सलियों से आमना-सामना हुआ। सुरक्षा बल को भारी पड़ता देख नक्सली भाग खड़े हुए। जवानों को

सर्चिंग के दौरान मौके पर नक्सली कैंप मिला, जिसे ध्वस्त किया गया।

शनिवार सुबह करीब छह बजे नक?सली इस कैंप से छिपकर हिंसक घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। जवानों ने इस नक्सली कैंप से नक्सलियों के कई सामान जप्त किए हैं, जिसमें भारी मात्रा में विस्फोटक, दवाईयां, नक्सली वर्दी, प्रतिबंधित नक्सल संगठन के प्रचार-प्रसार की सामग्री, नक्सली साहित्य और अन्य दैनिक इस्तेमाल की सामग्री शामिल है।

जवानों को बड़ी कामयाबी, आईईडी ब्लास्ट में शामिल 4 नक्सलियों को किया गिरफ्तार

कांकेर। जिला पुलिस बल और बीएसएफ की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। जवानों ने आईईडी ब्लास्ट में शामिल 4 जनमिलिशिया सदस्यों को गिरफ्तार किया है। परतापुर सड़कटोला में 14 दिसंबर को आरोपियों ने आईईडी ब्लास्ट किया गया था। आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से बीएसएफ जवान अखिलेश कुमार राय शहीद हुए थे। सभी नक्सलियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है।

कांकेर एसपी दिव्यांग पटेल ने बताया कि परतापुर सड़कटोला में हुए आईईडी ब्लास्ट में शामिल सक्रिय नक्सली जन मिलिशिया मुकुंद नरवास, जग्गू राम आंचला, अर्जुन पोटाई, दशरथ दुग्गा परतापुर के रहने वाले हैं। सभी जनमिलिशिया से जुड़कर कई दिनों से काम कर रहे हैं। चारों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में सभी ने आईईडी ब्लास्ट में शामिल होने की बात स्वीकार की है। जिसके बाद उन पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

एक्शन में विधायक, रेत माफियाओं पर लगाम कसने दिए निर्देश

सड़क निर्माण जल्द पूरा करने को कहा

बिलासपुर। प्रदेश में भाजपा की सरकार आते ही अवैध निर्माण और माफियाओं पर कार्रवाई शुरू हो गई है। वहीं बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला रेत माफियाओं पर लगाम लगाने सड़क पर उतर गए। उन्होंने क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में एरिगेशन की सड़कों पर बेधड़क हाइवा पर रोक लगाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने सरकंडा के मोपका में साल भर से बन रहे स्मार्ट सिटी सड़क को भी एक माह के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए।

रेत माफियाओं के खिलाफ बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला एक्शन मोड में हैं। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र मोपका, सेलर, जाली, बाम्हू सहित आसपास के इलाकों में सक्रिय रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए, इस दौरान विधायक को जानकारी दी गई कि प्रशासन और पुलिस से बचने के लिए रेत माफिया एरिगेशन डिपार्टमेंट की नहर लाइन वाली छोटी सड़कों पर ट्रैक्टर और हाइवा से रेत परिवहन कर रहे हैं। इस पर उन्होंने सिंचाई विभाग के अफसरों को तलब किया और नहर लाइनिंग की सभी सड़कों को केवल छोटी गाड़ियों के लिए चालू रखने और सड़क पर भारी वाहनों पर सख्ती से प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान विधायक सुशांत शुक्ला ने मोपका के धान मंडी रोड में डेढ़ किलोमीटर तक स्मार्ट सिटी की मद से बन रही सड़क को एक माह के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। बता दें कि 1 करोड़ 90 लाख रुपये की लागत से यहां डेढ़ किलोमीटर सड़क का निर्माण चल रहा है।

मनमानी पड़ेगी मंहगी

54 राइस मिलरों ने सरकार को लगाई करोड़ों की चपत, ब्लैक लिस्टेड के साथ होगी वसूली

दुर्ग। जिले मे राइस मिलरों पर अब जिला प्रशासन कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। 54 राइस मिलर प्रशासन को करोड़ों रुपये की चपत लगाने में लगे हैं। बार-बार नोटिस के बाद भी जिले के 54 राइस मिलरों ने सरकार से धान तो लिया, लेकिन कस्टम मिलिंग की करोड़ों मूल्य के चावल को समय पर जमा नहीं करने से शासन को भारी नुकसान हुआ है। वहीं नोटिस जारी करके विपणन विभाग राज्य शासन के अगले आदेश का इंतजार कर रहा है। आदेश के बाद राइस मिलरों पर ब्लैक लिस्टेड और वसूली करने की कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि, राइस मिलरों की मनमानी को रोकने के लिए दुर्ग जिला विपणन विभाग ने उसका कस्टम मिलिंग का अनुबंध समाप्त करने का निर्णय लिया है। दुर्ग जिला विपणन अधिकारी भौमिक बघेल ने बताया कि, जिले में वर्ष 22-23 में कस्टम मिलिंग के लिए 151 राइस मिलरों का पंजीयन किया गया था। अनुबंध के अनुसार प्राप्त धान के एवज में प्रत्येक राइस मिलरों को 1 क्विंटल अरवा धान के बदले 67 किलो चावल और 1 क्विंटल उसना धान के बदले 68 किलो चावल जमा करना था। लेकिन 54 राइस मिलरो ने आज तक लगभग 19000 टन चावल जमा ही नहीं किया। इससे शासन को 72 करोड़ 84 लाख रुपए नुकसान झेलना पड़ रहा है।

नियमानुसार तय समय सीमा के अन्दर राइस मिलरो को चावल जमा करना अनिवार्य होता है। चावल जमा नहीं करने पर प्रशासन उन पर उचित कार्रवाई करने के साथ उनका पंजीयन नए सत्र के कस्टम मिलिंग के लिए नहीं करता है। उन्होंने कहा कि, राइस मिलर्स ने 70 प्रतिशत या उससे अधिक चावल जमा किया है। केवल उसी के साथ ही कस्टम मिलिंग का अनुबंध किया जाएगा, शेष के साथ अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा। वहीं जिले में वर्ष 23-24 के लिए 1 नवंबर से अभी तक 161785 मैट्रिक टन धान की खरीदी हुई है और 107118 मैट्रिक टन धान के लिए डीओ जारी किया जा चुका है, जिसमें से 70643 मिट्रिक टन धान का उठाव हो चुका है। बाकी 36475 मैट्रिक टन धान अभी भी धान उपार्जन केन्द्रों में खुले आसमान में पड़ा है।

स्कूल में व्यवस्था बदहाल, नौनिहालों के भविष्य से खिलवाड

बिना मिड डे मील खिलाए स्कूल की समय से पहले कर दी गई छुट्टी

गरियाबंद। जिले के छुरा विकासखंड के अंतिम छोर स्थित ग्राम छिंदौली में शिक्षा का स्तर बदहाल है। आदिवासी बाहुल्य वनाआंचल ग्राम में लापरवाही इस कदर सामने आ रही है कि बिना मिड डे मील खिलाये ही स्कूल बंद होने से पहले बच्चों को छुट्टी दे दी गई।

मीडिया की टीम शुक्रवार को जब स्कूल पहुंची तो कक्षा पहली से पांचवी तक दर्ज कुल 37 बच्चों वाली स्कूल में सन्नाटा का आलम पसरा हुआ था। वहीं मौके पर उपस्थित शिक्षक सवालों से बचते हुए नजर आए।

स्कूल नहीं लगने पर परीसर में खड़ी ट्रैक्टर ट्राली में बच्चे खेलते नजर आए। इस दौरान जब नौनिहालों से पूछा गया तो उन्होंने बताया की आज समय से पहले स्कूल की छुट्टी हो गई है। साथ ही बच्चों को मिड डे मिल भी नहीं दी गई। इस मामले को लेकर जब स्कूल के शिक्षकों से बात की गई तो कुछ शिक्षक सवाल से बचते नजर आए तो कुछ ने जवाब दिया।

शिक्षक यशवंत नागेश ने बताया कि बच्चों का पेपर लेने के बाद छुट्टी दे दे गई। बाचे को मीड डे मील नहीं मिलने पर शिक्षक ने कहा कि मध्यान भोजन बनाने वाले के घर किसी का निधन हो गया है, जिसकी वजह से उन्हें मीड डे मील नहीं दिया गया।

केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा स्कूली बच्चों को उच्च शिक्षा देने नित नए अभिनव पहल कर लाखों करोड़ों रुपये खर्च किये जाने के बाद गैर जिम्मेदार शिक्षकों के द्वारा नौनिहालों की भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। अब इस तरह की लापरवाही उजागर होने के बाद देखने वाली बात होगी की शिक्षा विभाग मामले में क्या कार्रवाई करता है।

हारे भाजपा विधायक की कांग्रेस को चेतावनी

संभल कर रहें, छत्तीसगढ़ में अब हमारी सरकार

बीजापुर। पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने जिला प्रशासन पर एक बार फिर बड़े आरोप लगाए हैं।भाजपा नेता महेश गागड़ा ने बयान जारी करते हुए जिला पंचायत सीईओ पर बड़ा आरोप लगाया है। गागड़ा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम शाह मंडावी को फायदा पहुंचाने के लिए प्रशासन ने करोड़ों की हेराफेरी की।

महेश गागड़ा ने कहा है कि ग्राम पंचायतों की डीएससी अपने पास रखकर 15 वें वित्त योजना की राशि में बड़े स्तर पर सेंधमारी की गयी है। चुनाव से पहले कांग्रेस को फायदा पहुंचाने ग्राम पंचायतों के खातों से करोड़ों की राशि निकाली गई। मनरेगा में मुरूम कार्य और पंचायतों की राशि में बड़ा हेर-फेर करने का आरोप भी गागड़ा ने लगाया।

पूर्वमंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को दो टूक कह दिया है कि भाजपा की सरकार आ गई है, अब पाई-पाई की जांच होगी। ग्राम पंचायतों के खातों में डाका डालने वाले जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की सरकार से मांग की जायेगी।

गागड़ा के आरोपों को कांग्रेस विधायक विक्रम शाह मंडावी ने हल्के में लिया। उन्होंने कहा कि चुनाव में हार के बाद गागड़ा जी को अपनी हार का बहाना नहीं मिल रहा है। इसलिए वे अपने बचाव के लिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं।

बीजापुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम शाह मंडावी और बीजेपी से महेश गागड़ा के बीच चुनाव हुआ। जिसमें विक्रम शाह मंडावी ने महेश गागड़ा को 2 हजार से ज्यादा वोटों से हराया।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार बेमेतरा पहुंचे शर्मा

बेमेतरा। छत्तीसगढ़ के नए डिप्टी सीएम विजय शर्मा शनिवार को बेमेतरा पहुंचे। वे अपने गृह नगर कवर्धा के लिए जा रहे थे। इसी दौरान बेमेतरा शहर में भाजपा कार्यकर्ताओं व शहर के लोगों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। बेमेतरा के तीनों विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। इस जीत के पीछे भाजपा कार्यकर्ताओं का विशेष योगदान रहा है। लोगों ने भी भाजपा को अच्छा समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने चुनाव के दौरान जो भी वादे किए हैं, सभी को पूरा करेंगे। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष ओमप्रकाश जोशी, पूर्व जिला अध्यक्ष राजेन्द्र शर्मा, योगेश तिवारी, जिला महामंत्री नरेन्द्र वर्मा समेत अन्य लोग उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ के शिमला में बिछी बर्फ की चादर

अंबिकापुर। सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मैनपाट में धीरे-धीरे तापमान नीचे जा रहा है।जिससे बर्फ की चादर जमने लगी है। आपको बता दें मैनपाट में न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सरगुजा जिले के मैनपाट के पठारी क्षेत्र में सुबह के समय ओस गिर रही है।ओस की बूंदे जब जमती है तो ऐसा लगता है मानो बर्फ की चादर बिछी हो।मैनपाट की इस खूबसूरती को देखने के लिए दूर दराज से लोग तिब्बतियों की इस बस्ती में आते हैं। नवंबर दिसंबर और जनवरी का महीना मैनपाट के लिए काफी खास होता है। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले इस जगह पर सैलानी ठंड के मौसम में भी आते हैं।यहां जमने वाली बर्फ लोगों को अपनी ओर खींचता है।लेकिन जिला प्रशासन सैलानियों के लिए कुछ खास व्यवस्थाएं जुटाने में नाकाम रहा है। स्थानीय लोग खुद से ही ठंड से बचने के लिए उपाय तलाशते हैं।अलाव की व्यवस्था ना होने से लोगों के साथ मवेशी भी काफी परेशान रहते हैं।

चलती मालगाड़ी के चार पहिये पटरी से नीचे उतरे

कोरबा। कुचेना के पास घटना चलती मालगाड़ी के एक डिब्बे के चार पहिये पटरी से नीचे उतर गए। पहिये उतरने के बाद भी मालगाड़ी 800 मीटर तक चलती रही। इस दौरान पटरी का एक बड़ा हिस्सा डैमेज हो गया और डिब्बे भी अलग-अलग हो गए। मालगाड़ी एसईसीएल. जूनाडीह साइडिंग से कोयला लोडकर कोरबा की ओर जा रही थी। इस घटना के बाद कोयला परिवहन भी प्रभावित हुआ। इस घटना के बाद हड़कप मच गया और इसकी सूचना रेलवे और एसईसीएल प्रबंधन को दी गई। जहां अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी ली। कोरबा आरपीएफ थाना प्रभारी आर एस चंद्रा ने बताया कि मामला जूनाडिह एसईसीएल प्राइवेट साइडिंग की है, जहां कुचेना के पास घटना घटी है। पीछे का चारों पहिया डिरेलमेंट एवं पीछे का सभी 10 वैगन पार्ट होकर अलग होना पाया गया। घटनास्थल पर पहुंची और रिरेलमेंट का कार्य शुरू किया। घटनास्थल पर क्षेत्रीय रेल प्रबंधक कोरबा एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर आरटीओ में बाबुओं की मनमानी, हाईकोर्ट ने फटकारा

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बाबुओं की मनमानी पर रायपुर के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को जमकर फटकार लगाई है। इसके साथ हुए वर्षों से एक ही जगह पर जमा कर्मचारियों के तबादला का आदेश दिया है। आदेश का परिपालन करने के बाद जानकारी देने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान पीड़ित के अधिवक्ता ने बताया कि रायपुर के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में पदस्थ क्लर्क की मनमानी चलती है। वर्षों से एक ही जगह पर जमे हुए हैं, और मनमानी करते हैं। कामकाज पर ध्यान नहीं देते। पीड़ित के साथ मारपीट की और उसी के खिलाफ ही झूठी शिकायत के आधार पर जुर्म दर्ज करा दिया है। अधिवक्ता की जानकारी के बाद हाईकोर्ट ने खमतराई थाना प्रभारी, रायपुर के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी व राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया था। मामले की सुनवाई जस्टिस एनके व्यास के सिंगल बेंच में हुई। जस्टिस व्यास ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कीर्तिमान राठौर को जमकर फटकार लगाई है।

नारायणपुर में महानगरों जैसा बना फुटबॉल मैदान

नारायणपुर। नारायणपुर नक्सल प्रभावित जिला है। यहां अबूझमाड़ का क्षेत्र नक्सल गतिविधियों के चलते आज भी पहुंचविहीन होने के साथ ही मूलभूत सुविधाओं और शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ माना जाता है। वहीं रामकृष्ण मिशन आश्रम अंदरूनी इलाकों के बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा, आवास समेत संस्कृतिक और खेल में रुचि रखने वालों छात्रों के लिए वरदान साबित हो रहा है। बता दें कि, रामकृष्ण मिशन आश्रम की ओर से फीका स्टेंडर्ड का आर्टिफिशियल टर्फ फुटबॉल मैदान का निर्माण कराया गया है। इसका कल उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक केदार कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में आश्रम के सभी महाराज, जनप्रतिनिधि समेत 1,200 छात्र मौजूद रहे। फुटलॉब मैदान बड़े महानगरों के तर्ज पर उच्च श्रेणी का बनाया गया है, जो नक्सल प्रभावित जिला नारायणपुर के खिलाड़ियों के लिए वरदान साबित होगा। आगामी समय में रामकृष्ण मिशन आश्रम की ओर से ऑल इंडिया टूर्नामेंट भी कराया जाएगा।

धूल चाट रही है सरोवर हमारी धरोहर योजना

- 17 एकड़ का तालाब जलकुंभी और गंदगी से लबालब

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। पेंड्रा नगर के सबसे बड़े बांधा तालाब में जलकुंभी एवं गंदगी के प्रकोप के कारण तालाब निस्तार योग्य नहीं रह गया है। लगभग 17 एकड़ में फैले बांधा तालाब से सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि में सिंचाई होती थी और पूरा गांव इस तालाब में निस्तारी करता था, लेकिन कभी साफ पानी का प्रमुख स्रोत रहा बांधा तालाब अब अपने अस्तित्व का संकट झेल रहा है। पेंड्रा नगर के पुरानी बस्ती स्थित राजमहल के पीछे बांधा तालाब की दुर्दशा देखी नहीं जाती। आलम यह है कि इस पूरे तालाब में जलकुंभी का प्रकोप छाया हुआ है, पूरे तालाब में गंदगी ही गंदगी है। शाम को तालाब को देखने पर ऐसा लगता है यह तालाब नहीं खेल का मैदान है।

बांधा तालाब के मेढ से होकर जो सड़क जाती है वह नए बस स्टैंड पेंड्रा को पुरानी बस्ती एवं बचरवार की बड़ी आबादी को जोड़ती है। इस सड़क का नवनिर्माण नगर पंचायत अध्यक्ष राकेश जालान के विशेष प्रयास से हुआ है, परंतु बांधा तालाब की दुर्दशा चरम पर है।

वर्ष 1997- 98 के आसपास नगर पंचायत अध्यक्ष इकबाल सिंह के कार्यकाल में बांधा तालाब का गहरीकरण एवं सौंदर्यीकरण हुआ था। एक दौर वह भी था जब इस बांधा तालाब से पुरानी बस्ती से लगे किसानों की सैकड़ो एकड़ कृषि भूमि की सिंचाई होती थी तथा इस तालाब में मछली पालन भी होता था और पुरानी बस्ती के लोग निस्तार भी करते थे परंतु अब स्थिति यह है कि इस तालाब में फैली जलकुंभी एवं गंदगी के कारण यह तालाब निस्तार योग्य नहीं रह गया है। बांधा तालाब को देखकर ऐसा लगता है जैसे सरोवर हमारी धरोहर योजना धूल चाट रही है।

17 एकड़ में फैले बांधा तालाब के चारों ओर कई तालाब हैं, जो इस स्थान को खूबसूरत बनाते हैं। सुबह-शाम यहां की रौनक देखते बनती है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय लोग समय बिताने यहां आना चाहते हैं। यहां पर तालाब की अधिक संख्या होने के कारण विशेष रूप से ठंडक होती है। पास ही मुक्तिधाम स्थित है जहां नगर के रचनात्मक युवाओं ने मुक्तिधाम विकास समिति बनाकर मुक्तिधाम को सजाया हुआ है। मुक्तिधाम से सटे होने के कारण इन तालाबों में अमृत कर्म करने के पश्चात लोग शुद्धिकरण एवं स्नान के लिए आते हैं परंतु लगातार तालाब की दुर्दशा को देखकर लोग अब यहां नहाना पसंद नहीं करते। ऐसे में अब जरूरी है कि इस सरोवर को बचाया जाए तथा इसे खूबसूरत बनाने के लिए नगर पंचायत पेंड्रा आगे आए।

भानुप्रतापपुर के स्कूल से भागी तीन छात्राएं, दो को पुलिस ने झांसी से किया बरामद

कांकेर। भानुप्रतापपुर के निजी स्कूल के हॉस्टल से लापता हुई तीन छात्राओं में से दो को पुलिस ने बरामद किया है। तीन छात्राओं के लापता होने की जानकारी सामने आई थी। स्कूल प्रबंधन ने इसकी शिकायत पुलिस से की थी ।तीनों ही छात्राएं पखांजूर और मानपुर क्षेत्र से पढ़ाई करने के लिए भानुप्रतापपुर आई थी। जहां तीनों निजी स्कूल के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी।लेकिन स्कूल के बाद अचानक तीनों छात्राएं बिना किसी को सूचना दिए कहीं चली गई थी। जिसमें से दो छात्राओं को पुलिस ने झांसी से बरामद किया है।वहीं एक छात्रा अब भी लापता है।

कांकेर एसपी दिव्यांग पटेल ने के मुताबिक शुक्रवार शाम को पुलिस के पास रिपोर्ट आई थी। तीन बालिकाएं भानुप्रतापपुर सेंट जोसेफ स्कूल से बिना बताए भाग गई हैं। इसके संबंध में तत्काल अपराध कायम किया गया। इसके संबंध में जांच पड़ताल किया गया।

एसपी ने कहा विशेष टीमों का गठन किया गया। जिसके बाद महज 24 घंटे के अंदर दो बच्चियों को झांसी से बरामद किया गया है।वहीं तीसरी बच्ची की तलाश जारी है उसे भी तत्काल बरामद कर लिया जाएगा।

स्कूल के प्राचार्य के मुताबिक इसकी जानकारी रात साढ़े 10 बजे मिली। जब स्कूल में अटेंडेंस मिसिंग था।इसके बाद पैरेंट्स से जानकारी ली गई।लेकिन उन्हें भी बच्चियों के बारे में जानकारी नहीं थी। इसके बाद पैरेंट्स स्कूल आए और रिश्तेदारों समेत बच्चियों के दूसरे साथियों के पास कॉन्टैक्ट लिया।लेकिन कोई जानकारी सामने नहीं आई।हॉस्टल के कमरे से दो फोन भी बरामद हुए थे जो लॉक होने के कारण नहीं खुले।इसके बाद बच्चियों के लापता होने की जानकारी पुलिस को दी गई।

जब बिरहोरों के लिए काम करने वाले नंगे पांव पहुंचे स्वयंसेवी को आत्मीयता से पुकारा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने, पहुना में पहुना भाव की तरह ही लोगों से बेहद आत्मीयता से मिल रहे मुख्यमंत्री

आ ऐती आ, उहां का खड़े हस, मोर कोती आ

रायपुर। जागेश्वर राज्य अतिथि गृह पहुना में मेजबान मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय हैं और पहुना है प्रदेश भर से आने वाले उनके आत्मीय स्नेहीजन। हर स्नेहीजन से मुख्यमंत्री पहुना में बेहद आत्मीयता से मिल रहे हैं। आज मुख्यमंत्री के गांव के निकट भीतघर से उनसे मिलने जागेश्वर राम पहुंचे। जागेश्वर राम कभी चप्पल नहीं पहनते, वे कपड़े भी मामूली ही पहनते हैं। वे मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से मिलने जब पहुना पहुंचे तो वे बैरिकेड के उस पार थोड़े से संकोच के भाव से अपनी बारी का इंतजार करते खड़े हो गये। मुख्यमंत्री श्री साय जब आये तो परिचितों से भेंट करते वक्त उनकी नजर दूर खड़े जागेश्वर राम पर गई। उन्होंने जागेश्वर को आवाज लगाई। बड़ी आत्मीयता से उन्होंने पुकारा। आ ऐती आ, उहां का खड़े हस, मोर कोती आ। फिर उन्होंने जागेश्वर राम को गले लगाया, पूरे समय साथ ही रहे और समय-समय पर आत्मीय चर्चा करते रहे। जागेश्वर ने उन्हें कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के 18 लाख लोगों को आवास देने के निर्णय पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से सरगुजा संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति के हजारों बिरहोर लोगों को आवास मिलने का रास्ता खुल गया है जो घास-फूस की

झोपडियों में हर साल सरगुजा की कड़ी सर्दी गुजारते हैं।

दरअसल जागेश्वर राम और मुख्यमंत्री श्री साय के बीच आत्मीयता की जो कड़ी जुड़ी, वो प्रदेश की अति पिछड़ी जनजाति मानी जाने वाली बिरहोर जनजाति की वजह से जुड़ पाई। जागेश्वर राम महकुल यादव जाति से आते हैं। अपने युवावस्था के दिनों में जब पहली बार वे बिरहोर जनजाति के संपर्क में आये तो इस विशेष पिछड़ी जनजाति की बेहद खराब स्थिति ने उन्हें बेहद दुखी कर दिया। वे शेष दुनिया से कटे थे। शिक्षा नहीं थी, वे झोपडियों में रहते थे। स्वास्थ्य सुविधा का अभाव था। उन्होंने संकल्प लिया कि अपना पूरा जीवन बिरहोर जनजाति के बेहतरी में लगाऊंगा। यह बहुत बड़ा मिशन था और इसके लिए उन्होंने अपनी ही तरह के संवेदनशील लोगों से संपर्क आरंभ किया। इसके चलते वे तत्कालीन सांसद श्री विष्णु देव साय के संपर्क में आये। श्री राम ने उनके समक्ष इस जनजाति के विकास के लिए योजना रखी। सांसद ने उन्हें पूरे सहयोग के लिए आश्वस्त किया। इसके बाद सांसद श्री साय के सहयोग से भीतघरा और धरमजयगढ़ में आश्रम खोले।

शुरूआत में ऐसी स्थिति थी कि लोग आश्रम से अपने बच्चों को घर ले जाते थे लेकिन जब आश्रम में पहली पीढ़ी के बच्चे पढ़कर निकले और उनके जीवन में सुखद बदलाव आये तो बिरहोरों ने अपने बच्चों को यहां भेजना शुरू किया। इस गौरवमयी उपलब्धि के लिए राज्य अलंकरण समारोह में उन्हें शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

मुख्यमंत्री से जागेश्वर राम ने कहा कि अब हमारे बिरहोर लोगों की मकान की जरूरत पूरी होगी। आपने 18 लाख आवासों के स्वीकृत करने का निर्णय कैबिनेट की बैठक में किया है। मैंने बिरहोरों की तकलीफ देखी हैं। उनकी उजाड़ झोपडियों की जगह अब पक्के घर होंगे। छत्तीसगढ़ में बड़ा फैसला आपने किया है जो लाखों बिरहोरों के जीवन में सुखद बदलाव लाएगा।

अति विशिष्ट अतिथियों की अगवानी करने वाले परिसर पहुना में आने वाला हर व्यक्ति इस बात को लेकर आशंकित रहता है कि मुख्यमंत्री से मिलने वाले हजारों प्रियजनों के बीच उसे मुख्यमंत्री का थोड़ा समय मिल पाएगा या नहीं। यह आशंका उन लोगों में और भी बढ़ जाती है जो आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं लेकिन पहुना आते ही उन्हें अपने घर-गांव जैसा ही माहौल लगता है जैसे पूरा पहुना परिसर मड़ई की तरह हो गया हो और वे पहुना हो गये हों। अपने लोगों से गहरा स्नेह रखने वाले मुख्यमंत्री यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि अपने सभी प्रियजनों को समय दें।

खाट-पलंग की व्यवस्था की थी श्री साय ने- श्री जागेश्वर राम ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सांसद रहते बिरहोर जनजाति के दुखदर्द को समझा। वे झोपडियों में सर्द रातें बिना खाट के गुजारते थे। श्री साय ने उनके लिए खाट-पलंग की व्यवस्था की। वे 1980 से ही उनके साथ हैं और पहाड़ी कोरवा तथा बिरहोर जनजाति के इलाकों में जब भी दौरे पर जाते हैं जागेश्वर राम को साथ ही रखते हैं।

दूसरी पार्टी में परिवारवाद चलता है और भाजपा में लोकतंत्र, सभी को मिलता है सम्मान : साय

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और यह पार्टी विचारधाराओं की पार्टी है। इसमें नीति, नियम होते हैं और कार्यकर्ताओं का सम्मान भी होता है। अगर कार्यकर्ता निष्ठा, ईमानदारी के साथ परिश्रम करता है तो इसका फल उसको पार्टी से जरूर मिलता है। दूसरी पार्टी में परिवारवाद चलता है, लेकिन भाजपा में लोकतंत्र है।

सीएम विष्णुदेव साय ने कहा %मैं एक किसान का बेटा हूं और बहुत कम उम्र में जिम्मेदारियां मिलीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस पद तक पहुंचूंगा। मैं लगातार दो बार विधायक चुना गया और चार बार सांसद रहा। मैंने पीएम मोदी के मार्गदर्शन में राज्य मंत्री के रूप में भी काम किया। मैं पार्टी का आभारी हूं कि मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मुझे विश्वास है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में मैं इस पद की जिम्मेदारी निभाने के लिए सफल होऊंगा।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है, कई संस्थाएं पार्टी के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाकर राष्ट्रवाद और भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन यह ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा और इसका नतीजा हाल के विधानसभा चुनावों में देखा गया।

छत्तीसगढ़ के नए सीएम विष्णुदेव का प्रदेश में बड़ा नाम है। वे आदिवासी समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। विष्णुदेव साय चार बार सांसद, दो बार विधायक, केंद्रीय राज्य मंत्री और दो-दो बार के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके साथ ही

साय को संगठन में काम करने का लंबा अनुभव भी है। साल 2023 में विधानसभा चुनाव में उन्होंने कुनकुरी सीट से जीत हासिल की है। विष्णुदेव साय साफ छवि के नेता के रूप में भी जाने जाते हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाए जाने के बाद भी वे पार्टी से लगातार जुड़े रहे।

मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फ़ी ज़ोन में फोटो खिंचवाई

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फ़ी ज़ोन में फोटो खिंचवाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न स्टालों का अवलोकन किया और शासकीय योजना के हितग्राहियों से चर्चा की।

संक्षिप्त समाचार

डिप्टी सीएम साव से रायपुर आईजी डांगी और एसएसपी अग्रवाल ने की मुलाकात

रायपुर। उपमुख्यमंत्री अरुण साव से शनिवार को रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक रतनलाल डांगी और रायपुर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने सौजन्य मुलाकात की। डिप्टी सीएम साव को उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनने पर बधाई और शुभकामना दी। उपमुख्यमंत्री साव ने इस दौरान दोनों से रायपुर रेंज और जिले में कानून-व्यवस्था की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने पुलिस के सभी विंग्स के बेहतर समन्वय से अपराध पर नियंत्रण कराने को कहा।

राष्ट्रीय महासचिव वेणुगोपाल से मिले कांग्रेस के पूर्व विधायक

रायपुर। कांग्रेस के पूर्व विधायकों ने दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की है। इस दौरान छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की करारी हार पर चर्चा की। वहीं पार्टी के कुछ बड़े नेताओं की शिकायत भी की। बता दें कि पूर्व विधायक विनय जयसवाल के घर शुक्रवार को पूर्व विधायकों ने बैठक की थी। इसके बाद आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करने दिल्ली पहुंचे हैं। वहीं अनुशासनहीनता बरतने पर पार्टी ने पूर्व विधायक विनय जयसवाल और बृहस्पत सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पूर्व विधायक विनय जयसवाल ने कहा, हमने अपनी बात रख दी है। वेणुगोपाल ने जिन 22 नेताओं की टिकट कटी थी उनसे मुलाकात कर वन टू वन चर्चा करने की बात कही है।

किसान ने की आत्महत्या, बघेल ने ट्विटर पर लिखा फिर से वही दौर लौट आया है

रायपुर। नारायणपुर में किसान की आत्महत्या के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। शायराना अंदाज में उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि 'फिर वही दौर लौट आया है, किसानों की चीख का शोर लौट आया है।' जानकारी के मुताबिक नारायणपुर के कुकड़ाझोर गांव में एक किसान द्वारा कर्ज में डुबे होने की वजह से आत्महत्या करने की बात सामने आई है। हालांकि जिला प्रशासन इस बात से इन्कार कर रहा है। कलेक्टर अजीत वसंत ने बताया कि उक्त किसान के नाम पर किसी प्रकार का कोई भी कर्ज नहीं है। मृतक व्यक्ति के रिश्तेदार के नाम पर कर्ज है, जिसे नोटिस जारी किया गया था।

मुख्यमंत्री साय ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह से की सौजन्य मुलाकात

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह से उनके राजधानी रायपुर स्थित निवास में सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय को पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव व विजय शर्मा उपस्थित रहे।

कांग्रेस के पूर्व विधायक ने दिया इस्तीफा

रायपुर। प्रदेश में कांग्रेस की हार के बाद अब पार्टी में बिखराव शुरू हो गया है। लगातार नेताओं को पार्टी छोडऩे का सिलसिला जारी है। इसी बीच पाली तानाखार के पूर्व विधायक मोहित राम केरकेट्टा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा व पीसीसी चीफ दीपक बैज को अपना त्यागपत्र भेज दिया है। बताया जा रहा है कि मोहित राम केरकेट्टा पार्टी के कई फैसलों से नाराज चल रहे थे।

राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से सौजन्य भेंट की

रायपुर। राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन ने शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से सौजन्य भेंट की। और राज्य हित से जुड़े विषयों पर चर्चा की ।

मंत्री बनने के लिए तैयार हैं विधायक ईश्वर साहू, पहले चलाते थे रिक्शा, सुरक्षाकर्मियों ने घेरा

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के सबसे चर्चित प्रत्याशी रहे ईश्वर साहू चुनाव जीतकर विधायक बन चुके हैं। विधायक बनते ही उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है। कभी रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट पालने वाले ईश्वर साहू सुरक्षाकर्मियों से घिरे नज़र आ रहे हैं। इतना ही नहीं,अब उनके चाहने वाले उन्हें मंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के 54 विधायकों में सबसे चर्चित साजा विधायक ईश्वर साहू को सुरक्षाकर्मियों ने घेर लिया है। उन्हें एक्स श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। इस सुरक्षा के पीछे ईश्वर साहू और उनके परिवार पर थ्रेट को वजह बताया जा रहा है। ईश्वर साहू का परिवार साजा के बिरनपुर में हिंसा का शिकार है। बताया जा रहा है कि उनके हर दिन दहशत और धमकियों में गुजार रहे हैं।

बिरनपुर हिंसा में अपने जवान बेटे को खोने वाले ईश्वर साहू के घर मातम खत्म नहीं हुआ था कि अब उनके विधायक बनने की खुशियां मनाई जा रही हैं। उनके गांव और साहू समाज के लोगों ने ईश्वर साहू को विष्णुदेव साय सरकार में मंत्री बनाने की मांग की है। एक यूट्यूबर को दिए साक्षात्कार में मंत्री बनने के सवाल पर दिए गए जवाब ने ईश्वर साहू ने बड़ा ही रोचक जवाब दिया है। ईश्वर साहू का कहना है कि मुझे पता नहीं था कि मै राजनीति में आऊंगा और चुनाव जीतूंगा। अब राजनीति के मैदान में आ चुका हूं, तो अगर भगवान और भाजपा संगठन चाहेगा,तो मंत्री पद भी मुझे स्वीकार होगा।

गैर- राजनीतिक पृष्ठभूमि से आने वाले ने ईश्वर साहू 7 बार के विधायक और भूपेश बघेल सरकार के दिग्गज मंत्री रविन्द्र चौबे को 5 हजार 196 वोटों के अंतर से हारकर साजा विधानसभा से चुनाव जीतकर विधायक बने हैं। रविन्द्र चौबे ने छत्तीसगढ़ सरकार में कृषि, पंचायत और संसदीय मंत्री रहते हुए चुनाव लड़ा था, वहीं पांचवी तक की पढ़ाई करने वाले 42 वर्षीय ईश्वर साहू खेतिहर मजदूर है। चुनाव लड़ने से पूर्व तक वह अपने जीवनयापन के लिए नागपुर में सब्जी बेचने और रिक्शा चलाने का काम कर रहे थे। रोहित को कप्तानी से हटाना मुंबई को पड़ा भारी, रातोंरात इतने लाख फैन्स ने इन्स्टाग्राम पर किया उनफॉलोरोहित को कप्तानी से हटाना मुंबई को पड़ा भारी, रातोंरात इतने लाख फैन्स ने इन्स्टाग्राम पर किया उनफॉलो

ज्ञात हो कि साजा विधानसभा के बीरनपुर नामक गांव में 8 अप्रैल 2023 को हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगो के बीच मामूली विवाद ने सांप्रदायिक रूप ले लिया था। इस विवाद ने हिंसा का रूप ले लिया,जिसमे ईश्वर साहू के 22 साल के बड़े बेटे भुवनेश्वर साहू की हत्या हो गई थी। भाजपा ने इसे मुद्दा बनाया और कांग्रेस सरकार के मंत्री रविंद्र चौबे के खिलाफ ईश्वर साहू को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया था। इस घटना की चर्चा पूरे देश में हुई और ईश्वर साहू चुनाव जीत गए। बहराहल ईश्वर प्रदेश के सबसे गरीब विधायकों में से हैं।

अपनी पार्टी के साथ चर्चा के आधार पर कहा था की 2 लाख रुपये तक कर्ज माफी होगी : विजय शर्मा

रायपुर। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा वनवासी कल्याण आश्रम रोहिणीपुरम पहुंचे। जहां बहनों ने तिलक लगाकर उनका स्वागत किया। उन्होंने आश्रम के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान डिप्टी सीएम शर्मा ने किसानों की कर्ज माफी समेत अनेक मुद्दों पर बयान दिया। यहां से विजय शर्मा विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने कवर्धा रवाना हुए।

उन्होंने कहा कि 3ञ्30 कवर्धा में कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम का उद्बोधन शाम 4 बजे प्रारम्भ होगा, लाभार्थियों तक पहुंचने और अन्य फीडबैक लेने के लिए ये प्रोग्राम हैं।

कर्ज माफी पर बयानबाजी को लेकर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अपनी पार्टी के साथ चर्चा के आधार पर कहा था की 2 लाख रुपये तक कर्ज माफी होगी। घोषणापत्र आने के बाद भी मैंने कहा कि इससे बड़ी योजना आ गई है।

धर्मांतरण पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। हमारा भाव स्पष्ट है कि अवैध धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो प्रशासन इसे लेकर कार्रवाई करेगी। कर्ज माफी पर बयानबाजी को लेकर उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि अपनी पार्टी के साथ चर्चा के आधार पर कहा था की 2 लाख रुपये तक कर्ज माफी होगी। घोषणापत्र आने के बाद भी मैंने कहा कि इससे बड़ी योजना आ गई है।

डिप्टी सीएम ने वनवासी कल्याण को लेकर कहा कि वनवासी हितरक्षा के संरक्षण में पहले भी कार्य किए हैं। वनाधियाकृ अधिनियम के अंतर्गत तीन प्रावधान होते हैं। व्यक्तिगत पट्टा, सामुदायिक पट्टा, वन प्रबंधन का अधिकार। वन प्रबंधन का अधिकार इस अधिनियम का सर्वोच्च भाव है। पारंपरिक तौर पर वन क्षेत्र के अधिकार का पट्टा उन्हें दिया जाता है। चाहटा नाम का गांव कवर्धा जिले का है। इस गांव को वन प्रबंधन का अधिकार मिला है।

मोदी की गारंटी पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा, आगे लोकसभा चुनाव है। भाजपा को 11 सीट छग में भाजपा को मिलें। इसके लिए आज से नहीं बहुत पहले से हमने प्रयास प्रारम्भ कर दिया है।

केंद्रीय योजनाओं का कितना असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा इस पर डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा कि केंद्रीय योजनाओं को विगत सरकार ने किस तरह निस्तोनाबूद किया, हम सबने देखा हैं। पीएम आवास सिर्फ इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री शब्द आ गया था। मुख्यमंत्री साय ने नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख आवास को स्वीकृति दी और अन्य केंद्रीय योजनाओं का जो बंदर बांट यहां पर किया गया था। उस पर भी अभी बात की जा रही है।

निगम मंडल की नियुक्तियां रद्द होने पर उन्होंने कहा, अलग-अलग विषय होते हैं जो संवैधानिक होते हैं। आयोग उन्हें नहीं हटा सकता, उनका कार्यकाल 5 साल का होता है। नई सरकार की मंशा है कि नए ढंग से काम शुरू किया जाए। आपकी सोच के साथ काम करने वाले व्यक्ति आपके साथ है तो बात आगे बढ़ती है और नहीं तो बात अटकती है। नई सरकार का सोचना है कि बात ना अटके।

कांग्रेस के पूर्व विधायकों के आरोप पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में अनेक नेता अनेक विषयों पर आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हैं। कोई गलत नहीं कह रहा सब सही है। विगत सरकार के कार्यकाल में हर चौराहों पर पैसे की खोज होती थी। इसका परिणाम आज देखने मिल रहा है।

विधायक अनुज शर्मा ने अवैध शराब पर कड़ाई से रोक लगाने के दिए निर्देश

कहा अधिकारीगण जनता से करें सदव्यवहार

रायपुर। धरसींवा विधायक श्री अनुज शर्मा ने शुक्रवार को कलेक्टोरेट परिसर स्थित कलेक्टर सभाकक्ष में एक पखवाडे के भीतर ही जिले के अधिकारियों की समन्वय बैठक लेते हुए कहा कि हमारा सर्वोपरी उद्देश्य उनके विधानसभा क्षेत्र के एक-एक गांव विकास करना है। साथ ही ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना है कि उनके क्षेत्र का ग्राम आदर्श ग्राम के रूप राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हो। श्री शर्मा ने कहा कि किसी भी हाल में अवैध शराब के बिक्री पर रोक लगाने। पुलिस एवं आबकारी विभाग टीम बनाकर निरंतर गांव का दौरा करें और ऐसे कोचियों पर कड़ी कार्रवाई करें। साथ ही ऐसे प्रकरणों की सूची बनाकर उसका परीक्षण करें ताकि इसकी पुनरावृति ना होने पाए।

उन्होंने कहा कि वे स्वयं जल्द अधिकारियों की टीम बनाकर गांवो का दौरा करेंगे आम जनता के समस्या सुनेंगे और यह भी प्रयास करेगें कि यथासंभव उनके समस्याओं का समाधान हो। विधायक श्री शर्मा ने कहा कि सभी अधिकारी जनता की समस्याओं को संवेदनशीलता से सुने और अच्छा व्यवहार करें। यदि जो कार्य त्वरित हो सकते हैं उसे अवश्य करें, जो कार्य संभव ना हो विनम्रता पूर्वक कारण बता दें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी शासकीय योजनाओं को गति प्रदान करें। एक गांव का आदर्श ग्राम के रूप में चयन करें।

वे स्वयं अपने क्षेत्र के ग्रामीणों को अन्य प्रदेशों के आदर्श ग्रामों को अवलोकन करने ले जाएंगे, जिससे उनमें जागरूकता आए।

उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र मे औद्योगिक क्षेत्र भी शामिल है, उनके साथ समन्वय बनाकर कार्य करें जिससे गांव का वातावरण सकारात्मक रहे। उन औद्योगिक समूहों के सहयोग से लेकर गांवों में विकास कार्य तेजी से किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अभी धान खरीदी चल रही है सभी विभागीय अधिकारी यह प्रयास करें कि किसानों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो और वे आसानी से अपना धान बेच सके। स्वास्थ्य केन्द्र में समय से चिकित्सक उपस्थित होएं और मरीजो से सदव्यवहार करते हुए ईलाज करें। खाद्य विभाग राशन दुकानों में आने वाले आम जनता को समय पर और बिना परेशानी के राशन देना सुनिश्चित करें। कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भुरे ने कहा कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगेगी। अतः जल्द विकास कार्यों को गति प्रदान करें।

सांसद सुनील सोनी ने रायपुर रेलवे स्टेशन पर किया नए फुट ओवरब्रिज का लोकार्पण

रायपुर। रेल यात्रियों के सुविधा के लिए रायपुर रेलवे स्टेशन पर नया फुट ओवरब्रिज बनाया गया है। इससे अब यात्री किसी भी प्लेटफार्म पर पहुंच सकते हैं, यानी प्लेटफार्म एक से सात तक सभी में जा सकेंगे। नए फुट ओवरब्रिज का आज लोकार्पण हुआ। कार्यक्रम में रायपुर सांसद सुनील सोनी, रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा और रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूणत शामिल हुए। ऋद्ङ्क्स्न स्थ्रह्द्द ङ्क डिप्टी सीएम अरुण साव से रायपुर ढ्ढत्र रतनलाल डांगी और स्स्क्रप्रशांत अग्रवाल ने की मुलाकात, कानून-व्यवस्था को लेकर हुई विशेष चर्चा

फुट ओवरब्रिज का लोकार्पण करने के बाद सांसद सुनील सोनी ने कहा कि अब रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट से भी बेहतर है। ढाई साल में एक मॉडल स्टेशन में रूप में लोकार्पण कर देंगे। उन्होंने कहा कि रायपुर लोकसभा में 8 स्टेशन है, सब का काम तेजी से होगा।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के शायराना ट्वीट पर सांसद सोनी ने कहा, भूपेश बघेल अभी भी बेहोशी से बाहर नहीं निकले हैं, हमारे सीएम ने शपथ ले लिया है और एक मोदी गारंटी है।

लगातार ट्रेनों के रद्द होने पर सुनील सोनी ने कहा कि, रेल अपडेट हो रहा है, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के लिए बेहतर होगा।

पिछली बार रेल विभाग को मात्र 300 करोड़ रुपए मिला था। 6 हजार करोड़ रुपए पीएम मोदी ने दिया है। वंदे भारत और दुरंतो जैसी ट्रेनें छत्तीसगढ़ में दौड़ेंगी। समय पर गंतव्य को पूरा करेंगे।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड कोण्डागांव जिला - कोण्डागांव (छ. ग.)

(फोन नंबर 07786-296071, ईमेल ideekon-pher-cg@gov.in)

-:: ई-प्रोक्यूरमेंट निविदा सूचना ::-

छत्तीसगढ़ की राज्यपाल की ओर से जिला कोण्डागांव में एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारो से निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती हैं:-

कार्य का नाम:- जल जीवन मिशन अंतर्गत विभिन्न ग्रामों में रेट्रोफिटिंग एवं एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना कार्य

स. क्र.	निविदा क्रमांक एवं दिनांक	सिस्टम निविदा क्रमांक	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (रू0 लाख में)
1	2	3	4	5
01	79/11.12.2023	149886	तोसकापाल रेट्रोफिटिंग नलजल प्रदाय योजना	99.96
02	80/11.12.2023	149887	कुम्हारबड़गांव एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना	88.56
03	81/11.12.2023	149889	लखनपुरी एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना	26.60
04	82/11.12.2023	149898	कुधूर एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना	85.99
05	83/11.12.2023	149905	मातेंगा एकल ग्राम ग्राम नलजल प्रदाय योजना	27.74
06	84/11.12.2023	149906	चिचाडी-2 एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना	20.22
07	85/11.12.2023	149909	सण्डसा-2 एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना	14.00
08	86/11.12.2023	149910	छोटेसोंहगा 2 एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना	15.90
09	87/11.12.2023	149911	केवटी-2 एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना	29.63
10	88/11.12.2023	149912	बड़बत्तर-2 एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना	47.75
11	89/11.12.2023	150001	झांकरी एकल ग्राम ग्राम नलजल प्रदाय योजना	70.29

निविदा की सामान्य शर्ते, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है, साथ ही यह जानकारी ई-प्रोक्यूरमेंट बेव पोर्टल http://cgeprocurement.gov.in पर तथा विभागीय बेवसाईट http://phedcegprocurement.gov.in से डाउनलोड की जा सकती हैं। डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 26.12.2023 है।

जी-06408

कार्यपालन अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड
कोण्डागांव (छ. ग.)

अब राजीव गांधी की गलती भी जल्द ही सुधर सकती है!

नीरज कुमार दुबे

उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर मोदी सरकार के फैसले को सही ठहरा कर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की ओर से की गयी ऐतिहासिक गलती को सुधारा था। अब उम्मीद की जा रही है कि उच्चतम न्यायालय जल्द ही पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की ओर से की गयी गलती को भी सुधार देगा। हम आपको याद दिला दें कि राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए असम में धारा 6ए लगा कर खतरनाक काम किया था। एक तरह से धारा 6ए के माध्यम से बांग्लादेश के अवैध घुसपैठियों को भारतीय नागरिकता देने की साजिश रची गयी और आबादी का संतुलन बिगाड़ कर अपने राजनीतिक स्वार्थ पूरे किये गये। इस मुद्दे को लेकर विभिन्न पक्ष उच्चतम न्यायालय गये थे जहां सुनवाई पूरी हो चुकी है और जल्द ही फैसला भी आ जाने के आसार हैं। उच्चतम न्यायालय ने असम में अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने से जुड़ी नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना आदेश को सुरक्षित रख लिया है। असम समझौते के दायरे में आने वाले लोगों की नागरिकता निर्धारित करने के लिए यह धारा नागरिकता अधिनियम में एक विशेष प्रावधान के रूप में शामिल की गई थी। इसमें कहा गया है कि जो लोग 1985 में संशोधित किये गए नागरिकता अधिनियम के अनुसार, बांग्लादेश सहित अन्य निर्धारित क्षेत्रों से 1 जनवरी, 1966 को या उसके बाद, लेकिन 25 मार्च, 1971 से पहले असम आए थे और तब से पूर्वोत्तर राज्य के निवासी हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए धारा 18 के तहत अपना पंजीकरण कराना होगा। परिणामस्वरूप, यह प्रावधान असम में रह रहे प्रवासियों, खासकर बांग्लादेश से आए लोगों को नागरिकता प्रदान करने के लिये 'कट ऑफ' तारीख 25 मार्च,1971 तय करता है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रखने से पहले अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान, कपिल सिब्बल और अन्य की चार दिनों तक दलीलें सुनीं। दलीलों के दौरान जो सबसे रोचक दलील आई वह केंद्र सरकार की ओर से थी। हम आपको बता दें कि केंद्र ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय को बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार के असहयोग और राज्य में भूमि अधिग्रहण के लंबित मुद्दों के कारण भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने की परियोजना बाधित हुई है। केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को बताया कि केंद्र सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा को सुरक्षित करने के लिए बहु-आयामी कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार के विधि अधिकारी तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को बताया कि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ 2,216.7 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है और 81.5 प्रतिशत बाड़ लगाई जा चुकी है। शेष सीमा पर भी बाड़ लगाने या तकनीकी समाधानों के माध्यम से उसे सुरक्षित करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। तुषार मेहता ने पीठ को बताया, "पश्चिम बंगाल सरकार कहीं अधिक धीमी, अधिक जटिल प्रत्यक्ष भूमि खरीद नीति का पालन कर रही है। यहां तक कि सीमा पर बाड़ लगाने जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों के लिए भी राज्य सरकार द्वारा असहयोग किया जा रहा है...।"

संसद सुरक्षा में चूक से ज्यादा साजिश

अजय सेतिया

13 दिसंबर 2001 को जब संसद पर आतंकी हमला हुआ था, उस समय मैं संसद के भीतर ही था।उसके बाद संसद के भीतर की सुरक्षा को आधुनिक उपकरणों से बेहतर ढंग से चाक चौबंद किया गया। इलेक्ट्रानिक गेट लगाए गए, सांसदों, पूर्व सांसदों, अधिकारियों, कर्मचारियों और पत्रकारों को चिप लगे पास दिए गए। लेकिन 22 साल बाद अब संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई है, उसके लिए भाजपा के सांसद प्रताप सिम्हा भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने बिना छानबीन किए अपने स्टाफ की सिफारिश पर सागर शर्मा और मनोरंजन के नाम पर दर्शक दीर्घा के पास बनवाए।

13 दिसंबर 2023 को ये दोनों लोकसभा में कूदने की पूरी योजना के साथ दर्शक दीर्घा का पास लेकर आए थे।वे अपने साथ जूते में छिपाकर कलरकेन लाए थे, जिसे उन्होंने लोकसभा में खोलकर रंगीन धुंआ फैला दिया।ठीक उसी समय संसद के बाहर रिसेप्शन के सामने भी उनके दो साथियों ने वैसे ही नारे लगाए और धुएं के केन लीक किए। संसद के भीतर ऐसी घटनाएं पहले भी बहुत बार हो चुकी हैं, इसलिए दर्शकदीर्घा पास बनवाते समय सांसदों को सावधानी बरतनी चाहिए।नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान 1994 में हू-ब-हू ऐसी ही दो घटनाएं हुई थीं।5 मई 1994 में प्रेमपाल सिंह सम्राट नाम का युवक नारे लगाते हुए लोकसभा में कूद गया था, उसने बाद में माफी मांग ली थी।कांग्रेस के नेता मुकुल वासनिक उस समय संसदीय कार्य राज्यमंत्री थे, उन्होंने जांच रिपोर्ट के बाद सदन में प्रस्ताव रखा था कि वह सदन की अवमानना का दोषी है, लेकिन क्योंकि उसने माफी मांग ली है, इसलिए उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए।

इससे तीन महीने बाद 24 अगस्त 1994 को भी मोहन पाठक नाम के युवक ने लोकसभा में छलांग लगा दी थी।उसी समय उसके एक साथी मनमोहन तिवारी ने भी दर्शक दीर्घा से नारेबाजी की थी।उन दोनों को अपने कृत्य पर कोई अफ़सोस नहीं था, इसलिए उन्हें तिहाड़ जेल भेजा गया और उनपर एफआईआर दर्ज करके मुकदमा चला। 2016 में भी एक युवक ने दर्शकदीर्घा से लोकसभा में कूदने की कोशिश की थी। इन घटनाओं के बाद लोकसभा सचिवालय को दर्शकदीर्घा पास के लिए गाईडलाईन बनानी

चाहिए थी, लेकिन सचिवालय ने ऐसा कुछ नहीं किया।संसद के सुरक्षा घेरे में हुई इस ताज़ा चूक के लिए आठ कर्मचारियों को निलंबित किया गया है, जिनकी जिम्मेदारी संसद के भीतर दर्शकदीर्घा में जाने वालों की तलाशी लेना था। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि संसद की सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों ने ही 22 साल पहले अपने प्राणों की आहुति देकर आतंकवादियों को भवन के भीतर जाने से रोका था, और सांसदों की सुरक्षा की थी।13 दिसंबर 2023 की घटना के लिए जिन आठ सुरक्षा अधिकारियों को निलंबित किया गया है, उन्हें बिना वजह बलि का बकरा बनाया गया है, उनका कोई कसूर नहीं है।

संसद के भीतर सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षाकर्मियों ने रूलबुक के अनुसार ही काम किया। रूलबुक में जूते उतरवाना शामिल नहीं है, तो वे किसी आगन्तुक के जूते उतरवा कर क्यों देखते।हवाई अड्डे पर अगर जूते उतरवाने का नियम है, तो उसका वहां पालन होता है, संसद में अब तक नियम नहीं था।फेल तो आईबी हुई है, जिसे देश के कई कोनों में बन रही साजिश की कोई भनक नहीं लगी।संसद के भीतर और संसद भवन के ईर्दगिर्द भी आईबी के अधिकारी चप्पे चप्पे पर तैनात रहते हैं, उन्हें भी कोई भनक नहीं लगी।दो प्रदर्शनकारी संसद भवन के ठीक गेट तक पहुंच कर प्रदर्शन करने में सफल रहे। 13 दिसंबर 2023 को हुई घटना, 1994 में हुई दोनों घटनाओं से ज्यादा गंभीर है।इस साजिश में एक दर्जन से ज्यादा लोग और कई संगठन शामिल हैं।लोकसभा में कूदने वाले सागर शर्मा और मनोरंजन को तो गिरफ्तार किया ही गया है, संसद के बाहर प्रदर्शन करने वाली नीलम वर्मा और अमोल शिंदे को भी गिरफ्तार किया गया।इसके अलावा चारों तरफ से घिर जाने के बाद साजिशकर्ताओं में से दो ललित झा और महेश ने खुद पुलिस स्टेशन पहुंच कर आत्मसमर्पण कर दिया है। इन सभी ने भगत सिंह फैन क्लब बना रखा था।यह किसी से छिपा नहीं कि शहरी नक्सलियों और कम्युनिस्ट पार्टियों ने युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जगह जगह भगतसिंह फैन क्लब बनाए हुए हैं।इस घटना को बहुत हल्के से नहीं लिया जा सकता।साजिशकर्ताओं में से एक ललित झा के गिरफ्तार होने के बाद यह घटना एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है।इस घटना को पिछले पांच सालों से हो रही घटनाओं के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए। इन सभी छह गिरफ्तार लोगों के तार नागरिकता संशोधन क़ानून के खिलाफ चले आन्दोलन, किसान आन्दोलन और पहलवान आंदोलन से भी जुड़े हैं।कम से कम किसान और नागरिकता आंदोलनों के पीछे नक्सलियों, वामपंथियों, मुस्लिम अलगाववादियों, खालिस्तानियों और मोदी विरोधी उन एनजीओ का हाथ था, जिनकी राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के कारण मोदी सरकार ने विदेशी फंडिंग पर रोक लगा दी थी।ये सभी आन्दोलन मोदी सरकार और भाजपा को निशाना बना कर चलाए गए थे।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 1978 में कांग्रेस के दो कार्यकर्ताओं भोलानाथ पांडे और देवेन्द्र पांडे ने इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ विमान अपहरण किया था।इन दोनों को बाद में इंदिरा गांधी ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का टिकट दिया, दोनों जीतकर विधायक बने थे।जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाने वाले कन्हैया कुमार को सीपीआई ने लोकसभा टिकट दिया, और अब वह कांग्रेस की कार्यसमिति का सदस्य है। लोकसभा में कूदने और संसद के बाहर प्रदर्शन करने वालों और साजिश रचने वालों की वामपंथी और कांग्रेसी पृष्ठभूमि सामने आ रही है।हम जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में वामपंथियों के राजनीतिक पराभव के बाद हिंसा में विश्वास करने वाले अनेक वामपंथी तृणमूल कांग्रेस में घुस चुके हैं।नीलम वर्मा के कांग्रेसी और ललित झा के तृणमूल कनेक्शन के सबूत सामने आ गए हैं।

आगे चल कर जांच में पता चलेगा कि साजिश में जेएनयू के नक्सल समर्थक छात्रों, भारत विरोधी एनजीओ और खालिस्तानियों की कितनी भूमिका है, लेकिन इन सभी के लिंक से इंकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने 13 दिसंबर को संसद पर हमले की धमकी दी थी।गुरपतवंत सिंह पन्नू और भारत के खिलाफ काम करने वाले एनजीओ के पीछे अमेरिका और कनाडा का हाथ भी किसी से छिपा नहीं है। क्या कारण है कि विपक्षी दलों ने बिना समय गंवाए संसद की सुरक्षा में हुई चूक को राजनीतिक मुद्दा बना लिया? उन्हें जांच का इन्तजार करना चाहिए, लेकिन सरकार का रवैया भी ठीक नहीं है।सरकार भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती, लेकिन सरकार ने सारी जिम्मेदारी लोकसभा स्पीकर पर डाल कर अपने हाथ झाड़ लिए हैं।जबकि विपक्ष ने इसे देश की सुरक्षा का मुद्दा बनाते हुए गृहमंत्री अमित शाह से सदन में बयान की मांग की है।

घटना के अगले दिन 14 दिसंबर को लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने अपनी मांग के पक्ष में हंगामा करने वाले विपक्ष के 15 सांसदों को निलंबित कर दिया।क्या लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति इतने कमजोर हैं कि वे सरकार को बयान देने की हिदायत नहीं दे सकते थे? सदनों के सभापतियों का काम सरकार का सुरक्षा कवच बनना नहीं है, इन दोनों सभापतियों की जिम्मेदारी सांसदों के अधिकारों की सुरक्षा करना है।सदनों के सभापति सरकार और सांसदों में कड़ी का काम करते हैं। भैरोंसिंह शेखावत 2002 से 2007 तक देश के उपराष्ट्रपति थे।उन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों की सरकारों के समय राज्यसभा के सभापति की भूमिका निभाई थी।भाजपा सरकार के समय वह सदन के भीतर मंत्रियों को सवालों के कटघरे में खड़े करते भी देखे जाते थे, और कांग्रेस सरकार के समय सरकार और विपक्ष में कड़ी का काम करते हुए भी देखे जाते थे।

लोकसभा में कूदने वाले सागर शर्मा और मनोरंजन को जिस तरह सभी दलों के सांसदों ने एकजुट होकर घेरा और पकड़ कर धुनाई की, क्या वैसी ही एकता का प्रदर्शन उन्हें इस घटना के बाद नहीं करना चाहिए था।इस घटना के बाद तुच्छ राजनीति शुरू हो गई।जो कुछ हुआ है, वह सांसदों के सामने हुआ है, सांसदों ने ही उन्हें पकड़ कर सुरक्षाकर्मियों के हवाले किया है। इसलिए संसद में इसे राजनीतिक मुद्दा बना कर हंगामा करने की बजाए सुरक्षा एजेंसियों को जांच करने देनी चाहिए।क्योंकि एफआईआर दर्ज होने के बाद अब यह मामला सदन के भीतर का नहीं रहा।इसलिए सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि जांच रिपोर्ट सदन में रखने का आश्वासन देकर राजनीतिक मुद्दा न बनने दे।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

योगचूडामण्युपनिषद् (भाग-14)

गतांक से आगे...

एकान्त स्थान में पद्मासन लगाकर कमर से सिर तक शरीर को सीधा करके नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि को जमाकर अव्यय प्रणव (?) का जप करना चाहिए। निरंजन, निर्विकल्प, नामरहित, शुद्ध, बुद्ध, नित्य, अनादिनिधन (शाश्वत), एक तुरीय, भूत, भविष्यत् वर्तमान में एक रस रहने वाले परब्रह्म से स्वयं प्रकाशरूपी पराशक्ति प्रकट हुई। आत्मा (परमात्मा) से आकाश प्रकट हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी प्रकट हुई। सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा ये पाँच देवता इन पाँच महाभूतों के पाँच स्वामी हैं। इसमें ब्रह्माजी उत्पत्ति करने वाले, विष्णु पालन करने वाले तथा रुद्र संहार करने वाले हैं।

सतोगुणरूप विष्णु, रजोगुणरूप ब्रह्मा, तमोगुणरूप रुद्र हैं। देवताओं में पहले ब्रह्माजी की उत्पत्ति हुई। सृष्टि की उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा, सृष्टि के पालन अर्थात् विकास करने के लिए विष्णु, सृष्टि के विनाश के लिए रुद्र, भोगों के लिए इन्द्र की उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई।

लोक, देव, तिर्यक, नर और स्थावर इन सबकी उत्पत्ति ब्रह्माजी के द्वारा हुई। उनमें मनुष्य आदि का शरीर पंचभूतों के संयोग से बनता है। ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, ज्ञान के विषय प्राण आदि पंच वायु, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार (अपेक्षाकृत) स्थूल रचना होने से (इनके मूल कारण को) स्थूल प्रकृति कहा जाता है।

कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, ज्ञान के विषय (शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध), पंचवायु, मन और बुद्धि को सूक्ष्म (लिंग) शरीर कहा जाता है। कारण शरीर तीन गुणों से युक्त है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण ये तीन शरीर सबके होते हैं। जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय चार अवस्थाएँ होती हैं, तैजस, प्राज्ञ, विश्व और आत्मा ये चार पुरुष इन सब (अवस्थाओं) के अधिपति हैं।

क्रमशः ...

बालासाहब देवरस

शिव कुमार सिंग

मधुकर दत्तात्रेय देवरस का प्रचलित नाम बालासाहब देवरस था। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तीसरे सरसंघचालक (1973-1994) थे। उनका जन्म 11 दिसंबर 1915 को नागपुर में हुआ, लेकिन उनका पैतृक गांव मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले का कारंजा था। उनके पिता नागपुर में एक सरकारी कर्मचारी थे। उनके छोटे भाई भाऊराव देवरस भी आजीवन संघ के प्रचारक रहे और उन्होंने संघ के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

साल 1927 में बालासाहब देवरस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गये थे। वह स्वयंसेवकों के उस पहले समूह में शामिल थे, जिन्होंने डॉ. हेडगेवार द्वारा नागपुर के मोहिते बाड़ा में शुरू की गयी संघ की पहली शाखा में हिस्सा लिया था।

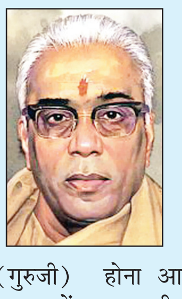

दो बार राज्यसभा सांसद रहे भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक दत्तोपंत ठेंगड़ी के अनुसार बालासाहब के व्यवहार तथा नेतृत्व क्षमता को देखते हुए संघ के दूसरे सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर (गुरुजी) स्वयंसेवकों से कहा करते थे कि आपमें से जिन लोगों ने संघ के संस्थापक डॉ. हेडगेवार को नहीं देखा, उन्हें बालासाहब को देखना चाहिए। आपको इनमें डॉ. हेडगेवार दिखेंगे। गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि बालासाहब देवरस के कारण ही मैं सरसंघचालक कहलाता हूं।

साल 1937 में बी.ए. एल.एल.बी. की पढ़ाई के बाद बालासाहब देवरस नागपुर के नगर कार्यवाह बने। 1939 में उन्हें प्रचारक बनाकर कलकत्ता भेजा गया, लेकिन 1940 डॉ. हेडगेवार के निधन के बाद उन्हें वापस नागपुर बुला लिया गया और नागपुर का प्रांत प्रचारक बनाया गया। क्योंकि, पूरे देश में संघ के कार्य में विस्तार के लिए नागपुर केंद्र का मजबूत होना आवश्यक था, इसलिए संघ के तत्कालीन सरसंघचालक गोलवलकर ने बालासाहब को नागपुर की ही जिम्मेदारी सौंपी। देवरस 1962 में सह-सरकार्यवाह, 1965 में सरकार्यवाह और गोलवलकर के निधन के बाद 1973 में संघ के सरसंघचालक बने। बालासाहब के सरसंघचालक काल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर कांग्रेस सरकार द्वारा दो बार प्रतिबंध भी लगाया गया। पहली बार, आपातकाल के दौरान 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार ने संघ पर प्रतिबंध लगाया, जो मार्च 1977 में इंदिरा गांधी के चुनाव में हार जाने के बाद हटा लिया गया। दूसरी बार, अयोध्या में बाबरी ढांचे को गिराए जाने के बाद 10 दिसंबर 1992 को केंद्र की नरसिम्हा राव सरकार ने संघ पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसे छह महीनों के अंदर ही हटाना पड़ा। साल 1973 में बालासाहब देवरस संघ के सरसंघचालक बने। दो साल बाद ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आपातकाल लगा दिया। 30 जून को देवरस को गिरफ्तार करके पुणे की यरवदा जेल भेज दिया गया। इसके साथ ही, इंदिरा गांधी की सरकार ने 4 जुलाई को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसे 1977 में हटा दिया गया। 21 मार्च 1977 को आपातकाल के खात्मे के बाद बालासाहब जेल से बाहर आए।

विपक्ष की गोलबंदी सही रही तो दिलचस्प होंगे लोकसभा चुनाव

विनोद अग्निहोत्री

लोकसभा चुनावों में अब महज चार महीने का वक्त है। संभावित चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक मार्च के अंतिम या अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आचार संहिता लग सकती है। इस चुनावी महाभारत के लिए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के पास अब उत्तर भारत के तीन राज्यों की हाल ही में हुई जीत का मनोबल, अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन और जनवरी में होने वाले अयोध्या में राम मंदिर के लोकार्पण से बने माहौल का आभा मंडल है।

इन तीन अभेद अस्त्रों के साथ भाजपा प्रधानमंत्री मोदी का करिश्माई नेतृत्व, गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की कड़ी मेहनत, सत्ता तंत्र के लाभ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पित स्वयंसेवकों की फौज और पार्टी कार्यकर्ताओं का बल भी है। उधर तीन राज्यों की पराजय से शिकस्त कांग्रेस, आपसी तूतू-मैं मैं और स्वार्थी अहंकारों में उलझे इंडिया गठबंधन के घटक दल और उसके नेता जो अभी तक न न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय कर पाए हैं और न ही लोकसभा सीटों का बंटवारा कर पाये हैं। क्या ऐसे विपक्ष से ये उम्मीद की जा सकती है कि वो इस तरह 2024 के लोकसभा चुनावों में मोदी और उनकी भाजपा को चुनौती दे पाएगा। यह एक अहम सवाल है, जिसका जवाब फिलहाल अभी बहुत आशावादी नहीं है। लेकिन बनारस में इसी महीने होने वाली जद(यू) की रैली जिसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित इंडिया गठबंधन के कई नेता संबोधित करेंगे।

अटकलें हैं कि नीतीश उत्तर प्रदेश की फूलपुर, मिर्जापुर या किसी और लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ सकते हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश और अखिलेश मिलकर उत्तर प्रदेश में अखिलेश के पीडीए समीकरण (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) बनाकर भाजपा को चुनौती देंगे। पिछड़ों में भी इस समूह की दो प्रभावशाली जातियों यादव और कुर्मी और मुस्लिमों को साथ लेकर

इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में काफी उम्मीदें जता रहा है। जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल के साथ आ जाने से यह सामाजिक समीकरण और ज्यादा मजबूत होने की संभावना हो जाती है। लेकिन याद रखना चाहिए उत्तर प्रदेश में मोदी-योगी के रूप में भाजपा का असली डबल इंजन है। अयोध्या, मथुरा काशी भी यहीं है और संघ परिवार के हिंदुत्व की सबसे बड़ी रणभूमि भी यही राज्य है। इसलिए यहां पिछले दोनों लोकसभा चुनावों में भाजपा ने जबर्दस्त कामयाबी हासिल की थी। इसलिए यहां मुकाबला आसान नहीं है।

उत्तर भारत के तीन प्रमुख राज्यों मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जबर्दस्त जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह तीनों राज्यों में एकदम नए चेहरों को मुख्यमंत्री बनाकर न सिर्फ सबको चौंकाया बल्कि इन राज्यों में नया नेतृत्व विकसित करने और लोकसभा चुनावों के मद्देनजर सामाजिक एवं जातीय समीकरण साधने की कवायद भी की है। मध्यप्रदेश में मोहन यादव को कमान देकर भाजपा ने जहां एक तरफ जहां लंबे समय तक चले शिवराज सिंह चौहान युग की समाप्ति की घोषणा की है, वहीं दूसरी तरफ मध्यप्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश और बिहार की बड़ी यादव आबादी जो अभी तक भाजपा की पहुंच से बाहर है, को भी साथ आने का संदेश दे दिया है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी विष्णु नारायण साय और राजस्थान में पहली बार विधायक बने ब्राह्मण नेता भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने देश के आदिवासियों और अपने बेहद ठोस जनाधार ब्राह्मणों को भी खुश कर दिया है। मध्यप्रदेश में विंध्य के कद्दावर ब्राह्मण नेता राजेंद्र शुक्ल और राज्य के दलित नेता जगदीश देवड़ा को उपमुख्यमंत्री बनाकर पिछड़ों के साथ साथ ब्राह्मण और दलित समुदाय को भी संतुष्ट किया गया है। राजस्थान में जयपुर राजघराने की राजकुमारी दीया कुमारी और प्रेमचंद बेवरा को उपमुख्यमंत्री बनाकर यहां भी राजपूत और दलित समुदाय को सकारात्मक संदेश दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी पिछड़े समाज के अरुण साओ और ब्राह्मण विजय शर्मा को उपमुख्यमंत्री बनाकर यहां भी इन दोनों मजबूत समाजों को साथ जोड़े रखने की कवायद की गई है।

अपनी इस किलेबंदी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातीय जनगणना और पिछड़ों को उनकी आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी देने के राहुल गांधी के नारे की काट करना चाहते हैं, जिसे इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनावों के लिए अपना ब्रह्मास्त्र मानता है। इसके साथ ही अनुच्छेद 370 पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को भी भाजपा लोकसभा चुनावों में भुनाएगी। लेकिन इस फैसले में अदालत ने यह भी कहा कि जिस दिन जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ था, उसी दिन से वह भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और उसकी कोई स्वायत्ता या संप्रभुता नहीं रह गई थी। अदालत के इस कथन से भाजपा और उनके समर्थकों के इस कथन कि अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के बाद ही जम्मू कश्मीर का भारत में वास्तविक विलय हुआ, को निराधार कर दिया है।

अब सवाल है कि विपक्षी इंडिया गठबंधन कैसे अब लोकसभा चुनावों में भाजपा का मुकाबला कर पाएगा। प्रथम दृष्टया लगता है कि विपक्ष के हाथ से बाजी निकल गई है। लेकिन इतिहास बताता है कि चुनाव से ठीक पहले विधानसभा चुनावों की जीत हमेशा लोकसभा चुनावों में जीत की गारंटी नहीं होती। 2003 में मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव जीतने वाली भाजपा 2004 का लोकसभा चुनाव हार गई। 2008 में भी भाजपा ने यह मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ जीते लेकिन राजस्थान हार गई और 2009 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने ज्यादा सीटें लेकर फिर यूपीए की सरकार बनाई। परंतु 2013 में भाजपा तीनों राज्य जीती और 2014 में लोकसभा चुनावों में भी उसे शानदार जीत मिली। जबकि 2018 में इन्हीं तीनों राज्यों में कांग्रेस जीती लेकिन 2019 का लोकसभा चुनाव हार गई।

इसके पहले भी 1998 में कांग्रेस ने मध्यप्रदेश, राजस्थान, दिल्ली में जीत दर्ज की, लेकिन लोकसभा चुनावों में भाजपा से हार गई। इसलिए विधानसभा चुनावों जैसे नतीजे ही लोकसभा चुनावों में भी होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यही एक उम्मीद है जो कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों को फिर मैदान में डटने की प्रेरणा दे रही है। 19 दिसंबर को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या विपक्षी दल 400 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर भाजपा और एनडीए के मुकाबले इंडिया का एक सर्वसम्मत उम्मीदवार देने के लिए सीट बंटवारे का कोई सर्वमान्य फॉर्मूला निकाल पाएंगे और क्या कोई न्यूनतम साझा कार्यक्रम बना पाएंगे। क्या इंडिया गठबंधन किसी नेता को अपना संयोजक बना सकेगी। क्या विधानसभा चुनावों के दौरान पैदा हुई, उनकी तल्खी इस बैठक के बाद खत्म हो जाएगी। क्या संयुक्त प्रचार की कोई रणनीति बनेगी। क्या मोदी के मुकाबले कोई सर्वमान्य चेहरा तय हो सकेगा या मोदी बनाम मुद्दों पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा।

इन सारे सवालों के जवाब में ही 2024 के लोकसभा चुनावों में विपक्षी गठबंधन की संभावनाओं की कुंजी है। अगर इंडिया गठबंधन ने इन सवालों को सही तरीके से सुलझा लिया, तो निश्चित रूप से लोकसभा चुनावों में वह नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व और मजबूत भाजपानीत एनडीए गठबंधन को चुनौती दे सकेगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत को कोई नहीं रोक सकेगा और विपक्ष महज चुनावी मुकाबले की औपचारिकता पूरी करते हुए इसी तरह संसद में दिखाई देगा जैसे कि अभी दिखता है। विपक्ष के मुकाबले में आने की सबसे पहली और सबसे बड़ी शर्त है कि कांग्रेस अपने घर को दुरुस्त करे, क्योंकि जिन तीन राज्यों में भाजपा जीती है, वहां कांग्रेस का ही मुकाबला उसके साथ लोकसभा चुनावों में भी मुकाबला होगा।

आज का इतिहास

1949 बर्मा (अब म्यांमार) ने साम्यवादी चीन को मान्यता दी।

1951 नागरिक अधिकार कांग्रेस, एक अमेरिकी नागरिक अधिकार समूह, ने संयुक्त राष्ट्र नरसंहार कन्वेंशन के लिए एक दस्तावेज प्रस्तुत किया जो अफ्रीकी अमेरिकियों के खिलाफ नरसंहार के साथ संयुक्त राज्य सरकार को चार्ज करता है।

1960 ईंधन के दूषित होने के कारण डाउनटाउन म्यूनिख में कुछ ही समय बाद अमेरिकी वायु सेना का एक समझौता सी -131 समरिटन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे सभी 20 लोगों की मौत हो गई और साथ ही जमीन पर 32 और घायल हो गए।

1970 सैनिकों ने मेमोरियल में काम करने वाले मजदूरों (स्मारक चित्र) पर गोलीबारी की, जो देश भर में सरकार विरोधी क्रूर विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत कर रहा था।

1981 राष्ट्रपति रीगन के आदेश के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में आपातकालीन मोबिलाइजेशन बोर्ड की स्थापना की गई।

1987 मेगा मैन जापान में जारी किया गया।

1989 सिम्पसंस, वर्तमान में सबसे लंबे समय तक चलने वाली अमेरिकी प्राइम टाइमटेन्सेरशिप श्रृंखला है, जिसने फॉक्स टेलीविजन नेटवर्क पर %सिम्पसंस रोस्टिंग ऑन अ ओपन फायर% के साथ अपनी शुरुआत की।

1992 जनरल सुवा को 4.4 मिलियन वर्ष पुराने ऑस्ट्रलोपिथेकस रामिडस के दांत मिले।

1993 केविन स्कॉट स्केट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड 1000 मीटर (1: 12.54)।

1993 टेनिस स्टार बोरिस बेकर (26) ने बारबरा फेल्टस (27) को पछाड़ा।

1998 अमेरिकी और ब्रिटिश बम वर्षकों ने आपरेशन डेजर्ट फ़ाक्स के तहत इराक पर भारी बमबारी की।

2004 राष्ट्रपति बुश 2004 के खुफिया सुधार और आतंकवाद अधिनियम पर हस्ताक्षर करते हैं जो खुफिया एजेंसियों को पुनर्गठित करता है और राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशक की स्थिति बनाता है।

2005 भूटान के राजा जिग सिगमे वांचुक को सत्ता से हटाया गया।

2009 लेबनान के समुद्री तट पर कार्गो जहाज एमवी डैनी एफ टू के डूबने से 40 लोगों तथा 28000 से अधिक पशुओं की मौत हो गयी।

2011 फिलीपींस में, ट्रॉपिकल स्टॉर्म वाशी से बाढ़ की वजह से कम से कम 400 लोगों की मौत हो गई, और अधिक लापता हो गए।

2012 निवर्तमान अमेरिकी सीनेटर जिम डीमिंट को ल्हक्ककांग्रेसी टिम स्कॉट द्वारा बदल दिया गया है, जो 1881 से दक्षिण का पहला अश्वेत सीनेटर है।

समाचार पचीसा
रायपुर, रविवार 17 दिसंबर 2023

3 राज्यों में मुख्यमंत्री के चेहरों के माध्यम से भाजपा ने दिये हैं बड़े राजनीतिक संकेत

मृत्युंजय दीक्षित

पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में तीन प्रमुख राज्यों में भाजपा को अप्रत्याशित विजय मिली। भाजपा ने ये चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लड़ा था और राज्य में किसी भी नेता को मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया था। विपक्ष के लिए ये भी हैरान करने वाली बात थी कि कई सांसदों को भी जिनमें कुछ तो मंत्री थे पार्टी ने विधानसभा का चुनाव लड़ने का आदेश दिया था। कई बड़े चेहरे जीते तो मुख्यमंत्री कौन होगा ? भाजपा की विजय के साथ ही मुख्य धारा और सोशल मीडिया के सूत्र अटकलें लगाने लगे। मुख्यमंत्री चयन की प्रक्रिया में देरी, राजस्थान में वसुंधरा के घर हलचल और मध्य प्रदेश में शिवराज जी की दिल्ली न जाने की घोषणा ने राजनैतिक विश्लेषकों और भविष्यवक्ताओं को काम पर लगा रखा था। मीडिया के सूत्र प्रतिदिन सुबह से शाम तक चार-पांच नाम चलाते और पीछे करते रहते थे। इन्हीं अटकलों के बीच जब भाजपा ने तीनों प्रान्तों के लिए पर्यवेक्षकों की घोषणा की तो मीडिया उसमें भी कथा कहानी ढूँढ़ने लगा किन्तु उनका भी कोई आधार नहीं था।

तीनों राज्यों में बने नये मुख्यमंत्रियों के नाम कहीं भी किसी भी चर्चा में दूर दूर तक नहीं आए थे। उनके विषय में बताने के लिए टीवी चैनल गूगल का सहारा ले रहे थे। विपक्षी खेमे में हड़कंप मचा हुआ है कि बिना किसी गुटबाजी के भाजपा अपने नये चेहरे कैसे चुन रही है। सभी टीवी चैनलों पर कौन बनेगा मुख्यमंत्री पर तरह तरह के विश्लेषण चल रहे थे किंतु अब सभी विश्लेषक हैरान हो गये और यह भी चर्चा करने लग गये कि वो लोग टीवी पर जिस भी चेहरे को आगे कर देते हैं भाजपा में वह चेहरा पीछे छूट जाता है और फिर एकदम नया चेहरा सामने आ जाता है। अब देश के मीडिया जगत के बड़े नामों को यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि वर्तमान समय की भारतीय राजनीति में यदि कोई सबसे बड़ा चुनावी सर्वे करने वाला और राजनीतिक भविष्यावाणी करने व्यक्ति है तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। बेहद विपरीत परिस्थितियों के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व व उनके धुआंधार प्रचार की बदौलत ही भाजपा की तीनों राज्यों में जोरदार वापसी हुई है।

भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले छत्तीसगढ़ में एक बड़े आदिवासी नेता विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाकर चौंकाया और फिर अरूण साव और विजय शर्मा को उपमुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा गया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव करके सभी प्रकार की अटकलों पर विराम लगा दिया गया। आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने का लाभ भाजपा को छत्तीसगढ़ में मिला और वहां की आदिवासी बहुल क्षेत्रों की अधिकांश सीटों पर भाजपा को विजयश्री प्राप्त हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि आदिवासी बहुल राज्य छत्तीसगढ़ में राज्य का गठन होने के बाद से एक आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग की जा रही थी जिसे अब भाजपा ने विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाकर पूरा कर दिया है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आदिवासी हैं और किसान परिवार से हैं। वह कुनकुरी विधानसभा सीट से जीते हैं वहीं वह 1999 से 2014 तक रायगढ़ लोकसभा सीट से सांसद भी रहे। वह पूर्व में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भी रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने जनता से अपील की थी कि आप साय को जितायें तो हम उन्हें बड़ा आदमी बना देंगे। अब साय मुख्यमंत्री बन गये हैं। यदि समग्र दृष्टि डाली जाये तो यह पता चलता है कि बिना किसी चेहरे को आगे किये चुनाव लड़ रही भाजपा ने प्रचार के दौरान ही यह तय कर लिया था कि अगर सरकार बनती है वह राज्य की कमान किसे सौंपेगी। साय का नाम भी किसी टीवी चैनल की डिबेट में नहीं चल रहा था। यहां पर भाजपा ने बिना किसी विशेष तैयारी के चुनाव लड़ा फिर भी शानदार विजय प्राप्त की और चुनावों के बाद रमन सिंह के प्रभाव से मुक्ति भी पा ली है हालांकि भाजपा ने रमन सिंह को दरकिनार नहीं किया है और उन्हें विधानसभा अध्यक्ष जैसा पद देकर उनका सम्मान बनाए रखा है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि साय का परिवार संघ से जुड़ा रहा है। उनके पिता और दादा भी संघ के स्वयंसेवक रहे हैं तथा राम मंदिर आंदोलन के आरंभिक

दिनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मध्य प्रदेश- विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक विजय के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के स्थान पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे उज्जैन दक्षिण के विधायक डॉ. मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर सभी को हैरान कर दिया। मध्य प्रदेश में यह माना जा रहा था कि चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उनके परिश्रम का प्रतिफल दिया जा सकता है और संभवत: वे लोकसभा चुनावों तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ और मामा जी को एक नए चेहरे के लिए अपनी दावेदारी से पीछे हटना ही पड़ा। मध्य प्रदेश में विरोधी प्रचार करने में जुट गये थे कि भाजपा में गुटबाजी के कारण नेता चयन में देरी हो रही है किंतु जब मोहन यादव के नाम का ऐलान हुआ तो सभी लोग हैरान रह गये। उत्तर प्रदेश और बिहार में यादव समाज के बड़े नेता परेशान हैं कि अब आगामी लोकसभा चुनावों में भाजपा एक यादव मुख्यमंत्री के सहारे अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने जा रही है। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं जिसमें पहला यह है कि अब मध्य प्रदेश में बीजेपी को एक नया चेहरा मिल चुका है। विगत चुनावों के दौरान कांग्रेस मामा जी पर भ्रष्टाचार व घोटालों के आरोप लगा रही थी और चुनाव प्रचार के दौरान 40 प्रतिशत कमीशन खाने वाली सरकार कहकर बीजेपी को घेरने का प्रयास कर रही थी अत: अब ऐसे सभी आरोपों से फिलहाल राहत मिल गयी है।

दूसरा भाजपा ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर उत्तर प्रदेश व बिहार के यादव मतदाताओं को साधने का जोरदार प्रयास किया है। राजनैतिक विश्लेषकों का अनुमान है कि मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाये जाने के कारण यूपी में सपा के लिए चुनौती बढ़ने जा रही है। यह बात तो समाजवादी नेता भी मान रहे हैं कि यूपी, बिहार व हरियाणा के यादव मतदाताओं को लुभाने की रणनीति के तहत ही मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में 10-12 प्रशित और बिहार में इनकी संख्या 14.26 प्रतिशत और हरियाणा में 10 प्रतिशत के आसपास है। अभी तक यूपी में अखिलेश यादव और बिहार में लालू यादव ही अपने आपको यादवों का एकमात्र बड़ा नेता घोषित करते आ रहे थे किंतु अब भाजपा के पास भी एक यादव नेता मिल गया है और वह है मोहन यादव। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर व उनके साथ दो उपमुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने राज्य के मतदाताओं के बीच गजब की सोशल इंजीनियरिंग की है। पिछली सरकार में जहां नरोत्तम मिश्रा जो ब्राह्मण चेहरा थे वहीं अब मोहन यादव की सरकार में राजेंद्र शुक्ला ब्राह्मण चेहरा बनकर उभरे हैं। वहीं जगदीश देवड़ा को उपमुख्यमंत्री बनाया गया जबकि पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष बनाये गये हैं।

मोहन यादव काफी पढ़े लिखे हैं और उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से उनका सम्बंध है। जब मोहन के नाम की घोषणा हुई तब उनके ससुराल सुल्तानपुर में भी जश्न मनाया गया। मोहन यादव प्रख्यात संत एवं रामघाट स्थित सीताराम आश्रम के संस्थापक स्वामी आत्मानंददास उर्फ नेपाली बाबा के शिष्य हैं। 2016 में उज्जैन महाकुंभ के दौरान नेपाली बाबा ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया था।

राजस्थान- लंबी बैठकों और तरह-तरह के कयासों के बाद आखिरकार राजस्थान को भी नया चेहरा मिल गया है और वहां भी महारानी वसुधंरा राजे का राज अब समाप्त हो चुका है तथा वहां पर एक ब्राह्मण चेहरे भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने सभी राजनैतिक पंडितों को बुरी तरह से चौंका दिया है और अब वह सभी लोग टीवी चैनलों पर बैठकर केवल अपना सिर खुजला रहे हैं कि आखिर भजन लाल शर्मा का नाम कैसे दौड़ में आ गया और वह पहली बार विधायक बने तथा पहली बार ही राज्य के मुख्यमंत्री बन गये। भजन लाल शर्मा के बारे में कहा जा रहा है कि वह संघ के करीबी हैं और चार बार महामंत्री रहे तथा संगठन में काफी सक्रिय रहे हैं। भजन लाल एक ब्राह्मण चेहरा हैं और बहुत दिनों बाद राजस्थान को एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री मिला है। राजस्थान में करीब 12 प्रतिशत ब्राह्मण आबादी है और संपूर्ण राज्य में फैली है वह एक शांत मतदाता माना जाता रहा है। राजस्थान की राजनीति में अभी तक केवल जाट, गुर्जर, दलित, मीणा आदि को लेकर ही चर्चाएं होती थीं किंतु अब बहुत दिनों बाद भाजपा ने ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाकर सवर्ण समाज को संदेश दे दिया है क्योंकि उत्तर भारत की राजनीति में सवर्ण मतदाता भी एक अहम भूमिका अदा करते हैं। वहीं राजस्थान में दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को उपमुख्यमंत्री बनाया है वहीं वासुदेव देवनानी जो चार बार के विधायक रहे हैं, उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाकर राज्य के सिंधी और मारवाड़ी समाज को भी साधने का सफल प्रयस किया है।

एक प्रकार से यदि देखा जाये तो भाजपा ने तीनों ही राज्यों में एक नया चेहरा देकर दूसरी पीढ़ी के नेताओं को पार्टी की बागडोर सौंपने की शुरुआत कर दी है। भाजपा ने यह भी बता दिया है उनके यहां जो भी कार्यकर्ता शांत रहकर केवल कार्य करता रहेगा, संगठन उन सभी का ध्यान रखता है और कोई भी साधारण से साधारण व्यक्ति ऊंचे पद पर बैठाया जा सकता है। संगठन में अब किसी भी स्तर पर गुटबाजी का दौर नहीं चलने वाला है। टीवी चैनलों पर सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग अपना प्रचार करते रहते थे वह सभी लोग मुख्यमंत्री पद की दौड़ से बाहर हो गये हैं। भाजपा ने जातिवाद की राजनीति को ध्वस्त करने के लिए जोरदार सोशल इंजीनियरिंग की है और विपक्ष हिंदू समाज को बांटने के लिए जातिगत जनगणना की जो रट लगाये था उस पर भी ब्रेक लगाने का सफल प्रयास किया है। भाजपा ने लोकसभा चुनावों के लिए तीन राज्यों में अपनी एकदम नई टीम बना ली है और अब समय आ गया है कि यह टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी गारंटी को पूरा करेगी ओर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे।

शिखर से शून्य की ओर जाता दिख रहा है बसपा का दलित मूवमेंट आंदोलन

अजय कुमार

बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने जैसे ही अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, उसके तुरंत बाद मायावती पर भी वंशवाद की राजनीति करने का आरोप लगने लगा है। उनसे पूछा जा रहा है कि मान्यवर कांशीराम के साथ दलित मूवमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बसपा नेताओं को बहन जी ने क्या इसी दिन के लिए बाहर का रास्ता दिखाया था, ताकि उनके भतीजे के लिए राजनीति का रास्ता सुगम हो सके? हाल ही में मायावती ने अपने सांसद दानिश अली को भी पार्टी से निलंबित कर दिया है, जो इस समय काफी तेजी के साथ बसपा में अपनी पकड़ बना रहे थे। यह और बात है कि इतना सब होने के बाद भी मायावती ने सार्वजनिक मंच से उत्तराधिकारी घोषित करने की पार्टी की परंपरा को कायम रखा। करीब ढाई दशक पहले मान्यवर कांशीराम ने भी इसी तरह मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। उन्होंने भी लखनऊ में एक सभा में मंच से इसका ऐलान किया था। उस समय खासी राजनीतिक हलचल मची थी। कांशीराम के फैसले पर सवाल उठाए गए थे। लेकिन, कांशीराम ने मायावती की प्रतिभा का आकलन करने के बाद उन्हें यह पद देने का ऐलान किया था। इस घोषणा के करीब 6 साल बाद वर्ष 2007 में उत्तर प्रदेश में मायावती पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हुई थीं, लेकिन मायावती के फैसले ने यूपी की सियासी गर्मी को बढ़ा दिया है। क्योंकि उन्होंने बसपा के किसी नंबर दो के दमदार नेता की बजाय भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित करना ज्यादा उचित समझा। यही परंपरा मान्यवर कांशीराम निभाते तो आज मायावती बसपा सुप्रीमो नहीं हो पातीं बल्कि उनकी जगह कांशीराम के परिवार का कोई सदस्य इस कुर्सी पर बैठा होता और हो सकता है वही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी होता। हालांकि, मायावती ने बसपा में उत्तराधिकारी घोषित करने की जो पुरानी परंपरा पुरानी है, उसे जीवित जरूर रखा, लेकिन मायावती और मान्यवर कांशीराम के फैसले में जमीन आसमान का अंतर है। यदि ऐसा ना होता तो आज मायावती के भतीजे की जगह कोई और नेता मायावती की सियासी विरासत का उत्तराधिकारी होता। अभी तक मायावती के भतीजे आकाश आनंद सियासत में कुछ ऐसा नहीं कर पाए हैं, जिसके आधार पर उनकी राजनीतिक कुशलता का एहसास किसी को हुआ हो। गौरतलब है कि मायावती को मान्यवर कांशीराम जब राजनीति में लाए थे तो उसे समय वह आईएएस की तैयारी कर रहीं थीं। उसी दौरान दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में मायावती को बड़े नेताओं के बीच बोलने का मौका मिला। उन्होंने तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री राज नारायण पर हमला बोला। राजनारायण दलितों को हरिजन कहकर संबोधित कर रहे थे। मायावती ने कहा कि आप हमें हरिजन कहकर अपमानित कर रहे हैं। कांशीराम ने जब यह बात सुनी तो वह मायावती के घर पहुंच गए। कांशीराम ने आईएएस बनने की बजाय राजनीति में आने के लिए मायावती को प्रेरित किया। कांशीराम ने मायावती को समझाया कि अगर वह राजनीति में सफल हो जाती हैं तो दर्जनों आईएएस अधिकारी उनके नीचे काम करेंगे। मायावती दलितों के उत्थान के लिए चल रहे संघर्ष के दौर में कांशीराम के साथ जुड़ीं थीं। मायावती 1984 में बसपा का गठन होने के बाद उसमें शामिल हुईं और उसी साल पहला लोकसभा चुनाव कैराना से लड़ा। पहली बार 1989 में वह सांसद बनीं। इसके बाद वह चार बार यूपी की मुख्यमंत्री भी रहीं। मान्यवर कांशीराम ने 15 दिसंबर 2001 को मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। लखनऊ में एक सभा में कांशीराम ने कहा कि मैं काफी समय से यूपी कम आ पा रहा हूं। लेकिन खुशी की बात यह है कि मेरी इस गैरहाजिरी को कुमारी मायावती ने मुझे महसूस नहीं होने दिया। यह कहकर उन्होंने मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया।

नई पौध के जरिए भाजपा के दिग्गज दरकिनार

निरंजन परिहार

चाणक्य नीति से लेकर राजनीतिक विज्ञान तक सब में सत्ता के संदर्भ में केवल एकसमान विचार चलता है और उन सबका सार भी केवल एक ही है। सार यह कि सत्ता के लिए सर उठानेवालों के आसपास के या करीबी किसी बेहद कमजोर को ही सर्वाधिक सामर्थ्यवान बना दो, ताकि ताकतवर लोगों के वे सभी रास्ते ही बंद हो जाएं, जिनके जरिये वे सत्तासीन होने के प्रयास कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी बीजेपी ने राजस्थान में भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने के साथ ही वसुंधरा राजे के पर कतर कर यही संदेश दिया है। वसुंधरा ही क्यों, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ में डॉ. रमण सिंह के साथ भी यही हुआ साफ लगता है। तीनों प्रदेशों के इन सर्वाधिक शक्तिशाली नेताओं के सामने कभी खड़े तक न हो पाने की क्षमतावाले लोगों को ही मुख्यमंत्री बना दिया है, ताकि नई पौध तैयार हो सके, पुरानों के बोझ से मुक्ति मिल जाए और सामान्य कार्यकर्ता को सदा यह लगता रहे कि उनके लिए भी कभी सत्ता के दरवाजे खुल सकते हैं। भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री देख राजस्थान के बीजेपी कार्यकर्ता यही कह रहे हैं।

राजस्थान में भजनलाल शर्मा का चयन पार्टी कैडर को मजबूत करने और संघ परिवार के वैचारिक प्रवाह को संगठित बनाए रखने के लिए किया गया निर्णय बताया जा रहा है। हालांकि वे उस ब्राह्मण समुदाय से हैं, जिसके बारे में बीजेपी के लिए कभी कहा जाता था है कि यह तो ब्राह्मण-बनियों की पार्टी है। लेकिन अब ये टैग हट गया है। शर्मा ने तीन राष्ट्रीय अध्यक्षों राजनाथ सिंह, अमित शाह व जेपी नड्डा के कार्यकाल में चार प्रदेश अध्यक्षों के साथ प्रदेश में काम किया है। अमित शाह और जेपी नड्डा उनके काम से प्रभावित रहे हैं और संघ के विचार पर अचल रहने के कारण आरएसएस भी उनको पसंद करता है। भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने की खास वजह ये भी है कि बहुत जूनियर और साथ ही विनम्र होने के कारण वे अपने वरिष्ठ नेताओं से वसुंधरा राजे की तरह न तो सर उठाकर बात कर सकते

हैं और न ही आंख दिखा सकते हैं। वसुंधरा वैसे भी न तो केंद्रीय नेताओं की पसंद थी और न ही संघ परिवार की। वे केवल विधायकों के समर्थन बल की पुरानी परंपरा के जरिए मुख्यमंत्री बनना चाहती थी, लेकिन मोदी और बीजेपी ने अब वह परंपरा ही पलट दी है। मुख्यमंत्री के रूप में शर्मा के चयन पर राजनीतिक जानकारों की राय में माना यही जा रही है कि राजस्थान में बीजेपी का यह फैसला भाजपा की पुरानी पीढ़ी के नेताओं से बचने की कोशिश तो है ही, वसुंधरा राजे के दो बार के मुख्यमंत्रीकाल के बैकलॉग से निजात पाने का प्रयास भी है। भजनलाल शर्मा एक बिल्कुल नया चेहरा हैं और एक उच्च जाति के नेता के रूप में फिट भी बैठते हैं। सबसे खास बात यह भी है कि वसुंधरा राजे की तरह से न तो वे सत्ता के अहंकार से ग्रस्त हैं और न ही विधायकों के समर्थन से लॉबिंग कर सकते हैं। बीजेपी ने भजनलाल शर्मा के जरिए अपनी मुख्यमंत्री की पसंद से यह भी बताने की कोशिश की है कि वह 2024 के चुनावों से पहले किसी भी तरह की गुटबाजी बर्दाश्त नहीं करेगी। फिर भी नए मुख्यमंत्रियों की तरफ से यदि ऐसा हुआ, तो सत्ता का अहंकार उनको छुए, उससे पहले ही सत्ताच्युत भी बेहद आसानी से किया जा सकता है। राजस्थान बीजेपी के एक बड़े नेता ने कहा कि पार्टी आलाकमान ने भजनलाल शर्मा के नाम पर निर्णय लेने से पहले कई पहलुओं पर गहन समीक्षा जरूर की होगी। इसमें सबसे प्रमुख तो यही हो सकता है कि वरिष्ठ नेतृत्व किसी भी नेता की ताकत दिखाने की कोशिश को पसंद नहीं करता इसीलिए चुनाव जीतने के बाद विधायकों का भले ही वसुंधरा राजे से लगातार मिलना हुआ और उनके समर्थकों की संख्या 70 के आसपास बताई जाती रही, लेकिन इस संख्याबल को दिखाकर ताकत पाने की कोशिश को केंद्र ने साफ नजरंदाज किया। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने फ़िलहाल पत्ते नहीं खोले हैं कि आखि़र पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लिए पार्टी का प्लान क्या हैं। 70 साल की वसुंधरा अपने प्रदेश की सर्वाधिक लोकप्रिय नेता अब भी हैं और भजनलाल शर्मा को उनकी बराबरी का कद पाने में लंबा वक्त लगेगा, मगर वे कभी भी वसुंधरा राजे जितना बड़ा राजनीतिक कद पा ही नहीं सकते क्योंकि वे चीजें जो कद को पद से भी बड़ा बना देती हैं, वे भजनलाल शर्मा में हैं ही नहीं। बहुत संभव है कि बीजेपी आलाकमान ने उनकी इस तासीर को भी भली भांति भांप लिया हो।

भजनलाल शर्मा की तरह ही मोहन यादव और विष्णुदेव साय का मुख्यमंत्री के रूप में चुना जाना कई लोगों के लिए निश्चित तौर से आश्चर्य की बात है। भले ही बीजेपी की धाराओं के जानकारों का कहना है कि 2024 के आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने ये रणनीतिक कदम उठाया है। जबकि कई लोग बीजेपी की पसंद से आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि इनमें से किसी भी मुख्यमंत्री में बड़े पैमाने पर वोट दिलाने की क्षमता नहीं है। फिर भी हवाला तो जाति, समाज, वर्ग का दिया जा रहा है। हालांकि जाति, समाज, वर्ग और सामुदायिक संबद्धता के आधार पर नेताओं को चुनने की प्रथा बीजेपी में नई नहीं है, लेकिन वर्तमान चयन विभिन्न समुदायों और जातियों के व्यापक क्षेत्रीय आधार की दिशा में एक रणनीतिक कदम हो सकते हैं। भजनलाल शर्मा सहित मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के नव नियुक्त तीनों मुख्यमंत्रियों का अगला लक्ष्य अगले साल होने वाले चुनाव में अपने-अपने प्रदेशों की सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत सुनिश्चित करना है।

अचर्चित चेहरों के हाथ कमान सौंपने के जोखिम में निहित संदेश

अजय बोकिल

भारतीय जनता पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व ने हिंदी पट्टी के तीन राज्यों में भारी जीत के बाद जिन अचर्चित चेहरों के हाथों में सत्ता की कमान सौंपी है, उससे 'चौंकना' शब्द भी फीका लगने लगा है। यह कुछ वैसा ही था कि कोई जादूगर अपनी जेब में हाथ डाले और नोट किसी भीड़ में छिपे शख्स की जेब से निकले।

मोदी- शाह ने मीडिया के तमाम अटकल मीटरों को बेकार साबित कर दिया है। लेकिन इन अप्रत्याशित फैसलों के भीतर कई राजनीतिक संदेश छुपे हैं, जो भाजपा के स्वयंभू नेताओं के लिए तो हैं ही, उन विपक्षी नेताओं के लिए भी हैं, जो मात्र सीट बंटवारे और वोटों के कागजी गणित के भरोसे आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी को पटखनी देने का अरमान पाले हुए हैं।

विधानसभा चुनावों में भाजपा के जीते हुए मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्यों में 'कौन बनेगा मुख्यमंत्री' की रेस असली हार्स रेस से भी ज्यादा रोमांचक होने लगी थी। दावेदारी और राजयोग में अदृश्य मुकाबला चल रहा था। मीडिया की आंखें और राजनीतिक भविष्यवाणियां उन्हीं चंद चेहरों के आसपास मंडरा रही थीं, जिन्हें परंपरागत रूप से कुर्सी की दौड़ में प्रथम पंक्ति में माना जाता रहा था। ऐसे कुछ नाम जो सीएम या फिर वो भी नहीं तो कम से कम डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के लिए नए सूट सिलवा चुके थे। लेकिन हाय री किस्मत! अब टीम में बारहवें खिलाड़ी की भूमिका के भी लाले हैं।

भाजपा आलाकमान ने इन फैसलों से छह संदेश दिए हैं। पहला तो कोई खुद को पार्टी से ऊपर न समझे, दूसरा भाजपा में संघ अभी भी पूरी तरह ताकतवर है, तीसरा भाजपा में कोई साधारण कार्यकर्ता भी शीर्ष पद तक पहुंच सकता है, चौथा भाजपा ने आने वाले 15 साल तक राजनीति करने वाले नए खून की फौज तैयार कर दी है, पांचवां सोशल इंजीनियरिंग में भाजपा सभी राजनीतिक दलो से मीलों आगे है और छठा, इस बदलाव के जरिए भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव की जमीन भी तैयार कर दी है और तकरीबन मुद्दे भी तय कर दिए हैं।

मप्र में डा. मोहन यादव, छग में विष्णुदेव साय और राजस्थान में भजनलाल शर्मा बाकी दुनिया के लिए भले ही अचर्चित चेहरे रहे हों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा को उनकी कार्यक्षमता पर भरोसा है। अब यह इन तीनो पर है कि मिले हुए अवसर को कामयाबी में वो कितना बदल पाते हैं।

खुद को कितना साबित कर पाते हैं। हालांकि यह जोखिम तो हर उस प्रयोग में रहता है, जो राजनीति की प्रयोगशाला में पहली बार किया जाता है। मप्र में जब पहली बार शिवराज को मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी गई थी तब कई लोगों ने उनकी नेतृत्व क्षमता और देसी छवि पर तंज कसा था, लेकिन वक्त के साथ शिवराज ने खुद कोन सिर्फ साबित किया बल्कि अपरिहार्य बन गए। उन्होंने अपनी राजनीति की नई इबारत लिखी। इमोशनल पॉलिटिक्स का नया सिलेबस तय किया और पूरे 18 साल तक सीएम पद पर जमे रहे।

हालांकि, पहली पारी के सीएम शिवराज और चौथी पारी के सीएम शिवराज में काफी अंतर था। उनका अपना आभा मंडल और काकस तैयार हो गया था। इस दौरान उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को भी

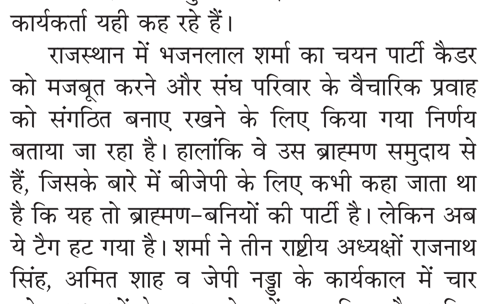

यथासंभव किनारे लगाया और शायद इसकी इंतिहा हो चुकी थी।

यही स्थिति राजस्थान में वसुंधरा राजे की थी। राजे तो पहले से राज परिवार से हैं। लिहाजा कुर्सी पर विराजना उनके लिए नैसर्गिक अधिकार था। उन्होंने खुद को पार्टी और राज्य का भाग्य विधाता मान लिया था। अलबत्ता छग के 15 साल सीएम रहे और बाद में भाजपा में ही हाशिए पर डाल दिए गए डॉ रमनसिंह ने खुली बगावत के रास्ते पर जाने से खुद को बचाया और कुछ बेहतर पाने की आस जिंदा रखी।

कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा में इस तरह क्षत्रप संस्कृति को समाप्त पर 'एक हाईकमान कल्चर' को लागू कर भाजपा ने बहुत बड़ा जोखिम लिया है, जो भविष्य में आत्मघाती भी हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के चेहरे पर ही पार्टी का पूरी तरह आश्रित हो जाना संगठन की आंतरिक कमजोरी को दर्शाता है। यानी जब मोदी भी नहीं रहेंगे, तब क्या होगा?

क्या क्षत्रपो के खंभों के बिना पार्टी का तंत्र चरमरा नहीं जाएगा? यह सवाल वाजिब है, लेकिन राजनीतिक दलों में समय रहते नए खून का संचार और उसके दिल दिमाग तक पहुंचाने की प्रक्रिया अगर कुंद हो जाती है तो उन दलों का हाल काफी हद तक कांग्रेस और वामपंथी दलों जैसा हो जाता है। कौन सोच सकता था कि पश्चिम बंगाल में 35 बरसों तक एकछत्र शासन करने के बाद आज बंगाल में माकपा को एक एक सीट के लिए भी कांग्रेस के कंधों की जरूरत पड़ रही है।

त्रिपुरा में वह हाशिए पर चली गई है। राजस्थान और मप्र में कांग्रेस में सत्ता में रहते नए और पुराने खून के बीच खुली लड़ाई हुई और लेकिन कोई सकारात्मक फैसला नहीं हो सका। मप्र में अभी भी कमलनाथ हार की नैतिक जिम्मेदारी लेकर प्रदेश कांग्रेस पद से इस्तीफा देना तो दूर नैतिक आधार पर ऐसा करने की पेशकश करने की भी नहीं सोच रहे हैं। विस चुनाव नतीजों में कांग्रेस की करारी हार के बाद उनके इस्तीफे ही अफवाह उड़ी थी, जिसका तुरंत खंडन कर दिया गया। अब शायद लोकसभा चुनावों के नतीजों का इंतजार किया जा रहा है।

कहने का आशय यही कि जोखिम उठाकर भी भाजपा और संघ ने तीन राज्यों में राजनीतिक नेतृत्व में बदलाव का जो निर्णय लिया है, उसके लिए यही सही वक्त था। एक अटकल यह भी थी कि शायद तीनो राज्यों में लोकसभा चुनावों तक फिर पुराने चेहरों के हाथों में सत्ता सूत्र थमा दिए जाएं, लेकिन इसमें खतरा यह था कि बाद में इन धुरंधरों को कुर्सी से बेदखल करना नामुमकिन होता। ताजा प्रयोग से चंद बड़े और बुजुर्ग नेता भले मायूस हों, आम कार्यकर्ता बहुत खुश है और किसी भी राजनीतिक दल की असल पूंजी यही कार्यकर्ता होते हैं।

इनकी भावनाओं की अनदेखी कर राजनीतिक जागीरदारों को प्रश्रय देना सियासी दलों को महंगा पड़ सकता है। तीनों राज्यों में नए चेहरों को लेकर जिस तरह की हद दर्जे की गोपनीयता बरती गई और मुख्यमंत्री पद के आईने में अपना चेहरा देखने वालों को आखिरी दम तक मुगालते में रखा गया, वह अभूतपूर्व था और शायद इसलिए भी था कि बगावत की चिंगारी किसी भी स्तर पर न भड़के।

इसके अलावा इन तीन राज्यों में बिल्कुल ताजा चेहरों की ताजपोशी के साथ राजनीतिक और जातीय समीकरण भी साधने की कोशिश है। छग में आदिवासी चेहरे विष्णुदेव साय को सीएम बनाकर समूचे आदिवासी समुदाय को यह संदेश दिया गया है कि आदिवासी भी हिंदू ही हैं और वो हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इसी तरह मप्र में बिल्कुल अप्रत्याशित चेहरे डॉ. मोहन यादव को सीएम बनाकर यूपी और बिहार के यादवों को भी संदेश दिया गया है कि वो क्षेत्रीय पार्टियों के मोह से उबरें और भाजपा से जुड़ें।

मप्र और राजस्थान में दलित डिप्टी सीएम बनाकर बहनजी मायावती और उनकी पार्टी के समर्थकों को संदेश है कि भाजपा में दलितों के लिए भी पूरी जगह है। दिलचस्प बात यह है कि विस चुनाव के दौरान तीनों राज्यों में कांग्रेस पूरे समय ओबीसी जातिजनगणना का मुद्दा उठाती रही, लेकिन जिस तेलंगाना में वह स्पष्ट बहुमत के साथ चुनाव जीती, वहां उसने किसी ओबीसी के बजाए रेवंत रेड्डी के रूप में एक अगड़े को ही मुख्यमंत्री बनाया।

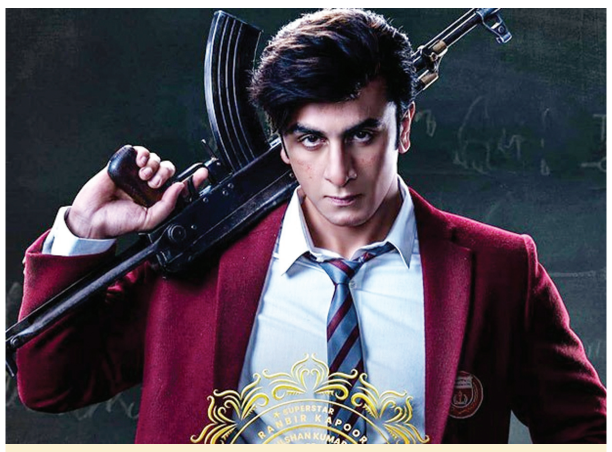

एनिमल ने रणबीर कपूर को बनाया बॉलीवुड का नया सुपरस्टार

बॉलीवुड में अभी तक शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार को ही सुपरस्टार कहा जाता रहा है । और इनके अलावा अभी तक किसी भी एक्टर में वो क्वालिटी नहीं दिखी जो उन्हें सुपरस्टार की कैटेगरी में रखती है । लेकिन अब बॉलीवुड को एक और नया सुपरस्टार मिल गया है और वो हैं एनिमल स्टार रणबीर कपूर । ऐसा हम नहीं बल्कि गैटी गैलेक्सी और मराठा मंदिर सिनेमा के एक्जिक्यूटिव डायरेक्टर और अनुभवी फ़िल्म निर्माता मनोज देसाई का कहना है । बॉलीवुड हंगामा के साथ हुई एक्सक्लूसिव बातचीत में मनोज देसाई ने रणबीर कपूर को नए सुपरस्टार की उपाधी दे दी है। बॉलीवुड हंगामा के साथ हुए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जब मनोज देसाई से पूछा गया कि, क्या अब एनिमल के बाद रणबीर कपूर भी सुपरस्टार की कैटेगरी में आ गए हैं ? इस पर मनोज ने कहा, हां,अब रणबीर कपूर भी सुपरस्टार बन गया है। वह अब दर्शकों को थियटर में खींचेगा । उसकी आने वाली फ़िल्में भी कमाल की रहेंगी । आलिया भट्ट और नीतू सिंह जी के लिए ये बहुत फ़क्र की बात है कि रणबीर कपूर अब एक सुपरस्टार बन चुके हैं। पूरे कपूर ख़ानदान को रणबीर पर नाज होना चाहिए क्योंकि एनिमल में रणबीर ने जो काम किया है वो असाधारण है । ये पक्की बात है कि रणबीर सुपरस्टार के रास्ते पर निकल चुके हैं। एनिमल की बात करें तो इसे इस साल की मास्टरपीस फ़िल्म बताया आ रहा है। संदीप रेड्डी वांगा निर्देशित एनिमल में रणबीर की बेहतरीन एक्टिंग को हर कोई पसंद कर रहा है। फ़िल्म अब तक बॉक्स ऑफ़िस पर कुल 470.58 करोड़ रु की कमाई कर चुकी है। और फ़िल्म अभी भी सिनेमाघरों में दर्शकों को आकर्षित कर रही है।

इस मशहूर डायरेक्टर ने खरीदी प्रभास की सालार की पहली टिकट, फैन्स बोले हमें कब मिलेगी ?

मशहूर डायरेक्टर एसएस राजामौली ने हाल ही में प्रभास की आने वाली फिल्म सालार= पार्ट 1 – सीजफायर का पहला टिकट खरीदा. फिल्म मेकर ने हैदराबाद में हुए एक इवेंट में ये टिकट खरीदा.

इस प्रोग्राम में सालार के डायरेक्टर प्रशांत नील और फिल्म स्टार प्रभास और पृथ्वीराज की भी शामिल थे. सभी अपनी फिल्म के प्रमोट करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं और ऐसे में राजामौली ने भी उनका साथ दिया. मैत्री मूवी मेकर्स के ऑफीशियल हैंडल ने एक कैप्शन के साथ तस्वीर शेयर की इसमें लिखा था.

रोहित निर्देशित फिल्म में सिद्धार्थ का पुलिस ऑफिसर लुक में शानदार अवतार

निर्माताओं ने आखिरकार इंडियन पुलिस फोर्स का बहुप्रतीक्षित टीज़र जारी कर दिया। टीज़र में सिद्धार्थ, शिल्पा और विवेक की तिकड़ी को पुलिस वाले के रूप में देखा जाता है जो आतंकवादी हमलों के इर्द-गिर्द घूमते मामले को सुलझाने के लिए तैयार हैं। यह शो मूल रूप से भारतीय पुलिस अधिकारियों की अथक प्रतिबद्धता को श्रद्धांजलि देता है। यह सीरीज सात भाग की एक्शन से भरपूर सीरीज है।

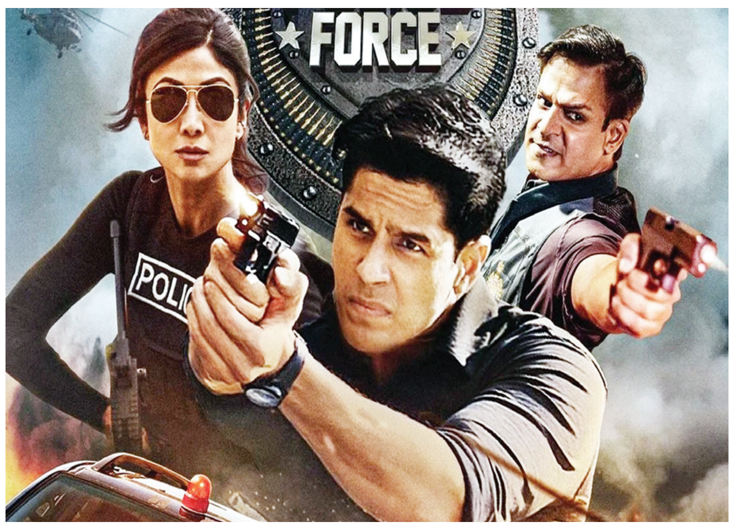

सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भी सोशल मीडिया पर टीजर शेयर किया है। टीज़र के साथ, उन्होंने कैप्शन में लिखा, आपके लिए अपना पहला एक्शन से भरपूर शो, #इंडियनपुलिसफोर्स लाने के लिए उत्साहित हूं। पुलिस ब्रह्मांड के उस्ताद के साथ एक नई वर्दी में वापस। #रोहितशेट्टी। यह श्रृंखला फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी की डिजिटल शुरुआत होगी। सीरीज़ में सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी, विवेक ओबेरॉय, श्वेता तिवारी, निकितिन धीर, ऋतुराज सिंह, मुकेश ऋषि और ललित परिमू जैसे कलाकार नज़र आएंगे। भारतीय पुलिस बल का प्रीमियर 19 जनवरी, 2024 को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेज़ॅन प्राइम वीडियो पर होने वाला है।

रोहित शेट्टी का पुलिस जगत 2011 में सिंघम फ्रेंचाइजी के साथ शुरू हुआ। उस श्रृंखला की तीसरी किस्त, सिंघम अगेन, फ्लोर पर आ गई है। इसमें अजय देवगन, करीना कपूर, दीपिका पादुकोण और टाइगर श्रॉफ हैं। सिंघम के अलावा, पुलिस यूनिवर्स में रणवीर सिंह की सिम्बा (2018) और अक्षय कुमार की सूर्यवंशी (2021) भी शामिल हैं।

अक्षय और रणवीर सिंघम अगेन में अपने कैमियो के साथ अपनी संबंधित पुलिस भूमिकाओं को फिर से दोहराने की संभावना रखते हैं। फिल्म में दीपिका पहली महिला पुलिसकर्मी शक्ति शेट्टी की भूमिका में नजर आएंगी। सिंघम अगेन भारतीय पुलिस बल के बाद 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रिलीज़ होने वाली है।

प्रभास की सालार पार्ट 1: 'सालार का स्कैल केजीएफ के पैमाने से पांच गुना बड़ा है'

होम्बले फिल्म्स यकीनन भारतीय सिनेमा में सबसे प्रतिष्ठित कंटेंट निर्माताओं में से एक है। इस प्रोडक्शन हाउस ने मेनस्ट्रीम दर्शकों को केजीएफ चैप्टर 1 और 2 और कंतारा के साथ लोगों को खूब एंटरटेन किया है। अब होम्बले फिल्म्स अपने अगले सबसे बड़े वेंचर, सालार पार्ट 1= सीजफायर की ग्रैंड रिलीज के लिए तैयार हैं, जिसमें बाहुबली स्टार प्रभास है और ये फिल्म केजीएफ निर्देशक प्रशांत नील द्वारा निर्देशित हैं । इस फिल्म के ट्रेलर को मिले जबरदस्त रिएक्शन के बाद निर्माताओं ने हाल ही में फिल्म का पहला सिंगल %सूरज ही छांव बनके% रिलीज किया है, जिसमें प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमारन द्वारा निभाए गए दो दोस्तों के बीच दोस्ती की कहानी को दर्शाया गया है। यह गाना एक हाई-इमोशनल गाना है जो दोनों किरदारों के सफर को दर्शाता है। जबकि फिल्म अगले हफ्ते, 22 दिसंबर, 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है, सिनेमैटोग्राफर भुवन गौड़ा, जिन्होंने फिल्म को अपने जादुई फ्रेम से सजाया है, ने कहा, हमने रामोजी सिटी के भीतर एक और रामोजी फिल्म सिटी द्बद्ध का निर्माण किया है, सालार के लिए, आर्ट- डायरेक्टर शिवकुमार और उनकी टीम द्वारा बनाए गए विशाल सेट 100 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। इसके अलावा, दंडुमिलाराम में, हमने आधा किलोमीटर की दीवार बनाई है और 100 एकड़ में फैले विशाल सेट। मेरी राय में, सालार का पैमाना केजीएफ से पांच गुना है। तकनीकी रूप से, हम एक अलग लेवल पर हैं। यह भारतीय फिल्मों में बनाए गए सबसे बड़े सेटों में से एक है।

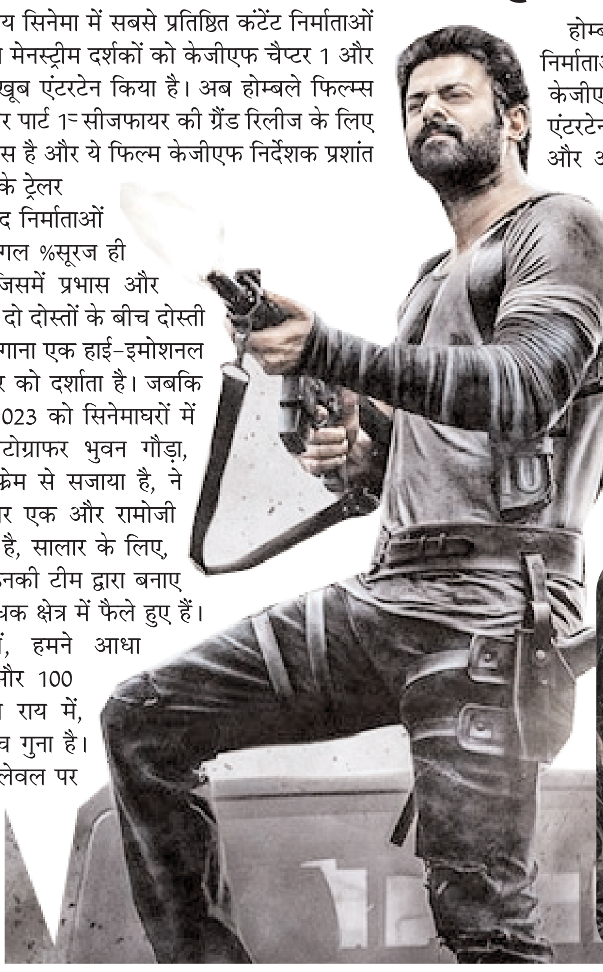

सालार पार्ट 1= सीजफायर की टेक्निकेलिटी के बारे में बात करते

लोकगीत और क्लासिकल का मिक्सर होगा कांतारा चैप्टर 1 का म्यूजिक

होम्बले फिल्म्स यकीनन भारतीय सिनेमा में सबसे प्रतिष्ठित कंटेंट निर्माताओं में से एक है। इस प्रोडक्शन हाउस ने मेनस्ट्रीम दर्शकों को केजीएफ चैप्टर 1 और 2 और कांतारा के साथ लोगों को खूब एंटरटेन किया है। इनकी फिल्मों ने सिनेमाघरों में भारी भीड़ खींची और आम जनता द्वारा भी उन्हें खूब सराहा गया। अब होम्बले फिल्म्स जहां अपने अगले सबसे बड़े वेंचर, सालार पार्ट 1= सीजफायर की ग्रैंड रिलीज के लिए तैयार हैं, उनकी हाल ही में घोषित कांतारा चैप्टर 1 भी जनता के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है और वे उत्सुकता से फिल्म का इंतजार कर रहें है । आपतो बता दें, कंतारा की सफलता में म्यूजिक ने बहुत अहम भूमिका निभाई है, जहां दर्शक वराह रूपम गीत की धुनों में खो गए थे और जो आज भी लोगों का पसंदीदा है। जबकि कांतारा चैप्टर 1 के टीज़र को दर्शकों ने बहुत पसंद किया, इसमें जिस एक चीज़ ने उनका ध्यान खींचा वह फिल्म का दिव्य संगीत था।

पहाड़ों के पथरीले रास्तों पर सोनू सूद ने किया थ्रिलिंग बाइक एडवेंचर

हाल ही में, एक्टर सोनू सूद हमें पहाड़ों के जरिये एक रोमांचक एडवेंचर पर ले गए, जहां नेचर की खूबसूरती के साथ ही एक हेल्थी और एडवेंचर्स लाइफस्टाइल के प्रति उनका समर्पण भी दिखाया गया । पहाड़ियों की चोटियों के बीच इंजन की गर्जना के साथ, सोनू सूद फिटनेस के साथ एड्रेनालाईन-पंपिंग एडवेंचर का मिश्रण करते हैं। चुनौतीपूर्ण ऊंचाइयों पर पहाड़ी लैंडस्केप की सुंदरता के साथ एक हेल्थी लाइफस्टाइल के प्रति सोनू अपनी प्रतिबद्धता को एक फिटनेस एनथुसीएस्ट के रूप में प्रकट करते हैं। हर ट्विस्ट और टर्न फिट रहने के रोमांच का प्रतीक है। यह वीडियो सिर्फ एक जॉयराइड नहीं है; यह सोनू सूद के एडवेंचर और फिटनेस के प्रति समर्पण का प्रमाण है। इस वीडियो के जरिये सोनू एडवेंचर और वेलबीइंग दोनों में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए लचीलेपन को दर्शाते हैं। आपको बता दें कि सोनू सूद ने फतेह की शूटिंग पूरी कर ली है। ज़ी स्टूडियो के साथ सोनू के शक्ति सागर प्रोडक्शंस का यह साथ में पहला को-प्रोडक्शन है।

सर्दी के मौसम में ली जाने वाली 5 सावधानियां

सर्दी के मौसम की सूचना मिलते ही, हम सब कड़ाके की पड़ने वाली ठंड और कोहरे के लिए तैयार होना शुरू कर देते हैं। यही वह समय होता है जब हम अपनी ड्राई स्किन और रोज़ होने वाले फ्लू से भी परेशान होते हैं और इसी कारण मेहनत से बनाई छुट्टियों की योजना भी धराशायी हो जाती है। यही कारण है कि सर्दियों के मौसम में अधिकतर डॉक्टर क्लीनिक और अस्पताल में सर्दी और खांसी से परेशान मरीजों की संख्या अधिक होती है।

सामान्य सर्दी- सर्दी के मौसम में आप देखेंगे कि आपके आस पास घर हो या दफ्तर, हर जगह सर्दी और खांसी से परेशान व्यक्ति मिल ही जाएँगे। हालांकि सामान्य रूप से होने वाली सर्दी से कोई विशेष परेशानी नहीं होती है लेकिन यदि इसका समय पर उपचार न किया जाये तब यह तेज़ सिरदर्द, खराब गले, बलगम जमा होना और नाक के इन्फेक्शन में बदल सकती है। इसलिए सामान्य रूप से होने वाली सर्दी से बचाव के लिए अच्छा होगा कि भली-प्रकार से जरूरत के अनुसार गरम कपड़े पहने जाएँ और जहां तक हो सके घरेलू उपचार जैसे गर्म पानी के गरारे करना, गरम पानी की भाप लेकर भी सर्दी और खांसी को दूर कर सकते हैं।

निमोनिया- निमोनिया की बीमारी का सबसे पहला लक्षण ठंड लगना हो सकता है और यदि इसका उपचार न किया जाये तो यह नुकसानदेह भी हो सकता है। यह बैक्टीरिया से होने वाला इन्फेक्शन है और इसके कारण आपको दूसरी विभिन्न बीमारियाँ भी हो सकती हैं। कुछ स्थितियों में इसका इलाज केवल डॉक्टर को दिखाने भर से और एंटी बायोटिक लेने से भी काम चल जाता है। लेकिन बीमारी के लक्षणों के आधार पर कभी-कभी मरीज को अधिक देखभाल की जरूरत होती है जिसके लिए अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत हो सकती है।

ड्राई स्किन- सर्दी में, विशेषकर कम नमी वाले मौसम में स्किन का ड्राई होना एक आम परेशानी है। सर्दी के मौसम में तेज़ गरम पानी से नहाने से बचना चाहिए जिससे आप स्किन पर होने वाली खुजली से बच सकें। इसके लिए अच्छी तरह से क्रीम या पेट्रोलियम जैली से स्किन को मॉस्चराइज करना चाहिए जिससे आप ड्राई स्किन की परेशानी से बच सकते हैं।

फ्लू- सर्दी के मौसम में फ्लू एक सामान्य रूप से होने वाली बीमारी मानी जाती है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि अपने हमेशा खाने से पहले हाथ धो लें जिससे हर प्रकार के किटाणु हमसे दूर रह सकते हैं। इसके साथ ही हमेशा कान ढ़क कर और मोज़ों को पहन कर शरीर को गरम रखने का प्रयास करना चाहिए।

सर्दी में होने वाली बीमारियों से बचाव कैसे करें- शरीर को गरम रखने के लिए थोड़े अधिक गरम कपड़े पहनें, स्वच्छता का ध्यान रखें, नियमित रूप से स्किन को मॉस्चराइज करें, ठंडा पानी पीने से बचें, तेज़ गरम पानी के स्नान से बचें, पौष्टिक भोजन करें, सर्दी में होने वाली सामान्य बीमारियों के उपचार के लिए एक हेल्थ बीमा पॉलिसी क्यों जरूरी है?

तनाव को रिवर्स करने के लिए शशांकासन से करें दिन की शुरूआत, जानें इसे करने की विधि

तन और मन को हेल्दी बनाए रखने के लिए योग एक बेहतरीन विकल्प है। दिनों दिन बढ़ रहे वर्कलोड और अनियमित खानपान के चलते शरीर में ऐंठन और तनाव की स्थिति बनी रहती है। इससे न केवल शारीरिक समस्याएं बढ़ती हैं बल्कि काम पर फोकस भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे में स्ट्रेसकम करने, शारीरिक क्षमता को बढ़ाने और खुद को हेल्दी बनाए रखने के लिए शशांकासन का अभ्यास करना बेहद ज़रूरी है। इससे शरीर को कई फायदे मिलते है और स्ट्रेस लेवल को भी कम किया जा सकता है। जानते हैं शशांकासन के फायदे और इसे करने की विधि भी।

इस बारे में योग विशेषज्ञ भावना जपत्यानी बताती हैं कि शशांकासन को करने से आज्ञा चक्र एक्टिव होता है, जिसे आसइब्रो चक्र भी कहा हैं। इससे तनाव कम होने लगता है। बार बार गुस्सा आना और इगो की समस्या भी हल हो जाती है। इसके अलावा शशांकासन के नियमित अभ्यास से पेट की मांसपेशियों को सुकून मिलता है और वो रिलैक्स हो जाती है, जिससे पेट संबधी समस्याओं से राहत मिलती है। इसके अलावा हृदय से जुड़े रोगों का खतरा भी टल जाता है। दिनभर में 2 से 3 बार इस योगासन का अभ्यास फायदेमंद साबित होता है।

हृदय रोग के जोखिम को करे कम-

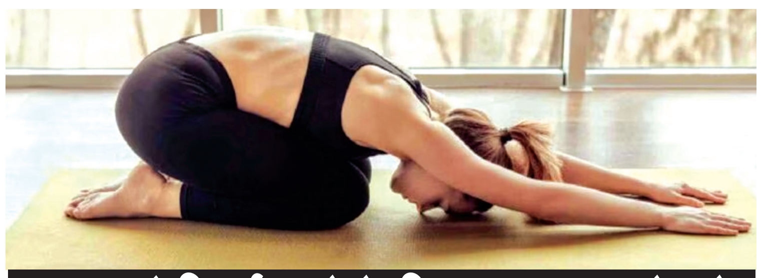

शशांकासन को रेबिट पोज़ के नाम से भी जाना जाता है। इसके नियमित अभ्यास से ब्लड प्रेशर नियमित बना रहता है और हार्ट रेट भी उचित रहता है। इससे हृदय संबधी समस्याओं का खतरा टल जाता है। रोज़ाना दिन में 2 से 3 बार इस योगाभ्यास से हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या से भी बचा जा सकता है।

तनाव होगा दूर- दिनभर चिंता में घिरे रहने के चलते मानसिक स्वस्थ्य पर उसका गहरा प्रभाव दिखने लगता है। ऐसे में मेंटल हेल्थ को बूस्ट करने के लिए शशांकासन को नियमित तौर पर करें। सिर को जमीन से छूने के चलते मस्तिष्क में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगता है, जिससे आपको फ्रेशनेस महसूस होती है।

कब्ज की समस्या से राहत- वज्रासन में बैठकर किए जाने वाले इस योग से पेट की मांसपेशियों पर खिंचाव आता है। इससे बॉवल मूवमेंट नियमित रहती है और कब्ज की समस्या से राहत मिल जाती है। रोज़ाना सुबह किए जाने वाले इस योग से पेट में होने वाली ऐंठन, अपच और एसिडिटी की समस्या से भी राहत मिल जाती है।

पोश्चर में सुधार- सुबह उठकर शशांकासन का अभ्यास करने से शरीर में लचीलापन बढ़ने लगता है। इससे शरीर का पोश्चर बेहतर हो जाता है। रोज़ाना कुछ देर तक इस योग मुद्रा में रहने से सांस पर नियंत्रण रहता है और श्वसन रोगों से भी मुक्ति मिल जाती है। इस योग मुद्रा से शारीरिक अंगों में होने वाली स्टिफनेस से राहत मिलती है।

वेटलॉस में सहायक- अक्सर थाइज़ और बट्स पर जमा फैट्स को बर्न करने के लिए कई प्रकार के व्यायाम किए जाते हैं। खुद को फिट बनाए रखने और वेटगेन से बचने के लिए शशांकासन का अभ्यास करें। इससे टांगों पर जमी चर्बी अपने आप बर्न होने लगती है। इससे आपका शरीर हेल्दी और एक्टिव बना रहता है।

जानें शशांकासन को करने की विधि- इस योगासन को करने के लिए सबसे पहले वज्रासन की मुद्रा में बैठ जाएं।

बढ़ती ठंड में शरीर को हो सकती हैं ये समस्याएं, इन बातों का रखें ध्यान

सर्दियों के सीजन में दिसंबर, जनवरी सबसे अधिक ठंड पड़ती है. ऐसे में बीते कुछ दिनों से दिल्ली समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा है. अधिक सर्दी के कारण लोग कांपने लगते हैं. तेजी से गिरता तापमान लोगों की सेहत पर भी बुरा असर डालता है. वहीं सर्दियां आते ही हमारी इम्युनिटी काफी कमजोर होने लगती है. जिसके चलते शरीर आसानी से किसी भी बीमारी के चपेट में आ जाता है. सर्दियों में सबसे पहले तो सर्दी-जुकाम से लेकर वायरल फीवर होने तक का खतरा अधिक होता है. इसलिए बढ़ती ठंड में खुद का ख्याल रखने के लिए आप कुछ आसान टिप्स को फॉलो कर सकते हैं. आइये जानें सर्दी के मौसम में खुद को सेहतमंद रखने वाली खास बातें...

गर्म कपड़े पहनें

शीतलहर के दौरान अपनी बॉडी को सर्द हवाओं से बचाने के लिए आप गर्म और ऊनी कपड़े ही पहनें. कहीं भी बाहर निकलने से पहले पूरे शरीर को गर्म कपड़ों से ढककर निकलें. खासतौर पर अपने कान, गले और सिर को ठंडी हवा से बचाएं. इसके अलावा आप खुद को गर्म रखने के लिए अलाव और हीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

गर्म तासीर वाली चीजें खाएं

ठंड के मौसम में हमारे शरीर की इम्युनिटी काफी कमजोर हो जाती है. इसलिए जरूरी है कि आप अपनी डाइट में गर्म तासीर वाली चीजों को शामिल करें. जिसे खाने से आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत हो सके. शीतलहर वाले इस मौसम में आप ज्यादा से ज्यादा अंडे, गुड़, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, लहसुन, अदरक, हल्दी, मेथी और खजूर आदि का सेवन करें.

गर्म पानी से नहाएं

ठंड के मौसम में ज्यादातर लोग नहाने से कतराते हैं, क्योंकि ठंड में नॉर्मल या फिर ठंडे पानी से नहाना आपकी तबियत खराब कर सकता है. इसलिए कोशिश करें कि आप गर्म पानी से ही नहाएं ध्यान रखें हल्के गर्म पानी से ही नहाएं. इस तरह आप खुद को भीषण ठंड से बचा सकते हैं.

पिएं गर्म पानी

ठंड के मौसम में रात में अधिक प्यास लगती है. वहीं दिन के समय में कम प्यास लगती है. जिसकी वजह से शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पहुंच पाता है. ऐसा करना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है. ठंडियों में भी शरीर को पानी की जरूरत होती है. ऐसे में बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए आप पानी जरूर पिएं, लेकिन ठंडे पानी की जगह आप गर्म पीना की सकते हैं. इससे कई तरह के फायदे होंगे.

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

संसद की सुरक्षा में चूक की वजह बेरोजगारी और महंगाई

नईदिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संसद की सुरक्षा में सेंध के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के कारण बेरोजगारी को जिम्मेदार ठहराया। पत्रकारों से बात करते हुए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि सदन में सुरक्षा चूक की घटना पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि ऐसा क्यों हुआ? देश में मुख्य मुद्दा बेरोजगारी है। प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के कारण देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और इसके पीछे (इस घटना का) कारण बेरोजगारी और महंगाई है। दिल्ली पुलिस ने स्थानीय अदालत में कहा कि संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के आरोप में गिरफ्तार ललित झा पूरे षड्यंत्र का सरगना है और वह तथा अन्य आरोपी देश में अराजकता फैलाना चाहते थे, ताकि वे सरकार को अपनी मांगें मनवाने के लिए मजबूर कर सकें। सूत्रों ने कहा कि पुलिस 13 दिसंबर को हुई इस घटना का नाट्य रूपांतरण करने के लिए संसद से अनुमति मांग सकती है।

संसद की सुरक्षा चूक मामले में छठवां आरोपी महेश गिरफ्तार

नईदिल्ली। संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में छठे आरोपी महेश कुमावत को दिल्ली पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया, जब अधिकारियों ने पुष्टि की कि वह भी पूरी साजिश का हिस्सा था। घंटों चली पूछताछ के बाद गिरफ्तारी की गई। राजस्थान के नागौर जिले के निवासी महेश भी 13 दिसंबर को दिल्ली आए थे, जब दो व्यक्ति दर्शक दीर्घा से लोकसभा कक्ष में कूद गए, जिससे धुआं फैल गया और पूरे देश में हड़कंप मच गया। राजस्थान में महेश के ठिकाने पर ही मुख्य साजिशकर्ता ललित झा घटना के बाद दिल्ली से भाग गया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि शुरुआत में गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों के मोबाइल फोन नष्ट करने में महेश भी ललित के साथ शामिल हो गया। महेश नीलम देवी के भी लगातार संपर्क में थे, जिन्हें संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के लिए गिरफ्तार किया गया था, जबकि उनके समूह के सदस्य लोकसभा में प्रवेश कर रहे थे।

19 को एक बार फिर विपश्यना पर जाएंगे अरविंद केजरीवाल

नईदिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 19 दिसंबर को राष्ट्रीय राजधानी में इंडिया ब्लॉक की चौथी बैठक के दिन 10 दिवसीय विपश्यना ध्यान पाठ्यक्रम के लिए एक अज्ञात स्थान पर रवाना होंगे। विपश्यना एक प्राचीन भारतीय ध्यान तकनीक है जिसमें अभ्यासकर्ता अपनी मानसिक भलाई को बहाल करने के लिए लंबे समय तक बात करके या इशारों के माध्यम से किसी भी संचार से दूर रहते हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि वह इंडिया ब्लॉक की चौथी बैठक में शामिल होंगे या नहीं, जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस की हार के बाद पहली बैठक है। केजरीवाल लंबे समय से विपश्यना का अभ्यास कर रहे हैं। हर साल, वह 10-दिवसीय विपश्यना पाठ्यक्रम के लिए जाते हैं और प्राचीन ध्यान प्रणाली का अभ्यास करने के लिए पिछले वर्षों में बेंगलुरु और जयपुर सहित कई स्थानों पर गए हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के सामने फिर पेश नहीं हुए कार्ति

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश होने के लिए कुछ दिन की मोहलत मांगी है। बता दें कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और साल 2011 में चीनी नागरिकों को वीजा जारी कराने के मामले में कार्ति चिदंबरम को समन जारी किया था। अब कार्ति चिदंबरम ने आरोप लगाया है कि ईडी द्वारा जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, वह मामले से बिल्कुल भी संबंधित नहीं हैं और उन्हें मांगे गए दस्तावेज इकट्ठा करने के लिए समय चाहिए। ईडी ने पहले कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को आज 12 दिसंबर को जांच अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया था। इस पर कार्ति चिदंबरम ने संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल होने का हवाला देकर पूछताछ के लिए पेश होने में असमर्थता जताई। इस पर ईडी ने 16 दिसंबर को कार्ति को जांच अधिकारी के सामने पेश होने का आदेश दिया। अब मांगे गए दस्तावेज इकट्ठा करने का हवाला देकर कार्ति चिदंबरम ने एक बार फिर पूछताछ के लिए पेश ना होने में असमर्थता जताई।

धारावी प्रोजेक्ट मामले में उद्धव और शिंदे गुट आमने-सामने

मुंबई। शिवसेना के दो समूहों के बीच चल रही खींचतान में धारावी पुनर्विकास परियोजना एक और मुद्दा बनकर उभरी है। जबकि शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने शनिवार को धारावी से मुंबई में उद्योगपति गौतम अडानी के कार्यालय तक मार्च करने की योजना बनाई है। वहीं, शिवसेना सांसद राहुल शेवाले ने परियोजना के कार्यान्वयन का आश्वासन देने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। धारावी मुंबई दक्षिण मध्य लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसका प्रतिनिधित्व दो बार के सांसद 49 वर्षीय शेवाले ने 2014 से किया है। एक समय में उद्धव ठाकरे के करीबी माने जाने वाले शेवाले दो दशकों से अधिक समय से शिवसेना से जुड़े हुए हैं। वह पार्टी संगठन में कई पदों पर रह चुके हैं और तीन बार बीएमसी का चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने बीएमसी की स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया और भारत के सबसे अमीर नगर निगम के प्रबंधन पर उनका नियंत्रण था। अडानी प्रॉपर्टीज़ ने जुलाई में 594 एकड़ की झुग्गी बस्ती के पुनर्विकास की बोली जीती।

प्रधानमंत्री मोदी ने बदल दी राजनीति की संस्कृति : नड्डा

- **कांग्रेस के लोग इसे जल्दी समझ लें, तो अच्छा है**

शिमला। तीन राज्यों में मिली चुनावी जीत के बाद भाजपा का उत्साह चरम पर है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार को अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। बिलासपुर में जेपी नड्डा के अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि 3 राज्यों की हमारी इस जीत ने तथाकथित राजनीति पंडितों को भी स्तब्ध किया है। क्योंकि वो राजनीति के गणित को पहचान नहीं पाते, राजनीति की गहराइयों को जान नहीं पाते। वो समझ नहीं पाते कि ये कैसे हो गया।

नड्डा ने कहा कि वर्तमान समय में राजनीति करने के अर्थ बदल चुके हैं। कांग्रेस के लोग इसे जल्दी समझ लें, तो अच्छा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने राजनीति की संस्कृति बदल दी है। मोदी जी ने कहा है कि जो कहा था, वो किया है और जो नहीं कहा था, वो भी करके दिया है। उन्होंने कहा कि आज के समय में जनता रिपोर्ट कार्ड की राजनीति पर विश्वास करती है। अब दुनिया में ये साबित हो गया है कि मोदी की गारंटी, गारंटी पूरा होने की भी गारंटी है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मोदी जी की सरकार ने हर घर तक नल से जल पहुंचाया है। मुझे खुशी है कि नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने मुझे स्वास्थ्य मंत्री बनाया। उसके बाद हमने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना हमने शुरू की। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश के 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। अब भारत में अति गरीबी 1% से भी कम रह गई है। ये है मोदी जी की गारंटी।

जेपी नड्डा ने कहा कि नारी शक्ति वंदन विधेयक के माध्यम से महिलाओं को 33% आरक्षण देने का काम मोदी जी ने किया है। 2027 में जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव होंगे तो यहां विधानसभा में 33% बहनें होंगी और 2029 में संसद में भी 33% महिलाएं होंगी। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने हिमाचल को हमेशा अपना समझा है। जब यहां आपदा आई, तो मोदी जी के निर्देश पर हम यहां आए थे। 10 जुलाई को हमने 180 करोड़ रुपये की पहली किस्त यहां दी और फिर 20 जुलाई को भी 180 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त हिमाचल के लिए दी गई।

नड्डा ने कहा कि अभी 4 दिन पहले 633 करोड़ रुपये हिमाचल को दिए गए हैं। हिमाचल में सिर्फ राहत के रूप में 1,782 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता दी गई है। 11 हजार घर बनाने के लिए 2,500 करोड़ रुपये अलग से हिमाचल प्रदेश सरकार को दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता हमारे लिए गरीब जनता की सेवा करने और उसे ताकत देने का माध्यम है। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भारत और हिमाचल की जनता को बहुत आशाएं हैं। इसलिए संयम और प्रेम के साथ, सभी को साथ जोड़कर हमे चलना है।

चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस ने मांगी मदद

शुरू करेगी डोनेट फॉर देश अभियान हर पदाधिकारियों को देने होंगे रुपए

नईदिल्ली। कांग्रेस ने शनिवार को 18 दिसंबर से डोनेट फॉर देश नाम से एक ऑनलाइन क्राउड फंडिंग अभियान शुरू करने की घोषणा की और कहा कि यह पहल 1920-21 में महात्मा गांधी के ऐतिहासिक तिलक स्वराज फंड से प्रेरित है। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अपने ऑनलाइन क्राउडफंडिंग अभियान, डोनेट फॉर देश के लॉन्च की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है। यह पहल 1920-21 में महात्मा गांधी के ऐतिहासिक तिलक स्वराज कोष से प्रेरित है और इसका उद्देश्य समान संसाधन वितरण और अवसरों से समृद्ध भारत बनाने में हमारी पार्टी को सशक्त बनाना है।

कांग्रेस नेता ने आगे बताया कि अभियान की आधिकारिक शुरुआत पार्टी अध्यक्ष 18 दिसंबर को दिल्ली में करेंगे। हम अपने राज्य-स्तरीय पदाधिकारियों, हमारे निर्वाचित प्रतिनिधियों, डीसीसी अध्यक्षों, पीसीसी अध्यक्षों और एआईसीसी पदाधिकारियों को कम से कम 1,380 रुपये का योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वेणुगोपाल ने कहा, हमारा डोनेशन अभियान बेहतर भारत के लिए दान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 138 साल की यात्रा का जश्न मनाता है। वेणुगोपाल ने कहा, अपने इतिहास को अपनाते हुए, हम समर्थकों को 138 रुपये या 1380 रुपये या 13,800 रुपये या उससे अधिक के गुणकों में दान करने के लिए आमंत्रित करते हैं, जो बेहतर भारत के लिए पार्टी की स्थायी प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

उन्होंने कहा कि इस ऑनलाइन क्राउडफंडिंग के लिए दो चैनल बनाए गए हैं, एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल: Donateinc.in के माध्यम से और दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आधिकारिक वेबसाइट: www.inc.in के माध्यम से। वेणुगोपाल ने कहा कि अभियान आधिकारिक तौर पर 18 दिसंबर को नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा लॉन्च किया जाएगा, साथ ही दान लिंक भी लाइव होगा। उन्होंने कहा कि हम सभी राज्य इकाई प्रमुखों से प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने का आह्वान करते हैं। अभियान मुख्य रूप से 28 दिसंबर, स्थापना दिवस तक ऑनलाइन रहेगा, जिसके बाद हम जमीनी अभियान शुरू करेंगे, जिसमें स्वयंसेवकों द्वारा घर-घर जाकर दौरा करना, प्रत्येक बूथ में कम से कम दस घरों को लक्षित करना और प्रत्येक घर से कम से कम 138 रुपये का योगदान देना शामिल है।

एआईसीसी कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि डोनेट फॉर देश पहल एक व्यापक अभियान है, जिसके तहत कैंपेन की एक सीरीज चलाई जाएगी। इनमें से एक पहल के तहत, पार्टी कांग्रेस की 138वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 138 के गुणकों में दान को प्रोत्साहित कर रही है।

18 दिसंबर को अभियान होगा लॉन्च

माकन ने कहा कि अभियान आधिकारिक तौर पर 18 दिसंबर को नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा शुरू किया जाएगा और ऑनलाइन दान लिंक उसी समय लाइव हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि दान के लिए दो चैनल बनाए गए हैं। एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल (www.donateinc.in) और आधिकारिक ढ्ढह्व वेबसाइट (www.inc.in)। कांग्रेस नेताओं के अनुसार यह अभियान मुख्य रूप से पार्टी के स्थापना दिवस 28 दिसंबर तक ऑनलाइन रहेगा।

सूरत का डायमंड एक्सचेंज का प्रधानमंत्री आज करेंगे उद्घाटन

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 दिसंबर (रविवार) को सूरत गुजरात में नवनिर्मित सूरत डायमंड बोर्स (एसडीबी) भवन का उद्घाटन करने के लिए तैयार हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर, एसडीबी बिल्डिंग, डायमंड रिसर्च एंड मर्केंटाइल (ड्रीम) सिटी और सूरत हवाई अड्डे के नए उन्नत टर्मिनल भवन का एक हिस्सा है। पीएम मोदी के दौरे से पहले सूरत में तैयारियां चल रही हैं। एसडीबी के मीडिया संयोजक दिनेश नवादिया के अनुसार, कई हीरा व्यापारियों, जिनमें पहले मुंबई स्थित व्यापारी भी शामिल थे, ने उद्घाटन से पहले ही अपने कार्यालयों पर कब्जा कर लिया है, जिन्हें नीलामी के बाद प्रबंधन द्वारा आवंटित किया गया था। उन्होंने कहा, उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एसडीबी भवन के पास एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। जुलाई में, सूरत डायमंड बोर्स के सीईओ महेश गढ़वी ने कहा था कि यह दुनिया की सबसे बड़ी कार्यालय इमारत है। इसमें 4,500 से अधिक हीरा व्यापार कार्यालय हैं। कच्चे हीरों के व्यापार से लेकर पॉलिश हीरों की बिक्री तक - ये दोनों यहीं होंगे। हमने यहां विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार किया है। इससे लगभग 1.5 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हमने वर्तमान और भविष्य दोनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भविष्य-प्रूफ इमारत बनाने की कोशिश की है। हमने हर एक कार्यालय को फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान की है। सुरक्षा से समझौता न हो इसके लिए यहां 4000 से ज्यादा कैमरे और अत्याधुनिक कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। एसडीबी बिल्डिंग, 67 लाख वर्ग फुट से अधिक क्षेत्रफल वाला दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर, सूरत शहर के पास खजोद गांव में स्थित है। कार्यालय परिसर संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन के मुख्यालय भवन से भी बड़ा है। इसकी कीमत करीब 3000 करोड़ रुपये है। एसडीबी के लगभग 4,500 हीरा व्यापार कार्यालय हैं। ड्रीम सिटी के अंदर 35.54 एकड़ के भूखंड पर बनी इस विशाल संरचना में भूतल के नौ टावर और 15 मंजिल हैं, जिसमें 300 वर्ग फुट से 1 लाख वर्ग फुट तक के कार्यालय स्थान हैं।

पीएम मोदी ने विजय दिवस पर कहा- देश रहेगा उनका कर्जदार

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विजय दिवस के मौके पर 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के नायकों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उनकी वीरता और समर्पण देश के लिए बेहद गर्व का स्रोत है। उनका बलिदान और अटूट भावना हमेशा लोगों के दिलों और हमारे देश के इतिहास में अंकित रहेगी। उन्होंने कहा कि भारत उनके साहस को सलाम करता है और उनकी अदम्य भावना को याद करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज, विजय दिवस पर, हम उन सभी बहादुर नायकों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने 1971 में निर्णायक जीत सुनिश्चित करते हुए कर्तव्यनिष्ठा से भारत की सेवा की। पाकिस्तान पर भारत की निर्णायक जीत से बांग्लादेश का जन्म हुआ। आज, विजय दिवस पर, हम उन सभी बहादुर नायकों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने 1971 में निर्णायक जीत सुनिश्चित करते हुए कर्तव्यनिष्ठा से भारत की सेवा की।

खेल

प्रमुख समाचार

शमी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से हुए बाहर

नईदिल्ली। दक्षिण अफ्रीका दौरे पर टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। हाल ही में समाप्त हुए वनडे वर्ल्ड कप में शानदार गेंदबाजी करने वाले भारत के स्टार पेसर मोहम्मद शमी टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। यह दो मैचों की टेस्ट सीरीज 26 दिसंबर से शुरू होने वाली है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एक विज्ञप्ति में इस बात की पुष्टि की है। विज्ञप्ति के अनुसार, फिटनेस हासिल नहीं कर पाने के कारण बीसीसीआई मेडिकल टीम द्वारा मोहम्मद शमी को इस सीरीज के लिए मंजूरी नहीं दी गई। पहले चार मैच नहीं खेलने के बावजूद, मोहम्मद शमी 24 विकेट के साथ क्रिकेट विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब रविवार से तीन मैचों की वनडे सीरीज शुरू होने वाली है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह जैसे सीनियर खिलाड़ियों की टेस्ट सीरीज में वापसी होनी है। इससे पहले खेले गए तीन मैचों की टी20 सीरीज 1-1 से बराबरी पर रहा। पहला मुकाबला बारिश की वजह से बिना टॉस के ही रद्द कर दिया गया था। दूसरा मुकाबला भारत हारा था और आखिरी मुकाबले में सूर्यकुमार यादव के शानदार शतक और कुलदीप यादव के 5 विकेट से टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की थी। रिंकू सिंह को हाल ही में समाप्त हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन का इनाम मिला है। उन्हें वनडे टीम में जगह दी गई है। टी20 में टीम की कप्तानी करने वाले सूर्यकुमार यादव को वनडे सीरीज से आराम दिया गया है।

वनडे टीम- रुतुराज गायकवाड़, साई सुदर्शन, तिलक वर्मा, रजत पाटीदार, रिंकू सिंह, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (कप्तान, विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, मुकेश कुमार, आवेश खान, अर्शदीप सिंह, आकाश दीप।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

वैश्विक चुनौतियों के बीच हमारी इकोनॉमी बेहतर ढंग से प्रबंधित

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की सराहना की। उन्होंने कहा है कि दुनिया के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं और अस्पष्ट चीजें चारों ओर हो रही हैं। इस सबके बीच हम अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छी तरह से प्रबंधित करने में सफल रहे हैं। भारत मंडपम में लीड रिपोर्ट 2023 जारी करने के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह अस्थिरता और अनिश्चितताओं का दिन और युग है। दुनिया के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं और अस्पष्ट चीजें चारों ओर हो रही हैं। इस वीयूसीए (अस्थिरता, अनिश्चितता, जटिलता और अस्पष्टता) की दुनिया में, मुझे लगता है कि भारत एक उज्ज्वल सितारे और एक ऐसे देश के रूप में खड़ा है जिसने पीएम मोदी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छी तरह से प्रबंधित किया है। हम लगातार सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं।

आठ आईपीओ में अगले सप्ताह निवेश का अवसर

नई दिल्ली। आईपीओ बाजार अपने उफान पर है। इस सप्ताह तीन कंपनियों के पूंजी बाजार में उतरने के बाद अगले हफ्ते आठ कंपनियों के शेयरों में निवेश का मौका मिलेगा। ये कंपनियां 4,360 करोड़ रुपये जुटाएंगी। साथ ही, तीन कंपनियों के शेयर सूचीबद्ध भी होंगे। इनमें से ज्यादातर के भाव ग्रे मार्केट में इश्यू के दाम से ऊपर चल रहे हैं। इस सप्ताह डोम्स और इंडिया शेल्टर के आईपीओ बंद हुए हैं। इस साल अब तक आए आईपीओ से निवेशकों को जमकर कमाई हुई है। करीब 95 फीसदी कंपनियों के शेयरों ने फायदा दिया है। हाल ही में सूचीबद्ध टाटा टेक, इरेडा और गांधार ऑयल ने लिस्टिंग पर ही निवेशकों की रकम करीब दोगुनी कर दी। इरेडा का शेयर अब तक ढाई गुना बढ़ चुका है। इस वित्त वर्ष में 44 कंपनियों ने अब तक 35,000 करोड़ रुपये बाजार से जुटाए हैं।

एनटीपीसी माइनिंग ने चालू वित्त वर्ष में दो करोड़ 32.2 लाख टन कोयला उत्पादन किया

नई दिल्ली। एनटीपीसी माइनिंग ने वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक दो करोड़ 32.2 लाख टन कोयला उत्पादन किया है। यह पूरे वित्त वर्ष 2022-23 में प्राप्त दो करोड़ 32 लाख टन के उत्पादन स्तर से कुछ अधिक है। उत्पादन का यह स्तर 257 दिनों में हासिल किया गया। यानी 2022-23 के मुकाबले 108 कम दिन में यह उत्पादन हासिल किया गया। सालाना आधार पर कोयला उत्पादन में 77 प्रतिशत और आपूर्ति में 88 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। एनटीपीसी लि. की अनुषंगी एनटीपीसी माइनिंग ने एक बयान में कहा, ''एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड (एनएमएल) ने वित्त वर्ष 2022-23 के दो करोड़ 32.03 लाख टन की तुलना में 2023-24 में 13 दिसंबर तक दो करोड़ 32.23 लाख टन उत्पादन किया।''

एलआईसी एजेंटों को अब मिलेगी पांच लाख ग्रेच्युटी

नई दिल्ली। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने अपने एजेंटों के लिए ग्रेच्युटी सीमा तीन लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी है। इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। यह बढ़ोतरी भारतीय जीवन बीमा निगम (एजेंट) विनियमन-2017 में संशोधन कर प्रभाव में लाई गई है। एलआईसी ने शेयर बाजार को बताया कि इन नियमों को भारतीय जीवन बीमा निगम (एजेंट) संशोधन विनियमन-2023 कहा जा सकता है। यह नियम 6 दिसंबर के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू हुआ है। वित्त मंत्रालय ने सितंबर में एलआईसी एजेंटों और कर्मचारियों के लाभ के लिए कई कल्याणकारी उपायों को मंजूरी दी थी। इन उपायों में ग्रेच्युटी सीमा और पारिवारिक पेंशन में वृद्धि भी शामिल है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की विभिन्न योजनाओं के तहत अक्तूबर में 17.28 लाख नए कर्मचारी जुड़े हैं।

उपभोक्ता व्यय में निरंतर वृद्धि आवश्यक

अजीत रानाडे

सरकार ने 30 नवंबर को वर्तमान वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के आर्थिक आंकड़े जारी किये हैं। इन्हें राष्ट्रीय आर्थिक उत्पादन का तात्कालिक आकलन कहा जाता है। इनमें दो प्रकार के आंकड़े होते हैं- योजित सकल मूल्य (जीवए) और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)। जीवीए, में हर व्यक्तिगत उत्पादक या क्षेत्र या उद्योग द्वारा अर्थव्यवस्था में जोड़े गये मूल्य को मापा जाता है। इसमें हर तरह के उत्पादकों, चाहे वे किसान हों, छोटे उद्यमी हों या बड़ी कंपनियां हों, के मूल्य का मापन होता है। इस प्रकार, जीवीए, उस मूल्य को मापता है, जो लागत (इनपुट) को उत्पाद (आउटपुट) में बदलने पर हासिल होता है। जीडीपी निर्धारित समयावधि में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य है। निर्धारित समय तिमाही या वार्षिक हो सकता है। इसे तीन अलग-अलग तरीकों से मापा जाता है- या तो सारे उत्पादन के मूल्य के रूप में, या सारे खर्च के रूप में या सारी आय के रूप में। इन तीनों का परिणाम एक ही होता है क्योंकि बेची गयी वस्तु का कुल मूल्य उसके उत्पादक की आय भी होती है। जीवीए और जीडीपी में एकमात्र अंतर चुकाये गये कर या प्राप्त किये गये अनुदान का होता है। आम तौर पर जीडीपी हमेशा जीवीए से अधिक होता है क्योंकि सरकार द्वारा वसूला गया कर दिये गये अनुदान से अधिक होता है।

दूसरी तिमाही में जीडीपी 72 लाख करोड़ रुपये रही, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 66 लाख करोड़ रुपये थी। जीवीए दूसरी तिमाही में 64 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 59 लाख करोड़ रुपये था। इस हिसाब से वर्तमान मूल्यों पर वार्षिक जीडीपी 300 लाख करोड़

रुपये हो सकती है, जो 2012 की तुलना में तीन गुना, यानी 200 प्रतिशत अधिक होगी। जीडीपी और जीवीए के आंकड़ों का परीक्षण बढ़ती कीमतों के असर को अलग रखकर करने की जरूरत है। चूंकि बीते चार वर्षों में मुद्रास्फीति औसतन पांच फीसदी के करीब रही है, तो वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी या जीवीए की वृद्धि की 'असली' तस्वीर नहीं है क्योंकि इसमें मुद्रास्फीति भी एक तत्व है। अगर मुद्रास्फीति के असर को हटा दें, तो दूसरी तिमाही में जीडीपी की वास्तविक वृद्धि 7.6 प्रतिशत रही, जो बीते साल के 6.2 प्रतिशत से अधिक है। इस साल की दोनों तिमाहियों (अप्रैल से सितंबर) को साथ देखें, तो जीडीपी की वास्तविक बढ़ोतरी 7.7 प्रतिशत रही है। इस हिसाब से वार्षिक जीडीपी निश्चित रूप से सात प्रतिशत से अधिक रहेगी और भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में बना रहेगा। युद्ध, मुद्रास्फीति, आपूर्ति श्रृंखला, भू-राजनीतिक तनावों और अनिश्चितता से पैदा संकटों में यह आर्थिक वृद्धि शानदार उपलब्धि है। अब हमें तीन प्रश्नों का परीक्षण करना चाहिए। पहला, इस वृद्धि का कारक क्या है? दूसरा, क्या यह मध्यम या दीर्घ अवधि में बरकरार रह सकेगी? तीसरा, विभिन्न वर्गों के लोगों को जीडीपी वृद्धि से क्या फायदे हो रहे हैं? पहले प्रश्न का उत्तर है कि उपभोक्ता व्यय की तुलना में सरकारी और निवेश व्यय में अधिक तेजी आयी है। सरकारी खर्च की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत और निवेश व्यय (जिसे पूंजी निर्माण भी कहा जाता है) की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत है। शेष उपभोक्ता व्यय है, जिसकी सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। अभी निर्यात का हिस्सा मुश्किल एक या डेढ़ फीसदी है। इस वर्ष जुलाई से सितंबर के बीच सरकारी खर्च में पिछले साल से 19 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। पिछले साल की दूसरी तिमाही में यह खर्च 5.9 लाख करोड़ रुपये था, जो इस बार सात लाख करोड़ रुपये रहा। इसी तरह, निवेश व्यय में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई। स्पष्ट रूप से ये दो कारक उल्लेखनीय वृद्धि को गति दे रहे हैं। लेकिन उपभोक्ता व्यय में इस तिमाही में मात्र आठ प्रतिशत बढ़ोतरी हुई। ये सब आंकड़े सामान्य हैं तथा इन्हें मुद्रास्फीति और महंगाई के हिसाब से समायोजित नहीं किया गया है। अगर आप इनका हिसाब लगायें, तो उपभोक्ता व्यय में बढ़त मात्र तीन प्रतिशत रह जायेगी, जबकि जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी 60 प्रतिशत है।

कही-सुनी

रवि भोई

छत्तीसगढ़ की नई सरकार में सब कुछ सस्पेंस में

छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार 13 दिसंबर से अस्तित्व में आ गई है, लेकिन अभी तक कुछ भी साफ़ नहीं है। मंत्रिमंडल के गठन को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। नए मंत्रिमंडल को लेकर कयासों का बाजार ठंडा पड़ गया है। प्रोटेम स्पीकर के लिए पहले बृजमोहन अग्रवाल का नाम चल रहा था, लेकिन जिम्मेदारी मिली रामविचार नेताम को। कहते हैं सबसे वरिष्ठ विधायक को प्रोटेम स्पीकर बनाने की परंपरा है, लेकिन मुख्यमंत्री दूसरे किसी वरिष्ठ विधायक का नाम सुझा सकते हैं। कहा जा रहा है कि रमन कैबिनेट में रहे किसी नेता को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। नए लोगों को उपमुख्यमंत्री बना दिया गया है। उपमुख्यमंत्री बनाए गए अरुण साव और विजय शर्मा पहली बार के विधायक हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि साय मंत्रिमंडल में पहली बार के कई विधायकों को जगह मिल सकती है। इस कारण ओपी चौधरी से लेकर किरणदेव,नीलकंठ टेकाम,खुशवंत साहेब, गजेंद्र यादव, टंकराम वर्मा, उद्धेश्वरी पैकरा का नाम मंत्री के लिए चलने लगा है। 19 दिसंबर से तीन दिवसीय विधानसभा सत्र है, ऐसे में 18 दिसंबर को कैबिनेट के विस्तार का हल्ला है। खबर है कि 17 दिसंबर को राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन दिल्ली से लौट आएंगे। इसी दिन वे प्रोटेम स्पीकर को शपथ भी दिलाने वाले हैं।

क्या बसवराजू होंगे मुख्यमंत्री के सचिव

कहा जा रहा है कि 2007 बैच के आईएएस बसवराजू एस मुख्यमंत्री के सचिव बनाए जा सकते हैं। बसवराजू मूलत: कर्नाटक के रहने वाले हैं और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बी एल संतोष के रिश्तेदार बताए जाते हैं। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल के गठन से लेकर ब्यूरोक्रेसी की नियुक्ति में बी एल संतोष का खासा दखल रहने वाला है। भूपेश बघेल के राज में बसवराजू उपेक्षित रहे। 2018 के चुनाव के वक्त वे रायपुर के कलेक्टर थे। फिर वे कुछ साल के लिए प्रतिनियुक्ति पर चले गए। डेपुटेशन से लौटने के बाद उन्हें स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री के सचिव के लिए 2006 बैच के आईएएस पी दयानंद का नाम भी चर्चा में है। भूपेश बघेल के राज में दयानंद को भी कोई अच्छी पोस्टिंग नहीं मिली थी। भूपेश सरकार के एक मंत्री से दयानंद का छत्तीस का आंकड़ा था। जब जिले में थे तब भी उनकी पटरी नहीं बैठी थी।

पावर सेंटर की तलाश में अफसर

चर्चा है कि राज्य के वरिष्ठ अफसर नई सरकार में अच्छी पोस्टिंग के लिए पावर सेंटर की तलाश में लगे हैं। कहा जा रहा है कि भाजपा की नई सरकार में अफसरों की पोस्टिंग से लेकर नीतिगत निर्णय दिल्ली से होंगे या संघ के दफ्तर से। कहते हैं मलाईदार पदों में पोस्टिंग की चाहत रखने वाले बड़े अफसर मुख्यमंत्री के आगे-पीछे दिख रहे हैं, साथ में संघ के दफ्तर में भी उपस्थिति दे रहे हैं। पिछले दिनों पुलिस के तीन आला अफसरों का जागृति मंडल में जाना, इसका उदाहरण माना जा रहा है। कुछ दिनों पहले तक अफसर भाजपा के एक दिग्गज नेता के दरबार में हाजिरी देने पहुंच रहे थे, जब समझ में आ गया कि नई सरकार में उनकी नहीं चलनी है, तो अफसरों की भीड़ छटने लग गई। भाजपा कार्यालय से लेकर कुछ और जगहों पर आईएएस,आईपीएस,आईएफएस और दूसरे अफसरों की पोस्टिंग लिस्ट बनाए जाने की ख़बरें आ रही हैं। रमन सरकार में पावरफुल रहे एक अफसर के एक आलीशान होटल में दफ्तर खोलने की भी चर्चा है। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में पावर सेंटर को लेकर कुहासा छटेगा।

नई सरकार में पावरफुल रहेगी साउथ लॉबी

माना जा रहा है कि विष्णुदेव साय की सरकार में दक्षिण भारतीय अफसर ज्यादा ताकतवर रहेंगे। खबर है कि रिटायर्ड आईएएस बीवीआर सुब्रमण्यम मुख्यमंत्री के सलाहकार बनकर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। 1987 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस सुब्रमण्यम अभी नीति आयोग के सीईओ हैं। वे जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव और भारत सरकार में कई पदों पर रह चुके हैं। 2005 बैच की आईएएस आर शंगीता को भी अच्छी पोस्टिंग मिल सकती है। भूपेश सरकार में आर शंगीता दरकिनार रही। साउथ के दूसरे अफसरों को भी नई सरकार में काफी तवज्जो मिल सकती है। नई सरकार में आईपीएस एसआरपी कल्लूरी को भी महत्व मिल सकता है। कल्लूरी और सुब्रमण्यम की कैमेस्ट्री अच्छी बताई जाती है। प्रमोटी आईएएस अफसरों का कद घट सकता है। जिलों में भी सीधी भर्ती वाले आईएएस बढ़ेंगे।

भाजपा के वरिष्ठ विधायक लड़ेंगे लोकसभा

चर्चा है कि भाजपा के कुछ वरिष्ठ विधायकों को पार्टी लोकसभा चुनाव लड़वाना चाहती है। खबर है कि उन्हें संकेत भी दे दिए गए हैं। इस कारण उन्हें मंत्री भी नहीं बनाया जा रहा है। माना जा रहा है कि बृजमोहन अग्रवाल को रायपुर, अजय चंद्राकर को महासमुंद और धरमलाल कौशिक या अमर अग्रवाल को बिलासपुर से लोकसभा चुनाव लड़वाया जा सकता है। कहते हैं विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी भाजपा कुछ नए प्रयोग कर सकती है। अब देखते हैं क्या होता है।

कल्लूरी बन सकते हैं एडीजी नक्सल आपरेशन

चर्चा है कि 1994 बैच के आईपीएस शिवरामप्रसाद कल्लूरी एडीजी नक्सल आपरेशन हो सकते हैं। भूपेश सरकार ने कल्लूरी को पहले ईओडब्ल्यू का एडीजी, फिर परिवहन आयुक्त बनाया था। इसके बाद लूप लाइन में पटक दिया। वे पिछले तीन साल से एडीजी ट्रेनिंग हैं। सरगुजा इलाके में नक्सलियों के खात्मे के लिए कल्लूरी को याद किया जाता है। कल्लूरी ने बस्तर आईजी रहते बस्तर इलाके में नक्सलवाद को काफी हद तक कंट्रोल किया था। यह अलग बात है कि उनकी कार्यशैली को लेकर तीखी आलोचना हुई और उन पर कई आरोप भी लगे, लेकिन कल्लूरी के नाम पर नक्सलियों में दहशत कायम हो गया था। कहते हैं जिस तरह बस्तर में भाजपा नेताओं की टारगेट किलिंग हो रही है, उसे देखते हुए नई सरकार कल्लूरी को नक्सलियों के खात्मे की कमान सौंप सकती है।

नेता प्रतिपक्ष के लिए महंत का पलड़ा भारी

नेता प्रतिपक्ष के लिए डॉ चरणदास महंत का पलड़ा भारी माना जा रहा है। वैसे दौड़ में कई लोग हैं। महंत केंद्र और संयुक्त मध्यप्रदेश में मंत्री रहने के साथ भूपेश सरकार में विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वरिष्ठता और अनुभव को देखते हुए उन्हें नेता प्रतिपक्ष का सशक्त दावेदार माना जा रहा है। माना जा रहा है कि दिल्ली में भी महंत की पकड़ अच्छी है। नेता चुनने के लिए पिछले दिनों कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी। कोई फैसला नहीं लिया जा सका और नेता चुनने का अधिकार हाईकमान को दे दिया गया। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष के लिए कांग्रेस हाईकमान कब तक फैसला लेती है। नई विधानसभा का पहला सत्र 19 दिसंबर से शुरू होने वाला है, ऐसे में हाईकमान को 19 दिसंबर से पहले फैसला करना होगा।

हार के बाद कांग्रेस में रार

विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद कांग्रेस का अंतरकलह आसमान फाड़ने लगा है। हार का ठीकरा संगठन और बड़े नेताओं पर फोड़ने वाले पूर्व विधायक बृहस्पत सिंह और डॉ विनय जायसवाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। अब पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल निशाने पर हैं। अग्रवाल को अपनी भड़ास निकालने पर नोटिस मिल गई है। नोटिस के जवाब पर जयसिंह के खिलाफ कार्रवाई टिकी है। बृहस्पत सिंह और विनय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी माने जाते हैं। जयसिंह को टीएस सिंहदेव के खेमे का माना जाता है। बृहस्पत की टिकट काटने में टीएस सिंहदेव की अहम भूमिका मानी जाती है। बृहस्पत की जगह टीएस सिंहदेव ने ख़ास समर्थक को प्रत्याशी बनवाया। टिकट से वंचित पूर्व विधायक अब लामबंद होने लगे हैं। इस कारण आने वाले दिनों में कांग्रेस के भीतर और झगड़े बढ़ने के आसार हैं। अपनी हार से दुखी होकर महंत रामसुंदर दास ने कांग्रेस को ही त्याग दिया। पूर्व विधायक मोहित राम भी कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया है।

जनता के आशीर्वाद और सहयोग से मोदी की गारंटी करेंगे पूरी: मुख्यमंत्री साय

छत्तीसगढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ, मोदी ने कहा: कोने-कोने में पहुंचेगी गारंटी, जरूरतमंदों को मिलेगा योजनाओं का लाभ

रायपुर। मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने के पश्चात राजधानी रायपुर के ऐतिहासिक विवेकानंद सरोवर से श्री विष्णु देव साय के पहले सार्वजनिक कार्यक्रम में ''विकसित भारत संकल्प यात्रा'' का आगाज हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ सहित पांच राज्यों में संकल्प यात्रा का आगाज नई दिल्ली से वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से रथों को हरी झंडी दिखाकर किया। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने रायपुर में ''विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ'' को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने विकास का विश्वास लेकर कार्यक्रम में पहुंचे बड़ी संख्या में उत्साहित लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि जनता के आशीर्वाद और सहयोग से हम ''मोदी की गारंटी'' को छत्तीसगढ़ में पूरा करेंगे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पांच राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के कोने कोने में पहुंच रही है। यात्रा को शुरू हुए एक महीना हो चुका है।

यात्रा हजारों गांवों के साथ डेढ़ हजार शहरों में भी पहुंच चुकी है। इनमें से अधिकतर छोटे-छोटे कस्बे हैं। आज छत्तीसगढ़ से भी यात्रा का शुभारंभ हो गया है। मेरा नई सरकार से आग्रह है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का अपने राज्य में तेजी से विस्तार करें।

इसे हरी झंडी भले ही मोदी ने दिखाई है लेकिन सच्चाई है कि राज्यों ने इस यात्रा की कमान संभाल ली है। अभी जिन लोगों से मैंने बातें की, उनके संवाद से मुझे लगा कि देश का जनमन इससे बहुत उत्साहित है। जहां यात्रा खत्म होती है, वहां से दूसरे गांव के लोग इसकी अगुवाई करने लगते हैं। लोगों में इसके स्वागत की प्रतिस्पर्धा है।

नये-नये तरीकों से लोग स्वागत कर रहे हैं। लोग सेल्फी ले रहे हैं। नमो एप को डाउनलोड कर रहे हैं और विकसित भारत के एंबेसडर बन रहे हैं। लोग प्रतियोगिताओं के माध्यम से न केवल पुरस्कार जीत रहे हैं, अपितु नई जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

दानी गर्ल्स स्कूल से जुड़ा मार्ग खोलने के दिए निर्देश

रायपुर। राजधानी के चांदनी चौक से बूढ़ा तालाब मार्ग बंद है, जिसे फिर से खोला जाएगा. इसके लिए विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कलेक्टर को निर्देश दिए हैं. बृजमोहन ने कलेक्टर के साथ बूढ़ा तालाब परिसर का भ्रमण किया. इस दौरान उन्होंने कहा, ये देश में एक मात्र अजूबा है. नई रोड बनाने की बजाय पुरानी रोड को बंद कर दी गई. 10,000 बच्चे दानी स्कूल, हॉस्टल कालीबाड़ी के बच्चे इस रोड से अपने घर जाते थे. इसके लिए इस रोड को चालू करने की मांग लंबे समय से कर रहे थे. कलेक्टर और संबंधित अधिकारों को इस रोड को फिर से चालू करने के निर्देश दिए गए हैं. विधायक बृजमोहन ने कहा, दानी स्कूल, डिग्री गर्ल्स स्कूल, चांदनी चौक की तरफ बंद गेट को खोला जाएगा. बैरिकेड लगाकर ओपन किया जाएगा, बाकी एरिया में डेवलपमेंट करना है. डिग्री गर्ल्स कॉलेज के दीवार से लगा हुआ चौपाटी नहीं बनाई जाएगी, जो बनाएंगे वह पीछे बनाया जाए. 15 दिन के अंदर यह सड़क चालू हो जाना चाहिए. स्मार्ट सिटी के साथ बैठकर समीक्षा करेंगे. वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने अधिकारियों, सचिवों को निर्देश देते हुए कहा, गरीब आवास जितना जरूरत है उतना बन सकता है, लेकिन यहां मकान रुक गया है. आज अधिकारी सेक्रेटरी सब बैठे हैं. आप सब मोदी जी की योजनाओं को देखिए. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सभी योजनाओं का लाभ गरीबों को पहुंचाएं. जितने भी गुंडा बदमाश हैं.

चलती मालगाड़ी के चार पहिये पटरी से नीचे उतरे, 800 मीटर तक चलती रही गाड़ी

कोरबा। कुचेना के पास घटना चलती मालगाड़ी के एक डिब्बे के चार पहिये पटरी से नीचे उतर गए। पहिये उतरने के बाद भी मालगाड़ी 800 मीटर तक चलती रही। इस दौरान पटरी का एक बड़ा हिस्सा डैमेज हो गया और डिब्बे भी अलग-अलग हो गए। मालगाड़ी एसईसीएल. जूनाडीह साइडिंग से कोयला लोडकर कोरबा की ओर जा रही थी। इस घटना के बाद कोयला परिवहन भी प्रभावित हुआ। इस घटना के बाद हड़कप मच गया और इसकी सूचना रेलवे और एसईसीएल प्रबंधन को दी गई। जहां अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी ली। कोरबा आरपीएफ थाना प्रभारी आर एस चंद्रा ने बताया कि मामला जूनाडिह एसईसीएल प्राइवेट साइडिंग की है, जहां कुचेना के पास घटना घटी है। पीछे का चारों पहिया डिरेलमेंट एवं पीछे का सभी 10 वैगन पार्ट होकर अलग होना पाया गया। घटनास्थल पर पहुंची और रिरेलमेंट का कार्य शुरू किया। घटनास्थल पर क्षेत्रीय रेल प्रबंधक कोरबा, एईएन चांपा, वरि.अनु.अभि.(कैरेज एवं वॉगन) कोरबा, सीएसएम जूनाडिह, वरि.अनु.अभि.(रेलपथ) कोरबा एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कुलदीप कुमार, निरीक्षक रेसुब पोस्ट चांपा घटनास्थल पर पहुंचे। इस घटना में कोई भी अपराधीक हस्तक्षेप का होना नहीं पाया गया। मामला जूनाडिह एसईसीएल प्राइवेट साइडिंग की है, जिसकी देखरेख एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी एसईसीएल साईडिंग प्रबंधन की है।

कुर्सी की लड़ाई में जनता को भूल गए, बारी आने पर जनता कांग्रेस को भूल गई

रायपुर। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक का बड़ा बयान आया है। कांग्रेस के पूर्व विधायकों और मंत्री को नोटिस के मामले में कौशिक ने कहा कि दो खेमा शुरू से ही दिखाई दे रहा था और दोनों खेमे के लोग आज आमने-सामने दिखाई दे रहे हैं। उनके लोग इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और उनके लोग इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। पांच साल किया क्या है, कुर्सी की लड़ाई लड़ते रहे हैं और कुर्सी की लड़ाई में इतने मस्त हैं कि जनता को भूल गए और जब जनता की बारी आई तो वह कांग्रेस को भूल गई। सत्ता के दबाव में लोग चुप रहे, अंतर्कलह पहले से उजागर हो गई थी। विधायकों, संगठन, मंत्रियों और मुख्यमंत्री में जो समन्वय होना चाहिए उसका अभाव शुरू से रहा और खुलकर आरोप भी विधायक लोग मंत्री पर लगाते रहे। इतने में ही कांग्रेस के मुखिया को समझ जाना चाहिए कि कांग्रेस के अंदर में जो अंतर्कलह है वो कांग्रेस को खा जाएगी, लेकिन सत्ता के नशे में यह लोग इनको अंकुश लगाते रहे और जैसे ही सत्ता गई विस्फोट हुआ है। दो बार कांग्रेस की सरकार बनी और दोनों बार कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि जो जनता की अपेक्षाएं हैं उससे यह सरकार काफी दूर रही और इसी कारण से यह सरकार गई है और अब आपस में ये सिर फुटव्वल कर रहे हैं।

भूपेश बघेल से अब कांग्रेस पार्टी करने लगी है किनारा

रायपुर. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और विधायक केदार कश्यप ने कांग्रेस पर तंज कसा है. केदार कश्यप ने कहा, कांग्रेस पार्टी को भूपेश बघेल पर अब भरोसा नहीं रहा, जो उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चरणदास महंत को विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष बनाया है. कांग्रेस सरकार में वनमैन शो का काम करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से अब कांग्रेस पार्टी किनारा करने लगी है, जिसका ताजा उदाहरण सबके सामने है. आगे उन्होंने कहा, 15 वर्षों से सत्ता से दूर रही कांग्रेस पार्टी को 2018 में जनता ने जो जनादेश दिया था. उसे जनादेश का कांग्रेस पार्टी ने जरा भी सम्मान नहीं किया. कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इन 5 वर्षों में भ्रष्टाचार के नए-नए कीर्तिमान बनाए थे. भूपेश है तो भरोसा है का नारा देने वाली कांग्रेस पार्टी में अब भूपेश बघेल पर जरा भी भरोसा नहीं है.विधायक केदार कश्यप ने यह भी कहा कि, कांग्रेस पार्टी शुरू से ही अपनी अंदरूनी कलह से जूझती रही. उनके सरकार के मंत्री ही भूपेश बघेल पर भरोसा नहीं करते थे. कांग्रेस पार्टी जान गई थी कि, भूपेश बघेल की नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा है. भ्रष्टाचार और लूट चारों तरफ हुई है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी ने भूपेश बघेल पर जरा भी भरोसा नहीं जताया. परिणामस्वरूप कांग्रेस के आलाकमान ने भूपेश बघेल को दरकिनार करते हुए अपने वरिष्ठ नेता चरणदास महंत को विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष बनाया है.

महतारी वंदन योजना के लिए किसी को कोई भुगतान ना करें महिलाएं: जयंती पटेल

रायपुर। भारतीय जानत पार्टी छत्तीसगढ़ ने चुनाव पूर्व अपने घोषणा पत्र में प्रदेश की महिलाओ के लिए एक बेहद महती योजना की घोषणा की थी जिसका नाम है महतारी वंदन योजना चुनाव नतीजे भाजपा के पक्ष में आने और मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के पश्चात से ही इस महती योजना को लागू करने की कवायद जोरो शोरो से शुरू हो गई है और साथ ही शुरू हो चुका है इसमें धोखाधड़ी और अवैध उगाही करने वाले जलसाजो का खेल ऐसी ही एक घटना आज रमण मंदिर वार्ड में घटित हुई है जहां कुछ लोग महतारी वंदन योजना के फार्म 2? में और उसके अतिरिक्त 50 प्रति महिला के हिसाब से अवैध वसूली की जा रही थी जिसकी सूचना स्थानीय पार्षद सूर्यकांत राठौड को लगी और उन्होंने त्वरित संज्ञान लेते हुए इसकी सूचना जिला भाजपा अध्यक्ष जयंती भाई पटेल को दी और थाने में भी इसकी सूचना दी गई। इस विषय पर जिला भाजपा अध्यक्ष जयंती पटेल ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा की इस विषय पर गंभीरता से कार्यवाही की आवश्यकता है हम प्रशासन से आग्रह करते हैं की ऐसे किसी भी संदिग्ध पर त्वरित कड़ी कार्यवाही की जाए एवं मीडिया के माध्यम से मैं रायपुर शहर और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को इस विषय पर जागरूकता से कार्य करने का निवेदन किया है एवं ऐसे किसी भी प्रकार के फर्जीवाड़ा करने वाले की जानकारी त्वरित नजदीकी थाने में देने का निवेदन किया है।

कांग्रेस आलाकमान से मिलने पहुंचे पार्टी से निष्कासित पूर्व विधायक, कुछ नेताओं के खिलाफ की शिकायत

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी के नेता एक दूसरे के ऊपर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। वहीं पार्टी से निष्कासित किए गए पूर्व विधायक दिल्ली पहुंचकर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के सी वेणुगोपाल से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश में हार को लेकर चर्चा की। इसके साथ ही पार्टी के नेताओं की शिकायत भी की।

कांग्रेस पार्टी से निष्कासित हुए पूर्व विधायक विनय जयसवाल ने दिल्ली पहुंचकर जिम्मेदार नेताओं की शिकायत वेणुगोपाल से की। दिल्ली जाने से पहले विनय जायसवाल के घर में सभी टिकट काटे गए विधायकों की बैठक हुई। इस बैठक को गोपनीय रखा गया था। सूत्रों के अनुसार, बैठक में चुनावी हार को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ ही जिम्मेदार नेताओं पर चर्चा की। इसके बाद वे दिल्ली पहुंचे। कांग्रेस पूर्व विधायक विनय जयसवाल ने बताया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के सी वेणुगोपाल से मुलाकात कर हमने अपनी बात रख दी है। इस दौरान उन्होंने जिन 22 नेताओं की टिकट कटी थी, उनसे मुलाकात करने की बात कही है। इसके साथ ही टिकट काटे गए विधायकों से एक-एक कर चर्चा करने की बात कही है। बता दें कि कांग्रेस के दो पूर्व विधायक को पार्टी से निष्कासित का दिया गया है। पूर्व विधायक विनय जयसवाल और बृहस्पत सिंह को 6 साल के लिए पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया है। इसके साथ ही पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को भी पार्टी कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये सभी पार्टी के खिलाफ बयान-बाजी कर रहे थे।

तत्काल बैठक कर हार की समीक्षा करें-चंद्रशेखर

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी में बवाल जारी है। अबकी बार पीसीसी महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला ने लेटर बम फोड़ दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि, कांग्रेस पर दलालों और वामपंथियों का कब्जा हो गया है। श्री शुक्ला ने प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को चिट्ठी लिखकर हार पर बैठक के नाम पर दिल्ली में लीपापोती का आरोप लगाया है।

नारायणपुर के किसान हीरू बढ़ई की आत्महत्या के लिये भाजपा सरकार जिम्मेदार: बैज

रायपुर। नारायणपुर के कुकड़ाझोर गांव के एक किसान के द्वारा कर्ज बोझ के कारण की गयी आत्महत्या दुखद और गंभीर हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा की असंवेदनशीलता और वायदाखिलाफी ने एक किसान को आत्महत्या करने को मजबूर कर दिया। यदि भाजपा सरकार ने पहली केबिनेट में 2 लाख तक कर्जा माफ कर दिया होता किसान को आत्महत्या नहीं करना पड़ता। किसान हीरू बढ़ई के ऊपर 1.24 लाख का कर्ज था उसको कर्ज माफी का भरोसा था। उसके पुत्र की भी शादी थी। कर्ज वसूली के नोटिस से वह मानसिक दबाव में आ गये थे। मृतक किसान के बेटे ने भी कहा कि भाजपा के लोग चुनाव प्रचार के दौरान 2 लाख रू. कर्ज माफ करने की बात कहकर गये थे। सरकार के कर्जमाफी के निर्णय नहीं लेने से वह व्यथित थे।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा के अनेकों नेताओं ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान किसानों के कर्जमाफी करने का वायदा अपने भाषणों में किया था, इस संबंध में पाम्पलेट भी वितरित किया गया था। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का चुनाव प्रचार का वीडियों भी सोशल मीडिया में वायरल है। जिसमें वे 2 लाख कर्जमाफी का वायदा कर रहे है। उन्होंने चुनाव के दौरान प्रदेश की जनता से अनेक जगह सभाओं में वादा किया है, कि

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.